

LOK SABHA DEBATES

(Ninth Session)



पार्लियामेंट ऑफ इंडिया

4(7) 3
6 12 8

(Vol. II contains Nos. 11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

Price : Rs. 1. 00

CONTENTS

No. 20—Saturday, December 13, 1969/Agrahayana 22, 1891 (Saka)

	COLUMNS
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 541 to 570 ..	1—25
Unstarred Questions Nos. 3601, 3602, 3604 to 3636, 3639 to 3643, 3645 to 3707, 3709 to 3722, 3724 to 3729, 3731 to 3768 and 3770 to 3800.	25—174
Papers Laid on the Table ..	175—77
Rules Committee—	
Minutes	177
Committee on Government Assurances—	
(i) Seventh Reports	177—178
(ii) Evidence	178
Business of the House	178—96
Re. Introduction of Indian Tariff (Amendment) Bill	196—97
Bihar Lands Reforms Laws (Regulating Mines and Minerals) Validation Bill—	
Motion to consider ..	197—217, 219—38
Shri Jagannath Rao ..	197—98
Shri P. G. Sen	199—201
Shri Ranga	201—04
Shri Brij Bhushan Lal ..	205—07
Shri Shiva Chandra Jha ..	207—11
Shri Jaipal Singh ..	211—12
Shri K. N. Tiwary ..	212—15
Shri Yashwant Singh Kushwah	215—16
Shri Himat Singka ..	219—20
Shri Bhogindra Jha ..	221—26
Shri Satya Narain Singh ..	226—28
Clauses 2 and 1	238
Motion to pass ..	238
Motion Re. Contempt of House by some Visitors	228—29
Adjournment of the House.	217—19

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

LOK SABHA

Saturday, December 13, 1969/Agrahayana
22, 1891 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रांची क्षेत्र में आदिवासियों तथा गैर-आदि-
वासियों के बीच झगड़ा

* 541. श्री शशि भूषण : क्या गृह-
कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार
पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर
दिलाया गया है कि रांची क्षेत्र में आदि-
वासियों की भूमि पर गैर-आदिवासियों
द्वारा गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिये
जाने के कारण आदिवासियों तथा गैर-
आदिवासियों में गम्भीर झगड़ा हो जाने
की आशंका है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस
तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि छोटा
नागपुर सेवा दल के पदाधिकारी आदिवासियों
का शोषण कर रहे हैं तथा गैर कानूनी
कार्यों से उनको तंग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में
केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा
सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही
करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव
चव्हाण) : (क) से (ग). सरकार को

मालूम है कि "छोटा नागपुर सेवा दल" से
ज्ञात एक संस्था का अभी हाल ही में गठन
किया गया है। इस संस्था की कोई उल्ले-
खनीय गतिविधि ध्यान में नहीं आई है।

सरकार आदिवासी क्षेत्रों की सामाजिक
व आर्थिक समस्याओं से परिचित है और
उनके समाधान के लिए प्राथमिकता के
आधार पर उचित कदम उठा रही है।

हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा
उप-कुलपतियों का सम्मेलन

* 542. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही
में चंडीगढ़ में हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षा
मंत्रियों तथा उप-कुलपतियों की बैठक में
यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 1973
तक सभी स्तरों पर हिन्दी की शिक्षा का
माध्यम बना दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो, इस उद्देश्य
के लिए इतना अधिक समय निर्धारित किये
जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व-
विद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों के
कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आयोग को
पुनर्गठित करने के बारे में सरकार के
विचाराधीन कोई प्रस्ताव है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सम्भवतः, माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति की बैठक से है, जिसकी 7 नवम्बर, 1969 को चण्डीगढ़ में बैठक हुई थी। इस समिति ने, 1 और 2 फरवरी, 1968 को वाराणसी में हुए हिन्दी भाषी राज्यों के कुलपतियों के सम्मेलन की पिछली इस सिफारिश को दोहराया था कि मेडिसिन, इंजीनियरी और कृषि सहित सभी संकायों में अधिकतम जुलाई, 1973 तक हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(ख) चार वर्ष की अवधि इसलिये ध्यान में रखी गई है, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि उत समय तक प्रत्येक भाषा में सभी स्तरों पर हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। कुछ स्तरों तक पुस्तकें जुलाई 1970 और जुलाई 1971 तक तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

DEMONSTRATION BY ALL INDIA STUDENTS FEDERATION AND ALL INDIA YOUTH FEDERATION

*543. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether any demonstration was held on the 17th November, 1969 by the All India Students Federation and the All-India Youth Federation near Parliament House;

(b) whether any memorandum demanding unemployment compensation, a ban on retrenchment and automation, voting rights at 18 and distribution of arable fallow land among landless peasants was submitted to the Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—2341/69.]

COMMITTEE TO DEAL WITH APPOINTMENTS/ COMPLAINTS IN LABORATORIES UNDER C.S.I.R.

*544. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether any Committee had been set up to deal with UPSC's appointments and complaints in Laboratories under the supervision of the Council of Scientific and Industrial Research;

(b) if so, the recommendations made by the Committee; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) U.P.S.C. does not deal with appointments and complaints in the Laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research. Therefore, no committee has been set up to deal with them.

(b) and (c). Do not arise.

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद

*545. श्री रामसेवक यादव :

श्री मधु लिमये :

श्री अनेश्वर मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद के सम्बन्ध में त्रिवेदी आयोग के प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि उसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रतिवेदन को

कार्यान्वित करने में देरी होने के कारण उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र बलिया जिले के नरही गांव में तेरह व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार को पहले ही मालूम था कि बिहार सरकार, जहां राष्ट्रपति का शासन है तथा उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सीमा विवाद को बनाये रखना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रश्न के बारे में केन्द्रीय सरकार कहां तक सक्रिय है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री त्रिवेदी की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए मई, 1968 में संसद द्वारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया तदुपरांत नियत सीमा का निर्धारण, जैसा अधिनियम में कहा गया था, किया गया। राज्य सरकार ने, जिसे सीमा स्थम्बों को गाड़ना था, अधिकांश काम पूरा कर लिया था तथा भारत सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके सुझाव दिया था कि अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रों के हस्तान्तरण को 1 अक्टूबर, 1969 से कार्यरूप दिया जायेगा। किन्तु, तब तक अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में कुछ लेख्य याचिकायें दायर की गईं। इन याचिकाओं की पटना उच्च-न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा 24 से 28 नवम्बर, 1969 तक सुनवाई की गई तथा 12 दिसम्बर, 1969 को उम उच्च-न्यायालय में सुनवाई पुनः आरम्भ होगी। अधिनियम के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए इन लेख्य याचिकाओं पर उच्च-न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार निःसंदेह गंगा नदी के बिहार की ओर स्थित एक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घी थी।

(ग) और (घ). श्री त्रिवेदी की सिफारिशों दोनों राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और जैसा ऊपर बतलाया गया है, इन सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए कानून अधिनियमित किया गया था। जहां तक भारत सरकार को जानकारी है, दोनों राज्य सरकारें इस सीमा-विवाद को यथा-शीघ्र समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं।

DEMAND FOR CESSION OF KASHMIR FROM INDIAN UNION BY PLEBISCITE FRONT

*546. SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI BRIJ BHUSHAN LAL :
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI JAGANNATH RAO
JOSHI :
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Plebiscite Front has been working for the support of such demands as cession of Kashmir from the Indian Union;

(b) whether such acts are treated as criminal offences under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (c). The Plebiscite Front has been demanding the right of self-determination for the people of Jammu and Kashmir State. No action has been considered necessary so far against the organisation.

PROMOTION OF INTERNAL TOURISM

*547. SHRI J. M. BISWAS :
SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI VASUDEVAN NAIR :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that promotion of internal tourism has not been given proper attention by Government;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have worked out any plan to promote internal tourism during the Fourth Plan; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The importance of promoting domestic tourism is fully recognised by Government and within the limits of available resources, efforts are made to provide facilities for domestic tourists. In addition, all the facilities available for foreign tourists are available for domestic tourists also.

(c) and (d). We are planning to construct a chain of youth hostels for which a sum of Rs. 25 lakhs is provided in the Fourth Plan. Also, a proposal to extend the benefit of the Hotel Development Loan Fund Scheme to 1 and 2 star hotels at key tourist centres is being processed.

COMMITTEE RE: WORKING OF MUSEUMS IN INDIA

*548. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI R. BARUA :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have appointed a Committee to go into the working of Museums in India;

(b) if so, the composition and the terms of reference of the Committee; and

(c) the time by which it would be finalising its report?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) Yes, Sir. Government have appointed a Committee to review the working of only the Central Museums, namely, the National Museum, New Delhi, the Salar Jung Museum, Hyderabad and the Indian Museum, Calcutta.

(b) The composition of the Committee is as follows :—

Chairman

(i) Dr. M. S. Randhawa.

Members

(ii) Prof. Nurul Hasan, M.P.

(iii) Dr. H. D. Sankalia.

(iv) Dr. Moti Chandra.

(v) Dr. S. T. Satyamurti.

Member-Secretary

(vi) Shri B. B. Lal.

The terms of reference of the Committee are :—

(i) to review the working of the three Central Museums and to make recommendations for their improved functioning and in particular to suggest measures for improving the security arrangements in the museums; and

(ii) to review the existing security arrangements of the protected archaeological monuments and sites and to recommend measures for strengthening them.

(c) Government have not prescribed any time limit for the Committee to submit its report. The Committee, has, however, been asked to submit its report as early as possible.

PROGRESS MADE IN SETTING UP OF NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI

*549. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the progress so far made in setting up the Nehru University in New Delhi;

(b) the total amount so far spent on the administrative wing of the University;

(c) by when the University will be set up; and

(d) what will be the characteristic features of the University?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): (a) and (c). The Executive Council and the Academic Advisory Committee of the University have started functioning. The University has taken over the Institute of Russian Studies as a University-maintained institution. The University was formally inaugurated on November 14, 1969 and it had its first Convocation on that day.

(b) Rs. 1,45,352 (up to 30-11-1969).

(d) The special characteristics of the University are incorporated in the provisions of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966 and its First Schedule.

चम्बल घाटी में डाकुओं का आतंक

* 550. श्री रामात्रतार शर्मा :
श्री नायू राम अहिरवार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समय से बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि चम्बल घाटी में डाकुओं के कारण आतंक फैला हुआ है और इसी कारण वहां पर कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, परन्तु डाकुओं के आतंक को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन डाकुओं से बरामद हुए शस्त्रास्त्रों में भारतीय सेना के तथा पाकिस्तान में निर्मित हथियार पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें चम्बल घाटी क्षेत्रों में डाकुओं की गतिविधियों को हमारे ध्यान में लाई है। इन राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें होती हैं जिनमें डाकुओं से आतंकित क्षेत्रों में समन्वित रूप से पुलिस तैनात करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इन बैठकों में केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया है।

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इन डाकुओं से बरामद कुछ हथियार और गोला-बारूद में भारतीय सेना के और पाकिस्तान में बने हथियार शामिल थे। ऐसे मामले में राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयुक्त जांच-पड़ताल की जाती है।

DISPLAYING OF PORTRAITS OF NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE IN NEHRU MUSEUM, NEW DELHI

* 551. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although photos and portraits of most of the national leaders have been kept for display in the Nehru Museum in New Delhi along with the portraits of Shri Jawaharlal Nehru, the photo or portrait of Netaji Subhas Chandra Bose has been excluded;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Netaji's photo, along with that of Shri Nehru particularly, will be displayed in the Nehru Museum ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

INCREASE BY U.K. GOVERNMENT IN TUITION FEES FOR OVERSEAS STUDENTS

*552. SHRI K. HALDER :

SHRI BADRUDDUJA :

SHRI B. K. MODAK :

SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the steps taken by Government when the U.K. Government abnormally increased tuition fees for the overseas students;

(b) whether this step of the U.K. Government is considered by a section of the population of glaring discrimination or racial grounds; and

(c) if so, what action, if any, is being taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) The Government of India considered the matter and came to the conclusion that the increase in fees was entirely a domestic problem of the British Government and British Universities and, therefore, no action was thought necessary.

(b) U.K. Government's action cannot be regarded as being discriminatory on racial grounds, as all foreign students in the U.K., including those from Australia, Canada, New Zealand, Germany, Greece,

Norway, South Africa, U.S.A. etc. are affected by it.

(c) Does not arise.

INCREASE IN THE MANUFACTURE OF EXPLOSIVES IN VARIOUS STATES

*553. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large scale manufacture of bombs and other explosives has increased considerably in various States like West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh etc;

(b) whether Government's measure to check the increase in the manufacture of such materials are ineffective and the lawlessness in the country is growing in alarming strength; and

(c) if so, the reasons therefor and whether Government would take new measures in this respect and the details of those measures proposed, if any ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). A statement giving the information received from the Governments of Gujarat, Harayana, Orissa, Punjab, Rajasthan and Nagaland is laid on the Table of the House.

Information from the remaining States is awaited and will be laid on the Table of House, on receipt.

Statement

Name of State	(a) whether large scale manufacture of bombs has increased considerably in States	(b) whether measures to curb this are ineffective and lawlessness is growing	(c) Reasons therefor and details of new measures proposed
Gujarat	No	No.	Does not arise.
Haryana	No.	No.	Does not arise.
Orissa	No.	Does not arise.	Does not arise.
Punjab	No.	Does not arise.	Does not arise.
Rajasthan	No.	Does not arise.	Does not arise.
Nagaland	No.	Does not arise.	Does not arise.

ATTEMPT TO INTIMIDATE SHRI HARI KRISHAN, M.P.

*554. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Hari Krishan, M.P. has complained to him that there have been persistent attempts to intimidate him; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The complaint is being inquired into.

COMPULSORY MILITARY TRAINING TO COLLEGE STUDENTS

*555. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government are considering the proposal for providing compulsory military training to every College student in the country; if not, the reasons therefor; and

(b) the details of the scheme for providing military training to the students at present ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the house. [*Placed in Library. See No. LT-2342/69*]

FARE-RAISE BY I.A.C. AND AIR-INDIA

*556. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Airlines is considering fare-raise and have sought Government's sanction for the internal flights;

(b) whether it is also a fact that Air India flights from U.K. to India will now enjoy a bonus of 30 per cent; and

(c) if so, in what way the revenue position of Indian Airlines Corporation and the Air India will be affected by the fare-raise and fare-cut respectively and how will it affect the passenger flow ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Indian Airlines' passenger fares were increased with effect from 1st November 1969, by 8% on the trunk routes and 7% on all other routes excepting those in Assam Region where the increase was limited to 5%.

(b) The Government of India have approved in principle a Travel Promotion Scheme whereby persons of Indian ethnic origin, resident in U.K., will be able to obtain from Government a bonus of approximately 37% of the applicable fare from Pakistan to Bombay, when they travel on the services of Air India/BOAC.

(c) The increase in Indian Airlines' passenger fares will yield about Rs. 110 lakhs during the current year (1969-70) and about Rs. 250 lakhs during 1970-71. It is not expected to affect the flow of traffic adversely.

It is anticipated that the number of passengers travelling by Air India on the sector London-Bombay will substantially increase. The additional revenue to Air India is estimated at Rs. 1.29 crores during the first year, gradually rising to Rs. 1.57 crores in the fifth year of the scheme's operation.

DEVELOPMENT OF GOVIND SAGAR AS A PLACE OF TOURIST INTEREST

*557. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether he visited the Bilaspur District of Himachal Pradesh and had discussions with the local officials and took some decisions on the development of Govind Sagar;

(b) if so, what are the details of the proposals and the decision as also the action taken on them; and

(c) in case Government propose to develop Govind Sagar area as a tourist attraction, what are the details of such a scheme and how much money is being set aside for its implementation during the year 1970-71 ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). It was decided to set up a Transport Unit at Chandigarh, run the Cafeteria at Bhakra Dam, provide motor launches for use in the Govind Sagar and to make a survey to find out what other tourist facilities like fishing, water sports, etc. could be provided in Govind Sagar. Action to implement these decisions is being taken. A sum of Rs. 10 lakhs has been provided for the development of Govind Sagar during the Fourth Five Year Plan period.

PAK DAY CELEBRATED IN SRINAGAR ON 14-8-1969

*558. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Day was publicly celebrated in Srinagar on 14th August, 1969, when Pakistan Flag was ceremonially hoisted and Pakistan Zindabad slogans were raised in the presence of thousands of people including Police; and

(b) if so, what action has been taken against those responsible for this anti-national activity and to prevent such occurrences in future ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). Government of Jammu and Kashmir have intimated that on 14th August, 1969 some students of a local college in Srinagar fired a few crackers and raised anti-national slogans and held up a green piece of cloth as flag. This was not a Pakistani flag. The police took prompt action and a few persons were taken into custody.

भारत-तिब्बत सीमा पर बसे हुए सीमा सुरक्षा दल के सैनिक

*559. श्री महाराज सिंह भारती : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-तिब्बत सीमा पर जो सीमा-सुरक्षा दल के सैनिक तैनात हैं उनमें सीमा पर बसे भारतीयों की संख्या कितने प्रतिशत है; और

(ख) दुर्गम स्थानों में रहने के अभ्यस्त होने के नाते उक्त नागरिकों की प्रतिशतता बढ़ाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सीमा सुरक्षा दल के किन्हीं सैनिकों के भारत तिब्बत सीमा पर बस जाने की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में विदेशी घर्म प्रचारक

*560. श्री कंबरलाल गुप्त :

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

श्री राम सिंह अयरवाल :

श्री क० अनिरुद्धन :

क्या गृह-कार्य मंत्री 8 अगस्त, 1969 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी घर्म प्रचारकों के नाम और पते क्या हैं जिन के विरुद्ध सरकार को गत तीन वर्षों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा जिनका गतिविधियों को सरकार द्वारा सदेहपूर्ण पाया गया है;

(ख) उन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का व्यौरा क्या है तथा सरकार ने किन-किन

विदेशी धर्म प्रचारकों के विरुद्ध कार्यवाही की है ;

(ग) गत तीन वर्षों में विदेशी धर्म प्रचारकों को विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ; और

(घ) उन विदेशी धर्म प्रचारकों तथा चर्चों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में विदेशों से 10,000 रुपये अथवा इससे अधिक सहायता प्राप्त हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। (प्रणालय में रख दिया गया (देखिये संख्या LT-2343/69)

(ग) और (घ) ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अनुसार धर्म प्रचारक संस्थानों इत्यादि को प्राप्त आय तथा किये गये व्यय का लेखा-जोखा उनके द्वारा रखा जाना तथा संवीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो। तथापि, 1965 से 1967 तक की सूचना, जिसे एकत्रित करना सम्भव हुआ है, 9 अगस्त, 1968 को अतारंकित प्रश्न संख्या 3206 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में सदन के पटल पर रखे जाने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है।

इस सम्बन्ध में पिछले आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग के सामान्य प्रश्न के बारे में 14 मई, 1969 को इस सदन में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। सामान्य व्यावसायिक लेन-देन के अलावा विदेशी संगठनों, अभिकरणों अथवा व्यक्तियों से धन प्राप्त करने पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार का एक व्यापक विधान बनाने का विचार है।

MAO POSTERS IN INDIA

*561. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mao posters have appeared in certain parts of India, even on the birth-day of Gandhiji; and

(b) if so, what steps Government have taken to see that Indian democracy is not taken advantage of, to encourage treason in the country ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). According to information received from the Government of Mysore, on October 4, 1969 manuscript wall posters in English, containing revolutionary communist propaganda slogans and salutations to Mao etc.. were found pasted on the walls of General Post Office, the bus shelters opposite the Central Telegraph Office and near the Income Tax Office in Bangalore. The State Government are keeping a close watch on the activities of certain extremist elements, who are suspected to be responsible for exhibiting these wall posters. No such posters have come to notice in Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Nagaland, Punjab, Andamans and Nicobar Islands, Chandigarh, Goa, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Laccadive, Minicoy & Amindive Islands and Manipur. Information from the remaining States is awaited.

एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की सप्लाई के लिये दिये गये क्रयादेशों में परिवर्तन

* 562. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की सप्लाई के लिये दिये गये क्रयादेशों में अब परिवर्तन किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन विमानों के लिये अब क्रयादेश दिये जा रहे हैं, वे अधिक कीमत के हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरा व्यौरा क्या है तथा पहले दिये गये क्रयादेशों में परिवर्तन करने के क्या कारण ह ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : एयर इंडिया ने तीन बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमानों को खरीदने के आर्डर दिये हैं। प्रारम्भ में पहले दो विमानों के लिए मूल (बेसिक) 747 का, और तीसरे विमान के लिए 747-बी का, जोकि मूल का उन्नत रूप है, आर्डर दिया गया था। अब एयर इंडिया ने पहले आर्डर को बदल कर प्रथम दो विमानों के लिये भी उन्नत रूप अर्थात् 747-बी का—जिसका परास (रेंज) लगभग 800 नावीय (नाटिकल) मील अधिक तथा भारवहन क्षमता (पे लोड कर्पासिटी) 15,000 पौण्ड तक अधिक है—आर्डर दे दिया है। मूल्य में वृद्धि प्रति विमान 9,18,000 डालर है।

CIRCULAR ISSUED BY STAFF OF ALIGARH
MUSLIM UNIVERSITY ON AHMEDABAD
RIOTS

*563. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of the Political Correspondent of "The Statesman" published in that paper on the 10th October, 1969, wherein he says that the "intemperate language of a circular issued by the teaching and non-teaching staff of the Aligarh Muslim University on the Ahmedabad riots is eye opening".

(b) if so, whether a copy of the said Circular would be laid on the Table; and

(c) if the language used in the circular is intemperate, what action has been taken against its authors ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The circular is being examined by the state government.

MALPRACTICES IN UNIVERSITY EXAMINATIONS
IN BIHAR

*564. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a report in the Hindu of the 8th November, 1969 under the caption, "Shocking Malpractices in University Exams.", which quoted several instances of malpractices in University Examinations in Bihar;

(b) whether it is a fact that in one instance Police protection was denied to a Higher Secondary Girls' School because the School authorities refused to accommodate malpractices in an examination by wards of Police Officers; and

(c) whether Government propose to take stern steps to eliminate malpractices in examinations in future and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(c) Suitable measures will have to be taken by the Universities in consultation with the University Grants Commission. To the extent that the Central Government can help in this matter, they will also do so.

DECISION ON THE RECOMMENDATIONS MADE
BY TATA COMMITTEE ON INTERNATIONAL
AIRPORTS

*565. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have since examined the recommendations of the International Airports Committee which was headed by Shri J. R. D. Tata;

(b) if so, the decisions taken thereon; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the time by which the decisions are likely to be taken ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). The recommendations of the International Airports Committee cover (a) interim modifications to the existing terminal buildings at the four International Airports and (b) long term development programmes at a cost of Rs. 106.12 crores. Government's approval to the works relating to interim modifications at a cost of Rs. 265 lakhs, has been issued. As regards the long-term programme, a sum of Rs. 50.45 crores has been included in the Fourth Plan for the purpose. Sanction for long-term works amounting to Rs. 333 lakhs has been issued so far, and the other recommendations are being processed. Government have also accepted, in principle, the recommendations of the Committee for setting up an autonomous corporation for the management of the four International Airports, and the question of bringing in legislation for this purpose is under consideration.

SCIENTIFIC METHOD OF TEACHING HINDI

*566. SHRI N. R. LASKAR : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is fact that he has suggested a need for evolving a scientific method to teach Hindi whereby a person may be able to learn Hindi language in a period of about six months;

(b) whether he has also stated that people can learn Russian language, within this period;

(c) if so, how far this is practicable;

(d) whether the suggestion has been examined by experts; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) Yes, Sir, the Education Minister suggested that Courses of instruction and Method of teaching should be so frame such as will enable the learning of basic Hindi in about six to eight months time.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e). The Kendriya Hindi Shikshan Sansthan at Agra, which is engaged in carrying out research in the methodology of teaching Hindi is in consultation with the Central Institute of Indian Languages finalising a scheme which envisages the possibility of evolving a method of intensive teaching of Hindi language so that working knowledge of the language may be acquired by the learner within a short period. A 12-week intensive course is also being prepared by the Sansthan for Class I Officers of the Central Government which aims at giving a working knowledge of the language.

अधुगैस का प्रभाव

*567. श्री ए० सा० बारूपाल :

श्री ओंकारलाल बेरवा

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ आर्मंड फोसिज के पेथालोजी विभाग की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि अधुगैस का प्रभाव इतना अधिक खतरनाक होता है कि इससे नेत्र ज्योति तक नष्ट हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अश्रु-गैस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या-चरणशुक्ल : (क) से (घ). अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ आर्मंड फोसिज के पेयालोजी विभाग की रिपोर्ट की एक प्रति अमेरिका सरकार से प्राप्त की जा रही है। किन्तु इस देश में प्रयोग किये जाने वाले अश्रु गैस गोलों आदि में काम में लाये गये रसायनिक तत्वों की उनकी व्याधिकीय प्रभावों के लिये जांच अच्छी तरह की गई है और उन्हें मानव शरीर पर कोई स्थायी हानिकारक प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाता; नये रसायनिक तत्वों वाली किसी अश्रुगैस सामग्री को पुलिस दल को दिये जाने से पहले प्रयोगशाला में तथा खुले में कड़े परीक्षणों द्वारा जांच की जाती है।

CIVIL AVIATION DEVELOPMENT FUND

*569. SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI TENNETI :
VISWANATHAM :
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

- (a) the object behind creating and maintaining Civil Aviation Development Fund;
- (b) the total amount held by this Fund;
- (c) whether this Fund will help growth of airports in backward areas; and
- (d) whether there are any immediate plans, and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (c). I lay a statement on the Table of the House.

- (b) Rs. 1,61,88,924 as on 8-12-1969.
- (d) No, Sir.

SIMPLIFICATION/CORRECT PRONUNCIATION OF NAMES OF AIR-INDIA'S AIRCRAFTS

*568. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government will consider the desirability of simplifying the names of Air-India Aircrafts which are not many; and

(b) if not, whether the announcers on these aircrafts will be taught to pronounce the names of the aircrafts correctly ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Air-India have named their Boeing aircraft after well-known Himalayan peaks. There is no proposal to change these names.

(b) This is already being done. The Corporation have, however, issued instructions that special attention should be given to this matter.

STATEMENT

- (1) For payment of subvention to Indian Airlines for the operation of un-economic routes not otherwise justified on commercial considerations but which may be necessary to meet regional requirements or for promotion of tourism.
- (2) Payment for the construction of air strips and provision for ancillary facilities for the operation of services as referred to in (1) above which could not be fitted into the general programme of the Civil Aviation Department.
- (3) Payment of subvention on account of purchase by Indian Airlines of aircraft (manufactured in India) to replace or supplement their existing fleet.

SHIFTING OF NEHRU MUSEUM, NEW DELHI

*570. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that foreign and Indian tourists have to face a

great difficulty while visiting Nehru Museum at 1, Teen Murti Marg where there is no historical monument etc., nearby;

(b) whether it is also a fact that the situation of Samadhis of Gandhiji, Nehruji and Shastriji by the side of each other is very comfortable to visitors;

(c) if so, whether Government propose to construct one more storey over Gandhi Memorial Museum and shift Nehru Museum there so as to make it convenient for visitors and also use the spacious building of Teen Murti House for some other purposes; and

(d) if so, the details of the scheme and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) There is no such proposal.

(d) It has been decided by Government not get any response from the authorities; and Library from the Teen Murti House.

ATTEMPT TO COMMIT SUICIDE BEFORE P.M.'s RESIDENCE

3601. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item in the Hindu of 30th September, 1969, under the caption, 'Man's suicide attempt in P.M.'s residence';

(b) whether it is a fact that one Shri Selvanathan, who was involved in the above incident, had applied for protection of his life on the ground that he feared that some gangsters whose enmity he had incurred by helping the customs authorities in making a big gold haul, were after his life;

(c) whether it is also a fact that he did not get any response from the authorities; and

(d) whether the matter has been fully investigated and if so, whether a statement showing the steps taken to smash the racket and punish the guilty persons will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No such news item has come to the notice of Government. However, one Shri K. Selvanathan while waiting in the reception room of P.M.'s house on 30-9-1969 appeared to be under the influence of some drug. The Delhi Police after enquiry have registered a case under section 309 I.P.C. against him.

(b) Delhi Police has no such information.

(c) Does not arise.

(d) The case registered by Delhi Police under section 309 I.P.C. is under investigation.

REPAIRS OF RUNWAY AT KESHOD AIRPORT

3602. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5460 on the 29th August 1969 and state the details of progress made so far in repairing the runway at Keshod Airport, and the approximate time of its completion?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : An estimate for extension of the runway to 4500 feet has been sanctioned. The extension is expected to be completed in one year from the date of commencement. An estimate for carrying out repairs to the main runway is under preparation.

CORRESPONDENCE COURSES IN DELHI UNIVERSITY

3604. SHRI N. R. DEOGHARE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Correspondence Courses for Master's Degree Examination have been started by the Delhi University;

(b) if so, how many students are expected to be benefited by this course; and

(c) the name of other Universities which have started or are thinking to start Correspondence Courses for B.A. and M.A. degrees?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) No, Sir. The matter is under consideration of the Delhi University.

(b) Does not arise.

(c) The following Universities have also started Correspondence Courses :—

1. Panjabi University—Pre-University Course, B.A. Giani (Honours in Punjabi).
2. Rajasthan University—B.Com.
3. Meerut University—B.A.

The University Grants Commission has also approved a proposal of the Mysore University to introduce Correspondence Courses in B.A. and M.A. with effect from 1969-70.

AMOUNT OWED BY DR. DHARMA TEJA

3605. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the particulars of the total amount which Dr. Dharma Teja owes to the country today;

(b) particulars of the total amount recovered from him so far;

(c) the manner in which it is proposed to recover the balance and when; and

(d) the total profits made by Jayanti Shipping Corporation since it was taken over ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) The new management of Jayanti Shipping Co. has filed a number of civil suits in India as well as abroad in respect of the amounts due to them from Dr. Teja and they have already obtained two decrees, one for Rs. 15.66 lakhs plus interest from the Delhi High Court and another for Rs. 82.92 lakhs plus interest from the Bombay High Court. Two civil suits are pending in Bombay High Court involving claims of Rs. 31.04 lakhs and Rs. 115.97 lakhs. Further civil suits

may also have to be filed against Dr. Teja and legal advice is being obtained about filing of these suits. The total amount due from Dr. Teja would be known only after all these suits have been filed and decided.

(b) So far, the following amounts have been realised from Dr. Teja :—

- (i) £ 310717-5-6 from the balance of Dr. Teja's credit in the State Bank of India, London, and
- (ii) Rs. 46383.70 from the sale of his Chevrolet motor car in India.

(c) The only method open is to obtain decrees in civil suits and then to execute them by selling the shares of Dr. Teja in Jayanti Shipping Company. All these shares are already attached under the orders of the Bombay High Court. It is proposed to sell these shares in the execution of the two decrees already obtained. However, the tax Recovery Officer, Bombay, has also attached all these shares for recovering arrears of income tax from him totalling Rs. 3,23,45,139 pertaining to the assessment years 1962-63 and 1963-64. The legal position is that this claim of Income Tax authorities would take precedence and priority over the claims of Jayanti Shipping Company when the shares are sold.

(d) The company has turned the corner and is now making profits but it is not possible to indicate the amount of profit at this stage because the accounts from the date of take-over of the management of the company by the Government of India have not yet been audited.

OPINION OF A WEST GERMAN EXPERT ON HOTEL MANAGEMENT IN INDIA

3606. SHRI BABURAO PATEL :
SHRI RAGHUVIR SINGH
SHASTRI :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be please to state :

(a) whether it is a fact that Prof. Rachfal, a West German expert in hotel management and catering technology now in India studying hotel management, complained that our "Hotels are more westernized than Indian" and that there is far too much Western entertainment in our hotels;

(b) whether Prof. Rachfal has submitted his recommendations to Government;

(c) if so, what efforts are being made in this respect; and

(d) the names of foreign hotel experts invited to India during the last two years and their opinions in short of our hotel management ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). Prof. Rachfal of the Institute of Hotel Management in Heidelberg, West Germany, visited India in September 1969 and observed, in his report submitted to Government, that more of the general decor and catering for tourists should be in typical Indian style. His detailed report is due to be submitted shortly.

(d) No other hotel experts have been officially invited to India, but one is included in a United Nations team expected shortly.

COLLAPSE OF BRIDGE OVER RIVER PHALGU NEAR GAYA (BIHAR)

3607. SHRI CHANDRA SEKHAR SINGH : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of persons who died at the time of collapse of a bridge over river Phalgu, near Gaya—Manpur Highway in Bihar in the last week of November, 1969;

(b) whether any compensation for the loss of life and property is being paid to the next of their kith and kin; and

(c) if so, when and the amount of compensation being paid to each of the affected families separately ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c) : The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

42LSS/69—2

मध्य प्रदेश में नये राजपथों का निर्माण

3608. श्री गं० च० दीक्षित : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में नए राजपथ बनाने की योजना पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पुराने राजपथों की अच्छी मरम्मत नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां के राजपथों की हालत को सुधारने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर कितना धन व्यय किया जा रहा है तथा राज्यों की तुलना में इसका अनुपात क्या है ?

संसद कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अनुमानतः सदस्य

महोदय का तात्पर्य मध्य प्रदेश में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति की सड़कों में और वृद्धि करने के सवाल से है। धन की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए इस मामले की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). यथा संभव हद तक उपलब्ध धनराशि के अधीन पर्याप्त मरम्मत की जा रही है। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के सुधार के लिए चौबीस पंचवर्षीय योजना में भी व्यवस्था की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3609. श्री गं० च० दीक्षित : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय

विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब तक यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालय किन-किन राज्यों में स्थापित किए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० भार० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शिक्षा आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। अतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने के प्रस्ताव को जो विचाराधीन है, को छोड़कर, और किसी भी स्थान पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है। वर्तमान पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से दो उत्तर प्रदेश में हैं, एक पश्चिमी बंगाल में और बाकी दो दिल्ली के संघ-क्षेत्र में हैं ।

मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों पर भोजन-जलपान व्यवस्था

3610. श्री गं० च० दीक्षित : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सभी पर्यटक केन्द्रों में भोजन-जलपान की व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन पर्यटक-स्थानों पर ऐसी व्यवस्था है और किन-किन में नहीं और क्या सरकार का विचार ऐसे स्थानों पर भोजन-जलपान की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जहां तक हमारा जानकारी है मध्य प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर खान-पान के प्रबन्ध मौजूद हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत पर्यटन विकास निगम को विश्राम-गृह का कब्जा दिया जाना

3611. श्री गं० च० दीक्षित : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के या अन्य प्रकार के विश्राम-गृह भारत पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के विश्राम-गृह दिए गए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं । परन्तु, कारपोरेशन ने खजुराहो, सांची और माण्डू के तीन पर्यटक बंगलों का प्रबन्ध भारत सरकार के पर्यटन विभाग से 1 अप्रैल, 1967 से अपने हाथ में ले लिया और बाद में 1 जनवरी 1969 को इनका स्वामित्व भी कारपोरेशन को हस्तांतरित कर दिया गया ।

AGREEMENT BETWEEN MADRAS PORT TRUST AND ENGINEERS INDIA LTD. REGARDING CONSULTANCY SERVICES

3612. SHRI G. S. MISHRA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the terms of payment, special clause and duration prescribed in the Madras Port Trust and Engineers India Ltd. consultancy agreement for product loading and unloading work;

(b) whether it is a fact that the validity of the agreement has expired;

(c) if so, the reasons why the Madras Port Trust authority are still utilising the consultancy services of Engineers India, without giving them extension in the validity period;

(d) whether it is a fact that Engineers India Ltd., have asked for revision in out-of-pocket allowance from Rs. 5,000 per month to Rs. 10,000 per month;

(e) whether it is a fact that the total value of the agreement is approximately

Rs. 1,00,000 out of which Rs. 40,000 is out-of-pocket allowance; and

(f) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). The remuneration of the Consulting Engineers for the performance of the services devolving on them under the two individual contracts are as under :—

(i) For preparation and submission of project report, complete design and procurement services.	3% of the cost of works.
(ii) For expediting and fabrication inspection of indigenous equipment and materials.	1% of the cost of works.
(iii) For complete works management and construction supervision.	2% of the cost of works.

The Consulting Engineers are eligible for additional payment computed on a time basis of the payroll costs plus 100% and in addition, such expenses which may be incurred in connection therewith plus a fee of 15% on this sum, in case of alterations or modifications to design, additional work due to resumption of postponed works and additional works beyond the scope of the agreement.

The Consulting Engineers are eligible for payment of additional fee and out of pocket expenses for crude unloading facilities and product loading services and in no circumstances, shall the out of pocket expenses and additional fees calculated exceed Rs. 5,000 and Rs. 10,000 respectively in case of overstay of the Resident Engineer. The out-of-pocket expenses shall include expenses actually and properly incurred in connection with printing, purchase of drawings, telegrams, telephones, cables, travelling and hotel expenses and advertising.

The scope of the works include the basic facilities for pipeline bulk transfers of export products into tankers at Madras Port ex. Madras Refineries and import of crude oil from tankers at Madras Port and trans-

ferred to Madras Refineries at the new Oil Dock. Certain programme of works is stipulated in the contract.

The contract provides for postponement and additional fees for the overstay of the Resident Engineer. Hence the question of expiry of the validity of the agreement does not arise.

(c) The question of any extension of the validity period does not arise as the contract provides for all contingencies.

(d) Yes. M/s. Engineers India Limited had requested the Madras Port Trust for revision in the ceiling amount towards out of pocket expenses, only in respect of the contract for loading refined products as the cost of works is doubled as compared to the date of execution of contract due to increase in the quantum of work.

(e) and (f). The total value of the agreement will be finally known only when the entire work is completed and the cost of works is known as remuneration is payable on the basis of a percentage of the cost of the works. The reimbursable cost also will be known only after the entire services are rendered by the Consulting Engineers.

**AGREEMENT BETWEEN MADRAS PORT TRUST
AND ENGINEERS INDIA LTD. REGARDING
CONSULTANCY SERVICES**

3613. SHRI G. S. MISRA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the technical consultancy agreement between Engineers India Ltd. and Madras Port Trust was on flat fee basis;

(b) whether Engineers India Ltd. undertook job for additional technical consultancy services, without prior sanction of the Madras Port Trust Board, and without awaiting issue of the formal amendment in the existing consultancy agreement;

(c) whether about Rs. 1 lakh is being charged as a fee for so-called additional services by the Engineers India Ltd., on cost reimbursable basis, in terms of those clauses of the existing agreement between the two parties which do not apply in the circumstances and during the currency of the agreement;

(d) whether it is a fact that Engineers India Ltd. is charging the most of the amount of the additional consultancy services, which comprises of out-of-pocket expenses;

(e) whether it is a fact that Madras Port Trust have agreed to make the payment as asked for by Engineers India Ltd.; and

(f) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No. The technical consultancy agreement between Engineers India Ltd. and Madras Port Trust is based on fee payable on percentage basis and not on a flat fee basis.

(b) As a result of having to provide urgent temporary facilities to Madras Refineries Limited for unloading of crude and loading of refined products, the quantum of work was increased. As the provision of immediate temporary facilities was approved in principle, which were only allied to the permanent facilities and closely interlinked with the permanent facilities,

M/s. Engineers India Limited carried out the additional job. The completion of the temporary facilities was committed to a very tight schedule and was required to be done urgently. As the consulting services for the piping scheme was being rendered by M/s. Engineers India Limited, the services for these additional facilities were also carried out by M/s. Engineers India Limited within the scope of the agreement. It was at that time considered that these works would be covered on the percentage basis, within the scope of works. However M/s. Engineers India Limited preferred their claim for these services under additional services and requested payment under these clauses. As the additional services contemplated under the contract include only "Alterations, modifications, postponement or cancellations of work", necessary sanction was given to include the "additional services beyond the scope of work also" under the contract.

Even if it is considered that the additional work is a new job, the Trust would have utilised the services of M/s. Engineers India Limited only for these jobs, as they are interlinked to the pipeline work which they were already doing. However, payment was not made for this work until sanction was accorded by the Port Trust Board on 3rd October, 1969.

(c) Payment towards additional services is covered in the contracts, which is computed on a time basis of the pay roll costs plus 100% and in addition such expenses, which may be incurred in connection therewith plus a fee of 15% on this sum. This amount was paid after the Port Trust Board's sanction. Total payments towards such additional services are estimated to be of the order of Rs. 1.50 lakhs.

(d) to (f). The Madras Port Trust are making payments to Engineers India Limited strictly in terms of their contract.

**AGREEMENT BETWEEN MADRAS PORT
TRUST AND ENGINEERS INDIA LTD.**

3614. SHRI G. S. MISHRA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madras Port Trust, in their technical consultancy

agreement, appointed Engineers India Ltd. for inspecting and expediting on their behalf;

(b) whether Madras Port Trust did not make any official insertion about the position of Engineers India Ltd. as inspector expediter in the purchase orders they were placing;

(c) whether Madras Port Trust officially made Lloyd Register of Shipping, a private organisation as their inspectors;

(d) whether Madras Port Trust, while officially mentioning Lloyd Register of Shipping as their inspector, also made Engineers India Ltd. to get on with their job of inspection/expediting, without making an official amendment or clarification in the purchase orders they were placing; and

(e) if so, the reasons therefor, and loss suffered by Engineers India Limited?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT: (SHRI IQBAL SINGH): (a) Yes.

(b) Wherever inspection is involved, reference to M/s. Engineers India Limited or the Port Trust's representative, as the case may be, is provided for in the purchase orders. So far as expediting is concerned no specific mention in the purchase orders is necessary.

(c) M/s. Engineers India Limited's services include inspection and expediting and they have been carrying out the same with regard to various orders such as for valves, flanges, pumps etc. M/s. Lloyds' inspection was accepted only in respect of the Port Trust's orders for supply of quality grade pipes placed on M/s. Hindustan Steel Limited as M/s. Hindustan Steel Limited, explained difficulty in fixing up definite dates and arranging inspection with prior intimation to M/s. Engineers India Limited. M/s. Hindustan Steel Limited therefore suggested the appointment of M/s. Lloyds for inspection to facilitate in-process inspection at their plant, as M/s. Lloyds are also stationed at Rourkela all the time, as third party inspectors. M/s. Lloyds' inspection was accepted by the Port Trust under the above circumstances, only in respect of orders on M/s. Hindustan Steel

Limited, for the supply of pipe of grade quality.

(d) No. In case of Lloyds' inspection already made, the question of any further inspection by M/s. Engineers India Limited did not arise. In view of urgent need for pipes, M/s. Engineers India Limited, were deputed to expedite despatch of the pipes. In such cases, no amendment or clarification to the purchase order was considered necessary as they are only expediting on the Port Trust's behalf and no inspection was involved.

(e) The Port Trust is not aware of any loss suffered by M/s. Engineers India Limited.

RECOGNITION TO XAVIER LABOUR RELATIONS INSTITUTE, JAMSHEDPUR

3615. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) whether the Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur (Bihar) has at any time applied to the Government of India for being recognised as a University under the U.G.C. Act;

(b) if so, the stage at which this matter rests now;

(c) whether his Ministry has asked this Institute to seek affiliation from the Ranchi University, now that the latter's M.A. degree in Labour and Social Welfare had been recognised by the Government of India in 1968; and

(d) if so, whether before considering the grant of recognition as a University under the University Grants Commission Act, Government would keep in mind on merits, that this Institute should not be recognised as such, because of its policy of discrimination against its non-Catholic staff as well as students in day-to-day matters and also because this Institute is run by foreign Christian Missionaries?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Proposals for declaration of any institution as a 'deemed' University under the University Grants Commission Act, 1956 are always considered on merits and decisions taken on the basis of the advice tendered by the University Grants Commission.

ग्वालियर महाराजा की आस्तियां

3616. श्री शशि भूषण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर के महाराजा तथा उनके परिवार ने संयुक्त रूप से ग्वालियर में मुहारकर के बाड़ा की भूमि तथा भवन सिन्धिया देवस्थान न्यास को दे दिया है, हालांकि वह सम्पति ग्वालियर महाराजा की नहीं थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ग्वालियर के महाराजा या सिन्धिया देवस्थान न्यास को उक्त भूमि और भवन के स्वामित्व से वंचित करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सम्बन्धित सम्पति को सिन्धिया देवस्थान न्यास को हस्तांतरित कर दिया गया है और वे इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि क्या यह सम्पति महाराजा ग्वालियर की है अथवा नहीं ।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

3617. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों में, जिन्हें अभी तक सीमावर्ती

जिले घोषित नहीं किया गया, जैसे उत्तराखण्ड के पीड़ी, चमोली, देहरादून, टेहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और उत्तर काशी जिलों में महिलाओं के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी जिलों को सीमावर्ती जिले घोषित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन जिलों के निवासियों को इससे लाभ होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

FOREIGN QUALIFIED DOCTORS WORKING AS POOL OFFICERS UNDER C.S.I.R.

3618. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the most foreign qualified doctors are still working as Pool Officers under C.S.I.R.;

(b) if so, the reasons for not offering them jobs; and

(c) the number of such doctors working as Pool Officers and the scheme to absorb them in different posts ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) 98 Doctors with specialisation from abroad were working in the Scientists' Pool on 1st November, 1969.

(b) As far as the Pool is concerned, all the Officers in the Pool are free to apply for any regular appointment and they are asked to do so. Assistance is also provided to them in seeking employment as detailed under (c). However, all organisations in need of doctors have their own methods and procedures of recruitment.

The absorption of these Pool Officers is dependent on their selection in accordance with these procedures.

(c) 98 as indicated in part (a) above. The following measures are taken by the C.S.I.R. to assist them in finding regular employment :

- (i) The particulars of these Medical Personnel are maintained in an Unemployment Live Register in the CSIR and referred against notified vacancies.
- (ii) Their names are also published in the Technical Manpower Bulletin as persons available for employment and circulated to Universities, Medical Colleges, Industrial Organisations and other prospective employes.
- (iii) Medical Personnel with outstanding qualifications and experience are also referred to organisations who may be specially interested in such personnel for consideration.

विदेश यात्राओं को जा रहे मंत्रियों द्वारा खरीदे गये उपहार

3619. श्री कंबर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी यात्राओं पर गए किन-किन मंत्रियों ने देने के लिए उपहार खरीदे और प्रत्येक ने कितने-कितने मूल्य के उपहार खरीदे;

(ख) अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन्हें कुल कितने-कितने मूल्य के उपहार मिले;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं कि विदेश यात्रा पर जाने वाले मंत्री अधिक से अधिक कितने मूल्य का उपहार खरीद सकते हैं और कहां से प्राप्त उपहारों को किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जैसा कि सदन में पहले बताया गया है, मांगी गई सूचना देने से एक मित्त देश को दूसरे मित्त देश से तुलना करने के कारण उलझन पैदा होगी। अतः उसका विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा;

(ग) और (घ). उस उपहार के मूल्य की सीमा निर्धारण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है जो कि कोई मंत्री विदेश जाते समय सरकारी खर्च पर खरीद सकता है। मंत्रियों के लिए आचार संहिता में पहले ही यह प्रावधान है कि किसी मंत्री को निकट सम्बन्धियों अथवा न हो, तथा जो पूर्णतया अथवा पर्याप्त रूप में सरकारी है अथवा सरकार द्वारा, नियंत्रित है। यदि ऐसा है तो, किसी सदस्य द्वारा अर्ध-सरकारी पद पर धारणाधिकार को रखने के सम्बन्ध में स्थिति उपरोक्त सम्बन्धित निकाय द्वारा इस बारे में बनाए गए नियमों पर संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्भर करेगी। इसी प्रकार कोई गैर-सरकारी व्यक्ति, जो आयोग के सदस्य के पद पर अपनी नियुक्ति से पूर्व किसी गैर-सरकारी अथवा अन्य स्वशासी निकाय में कोई पद धारण करता हो, आयोग में अपनी नियुक्ति होने पर ऐसे गैर-सरकारी अथवा स्वशासी निकाय में अपने धारणाधिकार को कायम रख सकता है यदि इस सम्बन्ध में उस निकाय के नियम के तथा यदि यह संविधान के उपबन्धों के अधीन हो। आयोग के उन चार सदस्यों के धारणाधिकार, जो पहले सरकारी कर्मचारी थे, या तो सरकारी सेवा से उनकी सेवा-निवृत्ति पर अथवा आयोग में उनको नियुक्ति होने पर, जो कोई भी पहले हो, समाप्त कर दिए गए। सशस्त्र सेनाओं के एक सदस्य जो आयोग में 3-2-1968 को शामिल हुए सेना से तब तक प्रतिनियुक्ति पर रहे जब तक कि वे 16-6-1968 को सेना नियमों के अधीन बाध्यक्य निवृत्त नहीं

हो गए। जहां तक चार गैर-सरकारी सदस्यों का सम्बन्ध है, दो का उनके पिछले पदों पर कोई धारणाधिकार नहीं था, एक उस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसे वे धारण किए हुए थे, और केवल एक सदस्य का अपने पिछले पद पर धारणाधिकार कायम है।

यात्राओं के दौरान मंत्रियों को प्राप्त उपहार तथा भेंट

3620. श्री कंबर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जिन-जिन मंत्रियों को विदेशों तथा भारत में उपहार और तोहफे प्राप्त हुए हैं उनके नाम क्या हैं तथा उपहारों का ब्योरा क्या है;

(ख) मंत्रियों द्वारा कितने तोहफे तथा उपहार सरकारी कोष में जमा कराए गए तथा कितने तोहफे और उपहार उन्होंने अपने पास रखे तथा उन मंत्रियों के नाम क्या हैं;

(ग) उन मंत्रियों का नाम क्या है जिन्होंने इन उपहारों के बदले में सरकारी कोष में धन जमा किया है तथा कितना धन जमा किया गया है ; और

(घ) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने न तो उपहारों को ही सरकारी कोष में जमा किया है और न ही उनके बदले धन जमा किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उनकी ओर सरकार का कितना धन बकाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). जैसा कि सदन में अन्य अवसरों पर बताया जा चुका है कि विदेशों में अथवा भारत में आए विदेशी उच्चाधिकारियों से मंत्रियों द्वारा प्राप्त हुए उपहारों और तोहफों के बारे में

सूचना प्रकट करने से एक मित्र देश तथा दूसरे मित्र देश के बीच तुलना से उलझन पैदा होगी और इसका विवरण देना लोकहित में नहीं होगा। ऐसे उपहारों तथा तोहफों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति से मूल्यवान उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए और यह कि किसी मंत्री अथवा उसके परिवार के सदस्यों को किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके साथ उसका सरकारी व्यवहार हो कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे अनुदेश भी विद्यमान हैं कि जब किसी मंत्री को किसी विदेश यात्रा के दौरान अथवा विदेशी उच्चाधिकारी से कोई उपहार मिलता है तो उस उपहार का अनुमानित मूल्य बताते हुए वह इसे प्रधान मंत्री के ध्यान में लाए। यदि इसका मूल्य 450 रुपए से कम हो अथवा यदि वह प्रतीकात्मक हो, तो वह मंत्री द्वारा अपने पास रखा जा सकता है। किन्तु यदि उपहार के अनुमानित मूल्य के बारे में कोई सन्देह हो तो यह मामला मूल्यांकन के लिए तोशाखाना को भेजा जा सकता है। यदि वह मूल्य 450 रुपए की निर्धारित सीमा के अन्दर पाया जाता है तो वह उपहार मंत्री महोदय को वापिस लौटा दिया जाएगा। यदि वह 450 से अधिक हो तो तोशाखाना द्वारा आंके गए मूल्य और 450 रुपए के बीच के अन्तर का भुगतान करके उसे तोशाखाना से खरीदने का प्राप्तकर्ता को विकल्प होगा।

मंत्रियों की परिलब्धियों पर किया गया व्यय

3621. श्री हुक्म चन्द कछवाय :

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों के सरकारी मकानों के रख-रखाव-वेतन-भत्ते दोरों तथा

कारों का रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में अलग-अलग सरकार का कितना खर्च हुआ है; और

(ख) उपरोक्त मदों पर वित्तीय वर्ष 1969-70 में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :: (क) और (ख), 1966-67, 1967-68, 1968-69 में

केन्द्रीय मंत्रियों के सरकारी मकानों के रख-रखाव, वेतन, भत्ते तथा दौरो पर सरकार द्वारा किए गए खर्च की राशि तथा वित्तीय वर्ष 1969-70 में इन मदों पर किये जाने वाले अनुमानित खर्च के सम्बन्ध में सूचना मंगलन विवरण में दी गई है।

मंत्रिगण सरकारी कर्तव्यों का निष्पादन करते समय मंत्रालयों की स्टाफ कारों का प्रयोग करते हैं। स्टाफ कार निश्चित रूप से मंत्रियों को आवंटित नहीं की जाती है।

विवरण

वर्ष	सरकारी मकानों का रख-रखाव	वेतन	भत्ते	दौरा खर्च
1966-67	10,64,306	13,10,075	1,14,027	14,07,629
1967-68	10,41,194	12,40,481	1,16,747	10,58,700
1968-69	11,74,381	12,98,161	99,064	20,56,236
1969-70 (अनुमानित खर्च)	11,47,399	13,65,000	1,14,000	12,00,000

EXTENSION GRANTED TO CABINET SECRETARY

3622. SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Cabinet Secretary who was due to retire in November, 1969 has been granted extension;

(b) if so, the reasons for granting him the extension which is in contravention of the convention that no extension should be given to any officer in view of the acute unemployment in the country;

(c) whether it is also a fact that extensions are given to high officials only and not to the Class II, III and IV officers; and

(d) if so, whether Government propose to withdraw its order in this case ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The present Cabinet Secretary has been granted extension in public interest. It is not correct to say that this was in contravention of any convention against grant of extensions. In the past also whenever public interest so required, extension have been given.

(c) No, Sir. Extension in service is granted to an officer in public interest, irrespective of the class to which he belongs.

(d) No, Sir.

मध्य प्रदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

3623. श्री० गं० च० दीक्षित : क्या पर्यटन तथा अतिरिक्त उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में हाल में ही पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों को देखने कितने पर्यटक गए;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में कितने भारतीय तथा विदेशी पर्यटक गए थे; और

(ग) उतारोक्त अवधि में मध्य प्रदेश आने वाले विदेशी पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जन की गई ?

पर्यटन तथा अतिरिक्त उड्डयन मंत्री (डा० हर्ष सिंह) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग अलग-अलग राज्यों अथवा पर्यटक रुचि के स्थानों को आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या को दिखाने वाले आंकड़े नहीं रखना है ।

चलचित्र प्रदर्शन की समाप्ति पर राष्ट्रगान के प्रति स्वल्प सम्मान

3624. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र प्रदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों की समाप्ति पर राष्ट्र-गान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करने की प्रथा कम होती जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रथा में आवश्यक परिवर्तन करने का है; और

(ग) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ख). मिनेमाघरों में जब राष्ट्रीयगान बजाया जाता है तो आमतौर पर लोग खड़े हो जाते हैं और उचित शिष्टता बनाए रखते हैं । तथापि, दर्शकगणों द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लंघन किये जाने की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कुछ समय पहले सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने मिनेमा दिखाने वालों से अपील की थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो दर्शकों द्वारा उचित शिष्टता बरती जाए । इस सम्बन्ध में यथोचित उपाय करने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था । मिनेमाघरों में तथा आकाशवाणी से राष्ट्रीय गान बजाने का उद्देश्य दर्शकों/श्रोताओं को हमारे देश तथा लोगों की एकता का स्मरण कराना है और इसके द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है । अतः इस प्रथा में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है । तथापि, सरकार को आशा है कि दर्शकों में इस बात का और अधिक बोध हो जाएगा कि राष्ट्रीय गान बजाए जाने समय उचित शिष्टता बरती जाए ।

बेरोजगार इंजीनियर

3625. श्री नारायण स्वरूप शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री 3 अप्रैल, 1969 के अतारिक्त प्रश्न संख्या 5202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार के अवसर देने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में सामहित विभिन्न विकाम कार्यक्रमों का व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे बेरोजगार इंजीनियरों को, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में इस समय पंजीकृत हैं, उस समय तक रोजगार भत्ता देने का विचार है जब तक उन्हें कोई उपयुक्त रोजगार नहीं मिल जाता, और

(ग) यदि नहीं, तो देश में ऐसे सभी इन्जीनियरों को किस समय तक काम पर लगाये जाने की सम्भावना है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) व्योरे अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना अभी प्रारूप की अवस्था में है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

मध्य प्रदेश में डाकुओं का मारा जाना और उनकी गिरफ्तारी

3626. श्री भारत सिंह चौहान :

श्री हनुम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से इस बात के आंकड़ें इकट्ठे किये हैं कि गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के डाकुओं से तत्क्षेत्र में कितने डाकू मारे गये और कितने पकड़े गये और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . अपेक्षित सूचना मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

DYNAMITE STICKS PLACED IN FARIDPUR POLICE STATION IN BURDWAN DISTRICT—WEST BENGAL

3627. SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a number of dynamite sticks were placed in the Faridpur Police Station in Burdwan District, on the Grand

Trunk Road in the last week of October or the first part of November, 1969;

(b) whether a red scarf was found near one of the sticks; and

(c) whether any inquiry has been held and if so, result of such inquiry ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

REPRESENTATION BY THE STAFF ALLOTTED FROM PUNJAB TO HIMACHAL PRADESH

3628. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 62 Secretariat Staff people allocated from Punjab Secretariat to Himachal Pradesh Secretariat have sent a representation through their elected representatives in August, 1969 and subsequently in September onwards to the Central Government for the fixation of the scales and their promotion; and

(b) if so, whether these have been examined and the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Representations have been received from a number of clerks allocated to Himachal Pradesh Secretariat from Punjab Secretariat through their elected representative against the equation of their posts with those of Junior Clerks of Himachal Pradesh Secretariat and also for the withdrawal of a formula for determining *inter se* seniority, recommended by an Advisory Committee constituted under Clause (4) of Section 82 of the Punjab Reorganisation Act 1966. The representations are being examined.

INCREASE IN AIR FARE BY I.A.C.

3629. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether air-fares have again been

increased by I.A.C. with effect from 1st November, 1969; if so, to what extent;

(b) whether it is a fact that the Union Territory of Tripura, surrounded on three sides by East Pakistan, has chiefly to depend on the Calcutta-Agartala air-services for communication with rest of the country;

(c) if so, whether in view of these facts and backwardness of tribal infested territory, the question of exempting the Calcutta-Agartala air-services from the general increase in fares had been considered as a special case; and

(d) if the answer to part (c) above be in affirmative, Government's decision in the matter, and if it is in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. The air fares have been increased with effect from 1st November, 1969 as follows :

8% on trunk routes

7% on regional routes

5% on eastern routes including Tripura.

(b) yes, Sir.

(c) and (d). In view of the answer to part (b), the fare increase on the sectors serving Tripura has been kept down to 5% as against 8% and 7% on most of the other routes.

EXTRACTION OF SYNTHETIC PETROL FROM COAL AND LIGNITE BY C.S.I.R. •

3630. SHRI K. M. KOUSHIK :

SHRI MEETHA LAL MEENA :

SHRI J. MOHAMMED IMAM :

SHRI R. K. AMIN :

SHRI MAHENDRA MAJHI :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether any attempts have been made by C.S.I.R. to make synthetic petrol from Coal (Bihar) and Lignite (Neyveli); and

(b) if so, details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The experiments conducted at Central Fuel Research Institute, Jealgora, did not find Bihar Coal suitable for conversion to synthetic oil due to its inherent nature.

The laboratory experiments conducted at the Institute showed encouraging results for conversion of Neyveli lignite to oil by direct hydrogenation or by Fischer Tropesch synthesis *via* gasification. Further work is in progress.

GRADE I STENOGRAPHERS' SCHEME

3631. SHRI C. K. CHAKRAPANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Grade I Stenographer's Scheme is still pending due to the conflicting policy decision of the Ministries concerned; and

(b) the reasons for the delay in the finalisation of the scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

INQUIRY INTO CHHOTI SADRI GOLD SCANDAL

3632. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the inquiries into Chhoti Sadri Gold Scandal case have been completed :

(b) if not, the reasons for the delay; and

(c) the time by which the inquiries are likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) A case relating to alleged misappropriation of gold by Shri Ganpat Lal

and others is pending in the court of the Civil Judge-Magistrate Udaipur. During the pendency of the criminal case enquiries have to be conducted with due regard to the provisions of the law and this takes time.

(c) This will depend on the progress in the court case.

LEAVE TRAVEL CONCESSION TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

3633. SHRI N. R. DEOGHARE :
SHRI NIHAL SINGH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government employees are given Leave Travel Concession once in two years to visit their home town;

(b) whether it is also a fact that those employees whose home town is their place of work are not entitled to any such concession;

(c) if so, whether the Government propose to give a concession to such employees for travelling once in two years to any place of their choice; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) No Sir.

(d) The Scheme of Leave Travel Concession is not intended to subsidize travel expenses to places other than the home town of the Government servant.

AIRPORTS FOR LANDING JUMBO JETS

3634. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the names of places where airports for the purpose of landing Jumbo Jets would be constructed ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : It is not proposed to construct

any new airports for the Jumbo Jets. The facilities available at the existing international airports at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras are being augmented to make them suitable for the operation of these new planes.

VISITS BY MINISTERS ABROAD

3635. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether there is any Minister, Minister of State or Deputy Minister in the present Council of Ministers who has not been to any foreign country during his ministership, and if so, the names of those Ministers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES' RIGHT TO STRIKE

3636. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees' organisations throughout the country have made an appeal to the Prime Minister not to take away the right to strike; and

(b) if so, her reaction thereto and whether she is likely to discuss this matter further with the employees' representatives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए एक व्यक्ति की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति

3639. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग में कोई ऐसा सदस्य है जिसने एक केन्द्रीय

विश्वविद्यालय में अपने पुराने पद से सेवा-निवृत्त होने के बाद आयोग की सदस्यता स्वीकार की है ;

(ख) क्या कोई व्यक्ति जिसका सरकारी अथवा अर्धसरकारी पद पर किसी न किसी रूप में धारणाधिकार है, नियमों के अन्तर्गत उक्त आयोग का सदस्य बन सकता है ; और

(ग) यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपने पहले पद से सब सम्बन्ध तोड़कर उक्त आयोग की सदस्यता स्वीकार की है तो उसने किस तिथि को अपने संबंध पुराने पद से तोड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक सदस्य, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से अपना कार्य-भार त्यागने के पश्चात्, आयोग में शामिल हुए ।

(ख) और (ग) : वर्तमान नियमों के अनुसार उस सरकारी कर्मचारी का धारणा-धिकार, जिसका वेतन भारत में सिविल प्राबकलों के नामे डाला जाता है तथा जो किसी स्थायी पद को मौलिक रूप से धारण किये हुए है, उसके संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त होने पर, समाप्त कर दिया जाता है । अनुमान लगाया जाता है कि "अर्ध-सरकारी पद" शब्दावली का आशय उस पद से है जो किसी निकाय में हो, चाहे वह निगमित हो निपटान के लिये प्रक्रिया सदन में आज अतारंकित प्रश्न संख्या 3619 के उत्तर में बतलाई गई है । जहां तक अन्य व्यक्तियों के उपहारों का सम्बन्ध है, मंत्रियों के लिये आचार संहिता में पहले ही यह प्रावधान है कि निकट के संबंधियों को छोड़कर अन्य किसी से मूल्यवान उपहार स्वीकार न किये जाएं और यह कि उसे अथवा उसके परिवार के सदस्यों को किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके साथ उसका सरकारी व्यवहार हो बिल्कुल कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए । अतः ऐसे उपहारों को कोष अथवा तोशाखानों में जमा कराने अथवा उनके

बदले भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार लोक सेवा आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति

3640. श्री प्रकाशबीर शास्त्री :

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय का एक ज्ञापन अथवा पत्र प्राप्त हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति के मामले में राजनीतिक दबाव डाला गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक व्यक्ति को जो हर दृष्टिकोण से योग्य एवं उपयुक्त था और जिसके नाम की विधिवत सिफारिश की गई थी, सदस्य के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति मुख्यतः उत्तरदायी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय एकता समिति की स्थायी समिति से बहिर्गमन

3641. श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता समिति की स्थायी समिति के कुछ सदस्यों ने हाल ही में दिल्ली में हुई इसकी बैठक से बहिर्गमन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या उन सदस्यों ने कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विचारों से समिति के सहमत न होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग)। जबकि राष्ट्रीय एकता समिति की स्थायी समिति 16 अक्तूबर, 1969 को अपनी बैठक में प्रारूप वक्तव्य की अभिस्वीकृत करने पर विचार रही थी, एक सदस्य बैठक के लगभग अन्त में बाहर निकल आये क्योंकि उनके द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किये गये थे समिति को स्वीकार नहीं थे। अन्तिम रूप से अभिस्वीकृत वक्तव्य की तथा सम्बन्धित सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की सूची की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रख दी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2344/69]

(घ) स्थायी समिति को निम्नलिखित कारणों से संशोधन स्वीकार नहीं थे :-

(i) संशोधन सं० 1 "सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता की आवश्यकता" के संदर्भ को वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रासंगिक नहीं समझा गया जो मूलतः साम्प्रदायिक मेल-मिलाप और सद्भाव के लिये शीघ्र उपाय करने के लिये था।

(ii) संशोधन सं० 2 (क) : यह संशोधन समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इससे समिति के उद्देश्य व्यक्त नहीं होते।

(iii) संशोधन सं० 2 (ख) : स्थायी समिति ने संशोधन स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस राष्ट्र में राष्ट्रीय जीवन की "मुख्य प्रेरणा" को परिभाषित करना सम्भव नहीं है जहाँ विविधता

में एकता विशिष्ट लक्षण है और किसी अल्पसंख्यक समुदाय के भारतीयकरण के बारे में सभी बातें समिति के दृष्टिकोण में पूणतः गलत आधार-वाक्यों पर आधारित थी।

PURCHASE OF VEHICLES

3642. SHRI ABDUL GHANI DAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of cars, station wagons, trucks and police vehicles purchased by his Ministry during the last three years, year-wise and the amount paid for such purchases; and

(b) the number of officers of his Ministry who purchased cars for their own use during this period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No station wagons, trucks or police vehicles were purchased for the Ministry proper during the last three years. The position regarding staff cars is given below :-

Years	No. of car purchased	Amount spent
1967-68	1	Rs. 19,405.67
1968-69	1	Rs. 50,586.63
1969-70	2	Rs. 38,832.00
(b) 1967	15	
1968	10	
1969	9	
	34	

STATUE OF SHRI RAFI AHMED KIDWAI NEAR PARLIAMENT HOUSE

3643. SHRI ABDUL GHANI DAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to instal a statue of the late Shri Rafi Ahmed Kidwai near Parliament House; and

(b) if so, when ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

CINEMA IN MUZAFFARPUR BOMBED

3645. SHRI ABDUL GHANI DAR . Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any cinema in Muzaffarpur was bombed in 1969 due to exhibition of a film against China; and

(b) whether Government took any action in the matter and if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

AGITATION FOR DIVISION OF MYSORE

3646. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the dissident Mysore Congressmen having threatened to revive the agitation for division of the State unless immediate steps are taken to remove the alleged discrimination against people living in the Old Mysore State in the matter of economic development and employment;

(b) whether Government propose to appoint some commission to examine the feasibility of smaller States in the country; and

(c) if so, the details thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No such threat has been received by Government.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

RISE IN PASSENGER FARES FOR KONKAN PORTS

3647. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have raised the passenger fares for Konkan ports; and

(b) if so, to what extent and the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY (SHRI SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH)) : (a) and (b). Yes Sir. A general increase of 8% was allowed with effect from the 10th September, 1969, as the existing fares were inadequate and the company was incurring losses.

RELEASE OF DOCUMENTS/PAPERS REGARDING TRANSFER OF POWER IN INDIA

3648. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of pre-independent India agreed with the Government of Britain that official documents dealing with the transfer of power in India will not be officially released until the year 1999 and if so, the details of the same;

(b) whether Government will publish a 'White Paper' dealing with the details of documents, papers, memorandum, official notes on conversations held between the then leaders of India and the representatives of the Government of Britain; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) and (c). On the basis of the recommendation of the Indian Historical Records Commission, a proposal is under consideration of the Ministry of Education to publish documents pertaining to events leading to the partition and transfer of power.

FACE-LIFTING OF ASHOKA HOTEL

3649. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is proposed to give Ashoka Hotel a face-lift;

(b) whether it would be a mere 'touch-up' or it would aim at expansion of accommodation or provision of additional facilities and conveniences in the hotel; and

(c) the salient renovation features and the cost thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). Yes, Sir. The Board of Directors of Ashoka Hotels Limited has instituted a comprehensive programme of renovating some of the public areas and two floors of the main building of the Ashoka Hotel, as no major renovation had been undertaken since it was constructed 13 years ago. From the commercial point of view the need for a major renovation of Ashoka Hotel has long been indicated, and the present work is expected substantially to improve its attractiveness and profitability. The salient features of the renovation are :

- (i) 126 rooms on the 6th and 7th floors have been completely renovated.
- (ii) The Lobbies and the Corridors on these two floors have been brightened by improved lighting and improved ceilings.
- (iii) The Main Entrance including the Lobby has been re-designed so that the area opens out into the newly created landscape.
- (iv) Existing public areas have been converted to achieve better commercial use. The majority of the existing shops have also been renovated. Three newly designed Restaurants are being created in lieu of the existing Dining Hall and Grill.
- (v) To improve service in rooms, a centralised room service is being located in the Main Kitchen with additional lifts to all floors.

INSTITUTE FOR TRAINING OF GUIDES FOR TOURISTS, AIRLINES AND HOTELS

3650. SHRI N. SHIVAPPA :
DR. P. MANDAL :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion that a regular Institute or College for the training of guides for tourists, airlines and hotels should be established by Government;

(b) whether Government feel the necessity of cultivating the right approach to the foreign tourists bearing in mind that their behaviour leaves a lasting impression on foreigners; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Government have set up a training cell in the Department of Tourism and are actively considering the establishment of a regular Training Institute.

विदेशों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार

3651. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नन्द
श्री अटल बिहारी वाजपेयी

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिये किये जाने वाले कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में भविष्य

के लिये किये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). फिलहाल, यह मंत्रालय क्रमशः सुरिनाम, गियाना तथा त्रिनीडाड में तीन हिन्दी एवं सांस्कृतिक लेक्चरर्स की नियुक्ति जारी रख रहा है। यह भी विचार है कि 1969-70 के दौरान काठमाण्डू (नेपाल) में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए, जिसमें हिन्दी और संस्कृत की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं काफी संख्या में रहेंगी और कुछ पुस्तकें भारतीय विद्या एवं भारतीय संस्कृति के सम्बंध में भी होंगी। अगले वित्तीय वर्ष में विदेशों में हिन्दी के प्रचार की योजना के विस्तार के लिये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हो रहा है। ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् जंग्रेव विश्वविद्यालय (युगोस्लाविया) में भारतीय विद्या के एक प्राध्यापक को जो हिन्दी भी पढ़ाता है, तेहरान विश्वविद्यालय में संस्कृत सिखाने के लिये एक प्राध्यापक, बुखारेस्ट (रोमानिया) विश्वविद्यालय में हिन्दी सिखाने के लिये एक प्राध्यापक तथा मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) विश्वविद्यालय में, भारतीय अध्ययन सम्बंधी लेक्चर देने के अलावा बंगाली पढ़ाने वाले भारतीय विद्या अध्ययन के लिये एक प्राध्यापक को जारी रखे हुए हैं। परिषद् का विचार चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन की कम से कम दस पीठ स्थापित करने का है। इन पीठों में से, तीन दक्षिण पूर्वी एशिया में, चार पश्चिम एशिया में, दो अफ्रिका में तथा एक दक्षिण अफ्रिका में स्थापित की जाएंगी। इन पीठों के प्राध्यापकों से, जो भारत से भेजे जाएंगे, भारतीय अध्ययन पर लेक्चर देने के अलावा, कुछ भारतीय भाषाएं सिखाने के लिये भी आशा की जायगी।

इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन द्वारा माल ढोया जाना

3652. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री सूरज भान :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री शारदा नन्द :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर-लाइंस कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 1965-66 और 1968-69 में क्रमशः 15 हजार मीटरी टन और 23 हजार मीटरी टन माल ढोया गया है; और

(ख) यदि हां, तो माल के लिये अधिक स्थान की बढ़ती हुई उत्तरोत्तर मांग को पूरा करने के लिये माल ले जाने की क्षमता को बढ़ाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक विमान प्राप्त करके तथा कुछ मुख्य मार्गों पर एयर इंडिया की सेवाओं पर उपलब्ध क्षमता का उपयोग करके इंडियन एयर लाइंस द्वारा माल वहन की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।

भारतीय भाषाओं की केन्द्रीय संस्था

3653. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री सूरज भान :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री शारदा नन्द :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं की केन्द्रीय संस्था, मैसूर के कार्य और कार्य प्रणाली क्या

है और उसका अब तक का अनुभव कैसा रहा है।

(ख) क्या इसकी शाखाएं देश के अन्य भागों में खोली जायेंगी, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान की मसूर में स्थापना की है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य भारतीय भाषाओं के विकास में सहायता और समन्वय प्रदान करना है।

संस्थान का एक प्रमुख कार्य होगा : इतिहास शब्दावली और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रसंगों और विषय वस्तु के संदर्भ में विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच में एकता की कड़ियों का पता लगाना।

संस्थान द्वारा, भारतीय भाषाओं का शिक्षण सुगम बनाने की प्रणालियों के निर्धारण, विभिन्न भाषाओं को संखने में जो समय लगता है उसे कम करने और बेसिक तमिल, बेसिक कन्नड़, बेसिक हिन्दी, बेसिक उर्दू आदि की बुनियादी शब्दावली तैयार करने के कार्य भी किये जायेंगे।

संस्थान विश्वविद्यालयों और राज्य निकायों की भाषागत गतिविधियों की अनुपूरित नहीं करेगा बल्कि दोहरे ध्रम और व्यर्थता के खर्च को रोकने के लिये अत्यंत आवश्यक समन्वय एजेन्सी का भी कार्य करेगा। संस्थान ऐसे अंतर विषयक कार्यक्रम प्रारम्भ करेगा जिसमें बहुत से विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और विषयों का सहयोग अपेक्षित होगा।

संस्थान उन प्रमुख जनजातीय भाषाओं का भी सर्वेक्षण करेगा जिनकी कोई लिपि नहीं है ताकि उनके लिये लिपि की व्यवस्था हो सके

जिससे कि जनजातियों को प्रारम्भिक शिक्षा उनकी अपनी भाषा ही में दी जा सके और साथ ही उसे दूसरों को पढ़ाया जा सके जो उनके साथ प्रशासनिक अथवा सांस्कृतिक सम्पर्क में आएँ।

चूँकि संस्थान अभी अपनी प्रारम्भिक स्थिति में है और अपेक्षित स्टाफ आदि की नियुक्ति की जा रही है, अभी कोई अनुभव प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

उल्लिखित प्रकार के कार्यकलापों के लिये देश के अन्य भागों में शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, जहां भी आवश्यक हो, प्रमुख जनजातीय भाषाओं के सर्वेक्षण के लिये संस्थान क्षेत्र स्टेशन कायम करेगा।

मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा और गुना जिलों में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजन

3654. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकूम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री 8 अगस्त, 1969 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा तथा गुना जिलों में गुप्त रूप से रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने किसने किस तारीख को उन जिलों में अपने नाम पंजीकृत कराये थे;

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्होंने अपने वीजों की अवधि कितनी बार बढ़वाई और हर बार प्रत्येक के वीजे की अवधि कितनी-कितनी बढ़ाई गई; और

(ग) उनके वीजों की अन्तिम बार बढ़ाई गई अवधि कब समाप्त हुई।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (र) से (ग) : सूचना ए. ए. की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

मध्य प्रदेश के खंडवा, दुर्ग और ग्वालियर जिलों में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजन

3655. श्री भारत सिंह चौहान :

श्री झा० सुन्दर लाल :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्रों 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के संबंध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खंडवा, दुर्ग और ग्वालियर जिलों में इस समय चोरी छिपे रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने उन जिलों में किस तिथि को अपने नाम पंजीकृत कराये थे;

(ख) उनके वीसा की बढ़ी हुई अवधि किस तिथि को समाप्त हुई थी;

(ग) उनका वीसा कितनी बार बढ़ाया गया और हर बार कितनी अवधि के लिए; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो वहां चोरी छिपे रह रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

PAK NATIONALS LIVING IN RATLAM DISTRICT OF MADHYA PRADESH

3656. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which each of the 56 Pakistani nationals at present living underground in District Ratlam of Madhya Pradesh got themselves registered in the District;

(b) the dates on which the periods of last extension of their visas expires;

(c) the number of times the periods of their visas were extended and the periods for which these were extended each time and in each case; and

(d) the names of these Pakistani nationals ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजन

3657. श्री भारत सिंह चौहान :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्रों 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सिहोर जिले में गुप्त रूप से रह रहे पांच पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने किस-किस तारीख को अपने नाम उक्त जिले में दर्ज कराये थे;

(ख) इन लोगों ने कितनी बार अपने वीजों की अवधि बढ़वाई और हर बार उनके वीजों की अवधि कितनी-कितनी बढ़ाई गई;

(ग) उन लोगों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन लोगों को बाहर निकालने का काम विशेष पुलिस कर्मचारियों को सौंपने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

अमरीकी प्रेजिडेंट निक्सन के भारत आगमन के समय नई दिल्ली में साउथ एवेन्यू में नारे लगाये जाने की घटना

3658. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शारदा नन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी प्रेजिडेंट निक्सन के हाल ही में भारत आगमन के समय कुछ व्यक्तियों ने उस समय नारे लगाये थे जब वह नई दिल्ली साउथ एवेन्यू से गुजर रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 उस समय साउथ एवेन्यू क्षेत्र में लागू थी; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार साउथ एवेन्यू क्षेत्र के कुछ भागों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू थी । किन्तु वह स्थान, जहाँ नारे लगाये गये थे, निषेधाज्ञा के अन्तर्गत नहीं आता था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रहे रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

3659. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्रों 8 अगस्त, 1969 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इस

समय जो 10 पाकिस्तानी चोरी-छिपे रहे रहे हैं उन्होंने उन जिले में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है;

(ख) उनके वंशों की अवधि जो पिछली बार बढ़ ई गई थी कि तारीख को समाप्त हुई थी;

(ग) उन्हें उज्जैन के अतिरिक्त किन स्थानों में जाने का अधिकार दिया गया था; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जो कि चोरी-छिपे रहे रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : () से (घ). सूचना एकांतरिक जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दं जायगा ।

FORMATION OF NEW DISTRICTS IN BIHAR

3660. SHRI J. M. BISWAS :
SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI YOGENDRA SHARMA :
SHRI VASUDEVAN NAIR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government has decided to create new District and sub-Divisions in the State;

(b) if so, the number of new Districts and Sub-Divisions to be created; and

(c) the reasons for creating New Districts and Sub-Divisions in the State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). It is intended to create 6 new districts and 9 new sub-divisions. A reference is invited to reply furnished to Unstarred Question No. 895 on 21st November, 1969.

(c) There has been a long standing popular demand for reorganisation of districts and sub-divisions in the interests of efficiency of normal and developmental administration.

QUESTION REGARDING WHIPS VERSUS CONSCIENCE VOTES DISCUSSED AT WHIPS CONFERENCE

3661. SHRI SHRI CHAND GOYAL :
Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a question was raised at the Whips Conference held recently at Madras regarding the whips versus conscience votes and the majority of the members participating in the Conference were in favour of adopting the Resolution thereon; and

(b) whether it is a fact that the resolution was not adopted under the plea that there was no unanimity on it ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Some of the delegates to the Seventh All India Whips' Conference held at Madras in September, 1969 gave notices of resolution against freedom of voting on the pretext of conscience or on any other basis. The resolution, which was considered by one of the Committees of the Conference, was not recommended for adoption by the Conference.

(b) Since differing views were expressed by the delegates about the admissibility of the resolution, the President of the Conference disallowed its consideration.

SERVICE CONDITIONS OF DRAFTSMEN IN HIMACHAL PRADESH

3662. SHRI SHRI CHAND GOYAL :
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the draftsmen allocated to Himachal Pradesh as a result of reorganisation of Punjab had provision in their rules applicable to them in composite Punjab of being promoted to the post of Assistant Engineers;

(b) if so, whether the provision has been altered and they are not being considered for promotion in Himachal Pradesh;

(c) if so, whether the Himachal Pradesh Government obtained prior approval of the Central Government as contemplated under the Punjab Reorganisation Act, 1966 to vary the service conditions of draftsmen, affecting their prospects of promotion;

(d) if so, whether similar consent was also given to the other States affected by reorganisations; and

(e) whether there are any promotion rule for draftsmen now allocated to Himachal Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) According to information given by the Government of Himachal Pradesh, in the Government of composite Punjab there was a provision for the promotion of Draftsmen successively to the posts of Head Draftsmen (Division), Head Draftsmen (Circle) and Assistant Engineers.

(b) The Government of India in exercise of their powers under provision of Article 309 of the Constitution have framed the Himachal Pradesh Allotted Government Servants (Conditions of Service) Rules, 1968, for regulating the conditions of service applicable to allotted Government servants. A copy of the rules is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. IT-2345/69].

(c) and (d). In view of the reply to para (b), the question does not arise.

(e) Himachal Pradesh Government have informed that draftsmen in Himachal Pradesh are considered for successive promotion to the posts of Head Draftsmen (Division), Head Draftsmen (Circle) and Planning Assistants.

BAN ON THE BOOK KNOWN AS 'DHARMA BUMS'

3663. SHRI SHRI CHAND GOYAL :
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a book known as "Dharma Bums" by Dr. Azizul Abbasi Vidyarthi;

(b) whether Government are aware that the book is full of filthy abuses of

Lord Rama and Krishna and of the Prime Minister; and

(c) whether Government are contemplating to ban the entry of the book in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Orders have also been issued under Section 99A Cr. P.C. forfeiting every copy of the book to Government. Instructions have also been issued to prevent the entry of the book into the country.

DISPOSAL OF WORK IN OFFICES

3664. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the reasons why an entry should not be added in the annual record of an official's work to show percentage of disposal of the work allotted to him;

(b) the reasons why the recommendation of the Administrative Reforms Commission that each official may submit a record of outstanding work done by him, has not been accepted;

(c) the reasons why all civil officials are not categorised annually as in the Army and the categorisation brought to their notice to encourage improvement; and

(d) what other measures exist to encourage competition for better work among officials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The existing Confidential Report form contains a specific provision for reporting on the speed of disposal of the work allotted to the Government servant reported upon. The Administrative Reforms Commission in their Report on Personnel Administration have made certain recommendations including the one referred to by the Member which are under consideration.

(c) There is provision for categorising civil officials in regard to their fitness for

promotion. As regards bringing the categorisation to the notice of the officials, in the case of military officers the Annual Confidential Reports are shown to them and their signatures obtained thereon. On the civil side such a practice is not in vogue; but where adverse remarks are made in the Report, in order that the officer may see the adverse remarks in the correct perspective, the adverse remarks as well as the substance of the entire report is communicated to the officer concerned. Instructions have also been issued that apart from the communication to the officer concerned of such remarks on the Annual Confidential Report as are considered to be clearly adverse, in cases where there is a fall in the standard of an officer in relation to his past performance, as revealed through his Annual Confidential Report, the attention of the officer should be specifically drawn to that so that he could be alerted for improving his performance. In view of his position it is not considered necessary to show to the officer concerned the Confidential Report on him recorded by his superiors.

(d) A scheme of merit promotion and advance increments to Scientific/Technical personnel is already in force. In regard to other personnel the fact that outstanding performance will be taken into account in the matter of promotion to selection posts is in itself an incentive for better performance.

REPRESENTATION OF MINORITIES IN SERVICES

3665. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what steps have been taken on the resolution of the National Integration Council, to improve the representation of minorities in the lower services;

(b) whether any information has been obtained from the Ministries of Central Government and the State Governments about the existing percentage of minorities in the Services comparatively and their proportion in the population;

(c) whether it is a fact that the representation of Muslims in the Revenue administration of South Kanara is only one

percent against a population of 9 percent; and

(d) the reasons for not issuing directions to secure some informal reservation of appointments for minorities so that their frustration is removed and national integration achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Though no specific resolution has been passed by the National Integration Council on the subject, the question of representation of minority communities in services had come up during discussions in the meeting of the Standing Committee of the National Integration Council. The matter was also discussed in a conference of Chief Ministers held on May 19, 1968. It was pointed out by the Home Minister that there was no proposal for reservation for any minority community in services. What was needed was to see that no prejudices worked against certain communities, and that proper opportunities were provided to the members of the minority communities. It was agreed that the position in this regard should be reviewed by the State Governments, and all possible efforts should be made to step up the recruitment of members of the minority communities in services, subject to the observance of the relevant constitutional provisions.

(b) No information regarding employment of all the various minorities in the Services under the Central and State Governments has been obtained. Some time back, however, some of the Ministries of the Government of India had been asked to furnish figures of Muslims and Christian employees under them and the State Governments too had been asked to furnish similar information in regard to Muslim employees. Information in regard to Muslim employees in the three Central Secretariat Services was given in reply to unstarred question No. 9935 in the Lok Sabha on 16th May, 1969.

(c) This is a matter primarily concerning the State Government. The Ministry of Home Affairs have no information.

(d) In view of the provisions of Article 16 of the Constitution, no such direction can be given.

CODIFICATION OF SERVICE CONDITION ON NON-TEACHING STAFF IN DELHI UNIVERSITY

3666. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no codified service condition of non-teaching staff in Delhi University;

(b) if so, the reasons for the same;

(c) whether there is a growing discontentment among the non-teaching staff because of unreasonable attitude of the university authorities; and

(d) if so, the steps taken by Government to have a negotiated settlement of various issues?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The service conditions of non-teaching staff of the Delhi University, which are at present laid down in the form of Rules nearly corresponding to those applicable to Central Government employees, are now proposed to be revised and embodied in the form of an Ordinance.

(c) and (d). According to the information furnished by the University authorities, no such situation exists. The members of non-teaching staff had, in the past, made certain representations and the University took action on them. The University has also appointed a Working Group to go into the problems and issues on which detailed investigation and study seem necessary in respect of matters concerning non-teaching staff.

DEMAND FOR BRINGING KANPUR ON TOURIST MAP

3667. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a request has been made by various organisations of Kanpur to bring Kanpur on the tourist map; and

(b) if so, whether proper investigations have been made and the result of the investigations?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). I am not aware of any such request. It needs to be pointed out, however, that there is no system of a particular place being brought on the tourist map by the Government of India. We only render assistance in providing tourist facilities wherever they are justified.

PROTECTION OF BELLUR MUTH, CALCUTTA

3668. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of the Central Government that some political parties in West Bengal are making serious efforts to take possession of the famous Bellur Muth situated on the bank of Hooghly river in Calcutta and if so, the details thereof;

(b) whether it is a fact that the State Government of West Bengal is not taking any steps to protect the Muth; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above are in the affirmative, what steps are being taken by the Central Government to protect such Muths of national importance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The State Government have no information of any efforts being made by any political parties to take possession of the Bellur Muth in district Howrah.

(b) and (c). Does not arise.

REORGANISATION OF ADMINISTRATIVE MACHINERY

3669. SHRI RAMAVTAR SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to re-organise the administrative machinery dominated by the I.C.S. officers at the Centre and create an administrative cadre of officers committed to national objectives and responsive to social needs; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Administrative Reforms Commission set up in 1966 was required, among other things, to give consideration to the need for making public administration a fit instrument for carrying out the social and economic policies of the Government and achieving social and economic goals of development, as also one which is responsive to the people. The Commission has submitted a number of reports to the Government, including one on personnel administration. Some of the recommendations of the Commission made in these reports have already been accepted and implemented by the Government and the remaining recommendations are receiving consideration. The Government proposes to implement the recommendations of the Commission to the maximum extent feasible.

FORMATION OF NEHRU BRIGADE

3670. SHRI RAMAVTAR SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the formation of a Nehru Brigade;

(b) whether the volunteers of the said Brigade will wear uniforms and will be given training also; and

(c) if so, Government's reaction in this regard and what steps Government are taking to check the formation of such private armies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). According to the report furnished by the Delhi Administration, volunteers donning Gandhi caps and badges of white cloth with the words "Nehru Brigade" inscribed thereon came to notice on 19-11-1969 and 22-11-1969. Government have no further information as to whether the volunteers of the Brigade will wear uniform or receive any training.

(c) Government's attitude to the activities of private armies (senas) has been clarified in reply to Lok Sabha unstarred question No. 911 dated 25-7-1969.

ALLEGATION AGAINST DELHI POLICE OFFICIALS

3671. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Sub-Inspector of Delhi Police had written a letter dated the 13th August, 1969 to him, copies of which had been sent to all concerned, levelling serious allegations against the Delhi Police officials;

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken by Government thereon;

(d) whether a copy of the said letter will be laid on the table of the House; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (e). A letter dated 13-8-1969 was received from a Sub-Inspector of Delhi Police addressed to the Prime Minister of India in which he had made general allegations that many senior police officers do not treat their juniors well. He had also mentioned that in order to bring about a real understanding between the officers of the Delhi Police in the Gandhian era he would be undertaking an indefinite hunger strike in front of the Parliament House from 14th August, 1969. On the date given in this letter (i.e. 13-8-1969) the Sub-Inspector was on leave on medical grounds as advised by the Medical Superintendent, Shahdara Mental Hospital, for treatment of the mental depression from which he was suffering.

The Sub-Inspector staged dharna in front of Parliament House on 14-8-1969 in contravention of the prohibitory orders under section 144 Cr. P.C. Since he did not desist from the Dharna inspite of the advice of the Sub-Divisional Magistrate he is facing a charge under section 188 I.P.C.

As regards the letter of Sub-Inspector, since the allegations made were general in nature no action was taken.

RE-NAMING OF ISLAND AND PORTS IN ANDAMAN AND NICOBAR GROUP OF ISLANDS

3672. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the names of the islands and ports in Andaman and Nicobar Group of Islands were given according to the names of the British conquerors and rulers, and these names are still being retained; and

(b) if so, the names of such islands and ports;

(c) whether such names are derogatory to the honour of the Indian nation; and

(d) if so, whether these islands and ports will be renamed according to Indian Tradition and in doing so the names of the revolutionaries and martyrs who were imprisoned in the Andaman Cellular Jail will also be associated with the names of the Islands and ports of Andaman and Nicobar Islands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Several islands and ports in the Andaman and Nicobar Group of Islands have foreign-sounding names. It cannot be said that all these names are those of Britishers. Many of the names are apparently those of inanimate objects. There are also several unnamed islands.

(b) A list of names of the islands in the Andaman and Nicobar Group of Islands is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2346/69]. Many of the islands are un-named at present. The list of islands is also subject to modification as a result of progressive surveys. A list of names of prominent ports in the Andaman and Nicobar Islands laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2346/67].

(c) No, Sir.

(d) The local people in the Andaman and Nicobar Islands are opposed to any change of the existing names.

CHANGES IN SON-ET-LUMIERE DISPLAY AT RED FORT, DELHI

3673. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the promised changes in the Son-et-Lumiere displayed at Red Fort, Delhi have been made;

(b) if so, the nature of the changes made; and

(c) if not, the reasons for the delay, although the promise for changes was made in the House during the First Session of this Parliament ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). The script for performance is being revised so as to include Netajee's voice, 'kadam-kadam badhaye ja' and 'Vande Matram'. The opportunity is also being taken to introduce some other changes. The delay has been due to certain technical problems, as coordination between the script and the actual production requires careful and delicate processing to ensure that the quality of the performance is not impaired in any way.

STUDY TOURS SPONSORED BY US FOUNDATION WORKING IN INDIA

3674. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) how many persons were sent abroad during the last three years on study tours sponsored by each U.S. Foundation working in India;

(b) the names of such persons and the countries visited by them;

(c) which agency or agencies financed these study tours;

(d) the sources of finance for conducting the study tours; and

(e) the outcome of such tours ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) According to information made available by the three foundation, the statistics are as below :—

	U.S. Educational Foundation in India	Ford Foundation*	Rockefeller Foundation
1966-67	119	73	8
1967-68	96	128	2
1968-69	89	170	22

*The information relates to the calendar years 1966, 1967 and 1968.

(b) The statements are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2347/69].

(c) and (d). The U.S. Educational Foundation in India-travel grant from PL-480 Rupee Fund; Dollar support from American Universities/National Science Foundation/U.S. Govt. Ford Foundation : Awards are administered either directly by the Foundation or by the Institute of International Education in New York.

Rockefeller Foundation : Foundations own private sources.

(e) Such study tours have gone a long way towards the widening of the horizon of knowledge of persons in their respective fields.

I.C.S. OFFICERS IN ACTIVE SERVICE AND SUPER-ANNUATED OFFICERS

3675. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI MUHAMMAD ISMAIL :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of I.C.S. officers in active service;

(b) the name and designation of each officer in active service;

(c) how many of these officers are super-annuated;

(d) the name and designation of each super-annuated officer; and

(e) the policy of the Government in regard to I.C.S. officers on the issue of promotion, super-annuation, etc. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) At present there are 128 I.C.S. officers still in service out of whom 13 are seconded to Indian Foreign Service.

(b) The available information is given in statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2348/69].

(c) and (d). The information regarding superannuated I.C.S. Officers, who have been re-employed, is contained in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2348/69].

(e) All I.C.S. Officers are holding posts in super time-scale. Their further promotion is by selection based on merit with due regard to seniority. The rules governing the super-annuation of I.C.S. Officers are contained in Civil Service Regulation 565, which runs as follows.—

"565(a) After thirty five years' service counting from the date of his arrival in India, an officer shall not, except for special reasons, and with the sanction of the President, retain his office or be appointed to any new office : Provided that if such officer has held his office for less than five years, he may, for special reasons, with the sanction of the President be permitted to retain his office until he has held the office for five years."

CONDUCTING OF EXAMINATIONS IN M.A. AND LL.B. COURSES FOR PRIVATE STUDENTS BY CERTAIN UNIVERSITIES

3676. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Universities in India (like Vikram University) are conducting examination in M.A. and LL.B. courses for private students;

(b) whether Government are contemplating to allow certain other universities to conduct examinations for private students for M.A. and LL.B. courses also;

(c) if so, the names of those universities and the subjects proposed to be introduced in M.A. courses; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) A statement showing list of the examinations for which candidates are allowed to appear privately in different Universities is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2349/69].

(b) Universities are autonomous bodies and matters like examinations and courses of study fall exclusively within their jurisdiction. The question of Government of India allowing Universities to conduct examinations for private students, therefore, does not arise.

(c) and (d). Do not arise.

DEVELOPMENT OF ANDAMANS AND NICOBAR

3677. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the amount sanctioned during various plan periods for the development of Andaman & Nicobar Islands;

(b) the amount proposed to be spent during the Fourth Five Year Plan;

(c) whether the amounts sanctioned during the Third Plan period were not fully and properly utilised for the purpose for which they were allocated and were diverted to other purposes resulting in slow rate of progress; and

(d) if so, the reasons thereof and measures taken to avoid this during the Fourth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and

(b) The requisite information is as under :—

Plan period	Approved Outlay	Actual Expenditure
(in lakhs of rupees)		
(i) First Five Year Plan (1951-56)	328.80	82.50
(ii) Second Five Year Plan (1956-61)	603.14	364.87
(iii) Third Five Year Plan (1961-66)	979.32	636.20
(iv) Annual Plan (1966-67)	158.31	105.79
(v) Annual Plan (1967-68)	278.39	125.44
(vi) Annual Plan (1968-69)	251.00	211.96
(vii) Fourth Year Plan (1969-74)	1100.36	—

(c) and (d). The main reasons for short-fall in the Plan expenditure during the Third Five Year Plan were foreign exchange difficulties resulting in the non-procurement of two main-land island Ships etc., suspension of the colonisation scheme, partial implementation of housing schemes due to poor response from the public, non-availability of technical personnel and suitable contractors, transport difficulties in moving men and material from one island to another etc. and not due to diversion of Plan funds for other purposes. With a view to ensuring accelerated development of the islands, highest priority has been given in the Fourth Plan for development of transport and communication which includes acquisition of vessels for inter-island and mainland-island services, construction of roads, jetties etc. It is also proposed to construct Andaman Trunk Road to connect the main islands of the Great Andaman group of islands to facilitate easy movement of men and material from one island to another.

UNEARTHING OF NAXALITE HIDE-OUT IN SRIKAKULAM DISTRICT

3678. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Naxalite hide-out for manufacturing arms has been

unearthed by the police during combing operations at Paudara village in Srikakulam District;

(b) whether it is also a fact that the police seized a large number of guns, country-made bombs, gun-powder, explosives and other components used in the manufacture of bombs; and

(c) if so, the steps taken by Government to frustrate the nefarious designs of the naxalites ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information received from the state government, the police seized three guns, two country bombs, small quantities of gun-powder, explosives etc.

(c) Certain areas in Srikakulam, Khammam, Karimnagar and Warangal districts have been declared as disturbed areas under the Andhra Pradesh Suppression of Disturbances Act, 1948. Strong contingents of Andhra Pradesh Special Police and Central Reserve Police have been deployed in the area for dealing with violent activities of the extremists. The state government is also taking necessary steps to co-ordinate action with the neighbouring States.

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दूध के पाउडर की कथित बिक्री

3679. श्री मोल्हू, प्रसाद :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के गरीब बच्चों के लिये एक सामाजिक संगठन द्वारा दान में दिये गये दूध के 90,000 पौण्ड पाउडर को कुछ कर्मचारियों द्वारा बाजार में बेच दिये जाने के मामले की जांच कर रहा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को ब्यूरो का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस मामले की पहिले दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई थी और अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है।

सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए संस्कृत की शास्त्री उपाधि को मान्यता

3680. श्री यशवन्त सिंह कुशावाह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये संस्कृत में शास्त्री की उपाधि को मान्यता दे दी है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और क्या राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं के लिये राज्य सरकारों ने इस उपाधि को मान्यता दे दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). भारत सरकार ने, वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी की शास्त्री (अंग्रेजी सहित) डिग्री को केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजन के लिये बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान की है।

इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उपर्युक्त डिग्री को अपनी सेवाओं में भर्ती के लिये बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान की है।

जहाँ तक बिहार सरकार का सम्बंध है, उसने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व-

विद्यालय अथवा भूतपूर्व बिहार संस्कृत संघ की शास्त्री (अंग्रेजी सहित) को अपने अधीन रोजगार के प्रयोजनों के लिये आई० ए० अथवा बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान की है।

यमुना नदी के घूघटा घाट पर पुल का निर्माण

3681. श्री नाथू राम अहिरवार : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना नदी के घूघटा घाट पर अन्तर्राज्य पुल (जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा) के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुल के न होने के कारण इस डककू पॉण्डित क्षेत्र में डाकुओं को पकड़ने में दोनों राज्यों की पुलिस अपने आपको असमर्थ पा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि संचार साधनों की कमी के कारण इस अन्तर्राज्यीय क्षेत्र का विकास नहीं किया जा रहा है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र का विकास करने के लिये सरकार इस पुल के निर्माण के प्रस्ताव को चौथा पंचवर्षीय योजना में शामिल करेगी ?

संतद कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-मटल पर रख दी जायेगी।

(घ) योजना आयोग द्वारा हाल ही में अन्तर्राज्यीय सड़कों को ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता दिये जाने के निश्चय को दृष्टि में रखते हुए इस विषय में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के निर्माण आमंत्रित किये जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहिले सिर्फ सहायता अनुदान की प्रार्थना की थी।

TRAINING IN HOME GUARDS/CIVIL
DEFENCE

3682. SHRI K. ANIRUDHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of people trained in the different States for Home Guards/Civil Defence annually;

(b) the specific programme of Government in this respect; and

(c) the method of recruitment to this cadre ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Training of Home Guards and Civil Defence volunteers is a continuous process and no annual quota of training is fixed, nor it is possible to do so. The number of trained Home Guards and Civil Defence volunteers as on 30th September, 1969, was as follows :

Home Guards—5,21,063.

Civil Defence Volunteers—1,82,132.

(b) According to the present programme, it is proposed to have a total trained strength of 5,99,526 Home Guards and 4,41,400 Civil Defence volunteers. Training is imparted at town, district and State levels in each State. Advance training in Civil Defence is also imparted at the National Civil Defence College, Nagpur.

(c) Home Guards and Civil Defence are voluntary organisations open to all citizens. Those who fulfil the conditions in regard to age, physical fitness etc, as laid down in Home Guards and Civil Defence Acts, Rules and Regulations are eligible for recruitment.

DEVELOPMENT OF TOURIST CENTRES IN
KERALA

3683. SHRI MANGALATHUMADAM: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether at the recent meeting of the Tourist Development Council a decision has been taken to further develop the Tourist Centres in Kerala like Kovalam; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). No additional decisions on developing Kovalam were taken at the Tourist Development Council. It has already been decided to develop Kovalam as an international beach resort. Formal clearance to the total scheme has yet to be given by the Government but work is to start immediately on 20 beach cottages.

CHECKING OF UNFAIR PRACTICES INDULGED
IN BY TRAVEL AGENTS

3684. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no organisation in existence to supervise the unfair practices indulged in by the travel agents;

(b) whether it is also a fact that there is no licensing of travel agents although Government provide many facilities to them like foreign exchange, sanction of teleprinters, telephone connections and other promotional facilities;

(c) the number of cases of fraud, cheating and unfair practices that have come to the notice of Government on the part of travel agents during the last year; and

(d) the reasons why licensing system has not been introduced and an organisation created to supervise their work in the interest of the tourists ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). At present there is no licensing of travel agents by Government. The Department of Tourism, however, maintains a list of approved travel agents and this entitles them to obtain on a priority basis the concessions mentioned by the Hon'ble Member. Complaints against travel agents are enquired into through the field offices of the Department of Tourism. The Department also maintains liaison with the representative body of travel agents, viz., the Travel Agents Association of India. It is also proposed

to set up a Directorate of Inspection with Regional Offices to keep a closer watch on the working of travel agencies and other important segments of the tourist industry.

(c) Two cases of alleged unfair practices by two approved travel agencies came to the notice of Government last year and these are being enquired into.

(d) Legislation which would provide for licensing of travel agencies is under the consideration of Government.

a few of the leading hotels in the country have been successfully presenting programme of Indian music and dance specially choreographed for tourist appeal, and the Federation of Hotel & Restaurant Associations of India has been urged to encourage all its members to develop and present attractive forms of Indian cabaret. Efforts are also being made to organise entertainment programmes suitable for tourists at Delhi through private cultural organisations by giving them financial subsidy.

IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS MADE BY JHA COMMITTEE REGARDING ENTERTAINMENT FACILITIES FOR TOURISTS

3685. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jha Committee which was appointed to go into the question of entertainment facilities for tourists submitted its report in 1963 and made valuable suggestions;

(b) whether it is also a fact that no serious attention has been paid to the problem nor the recommendations of Jha Committee implemented; and

(c) what were the difficulties in the way of implementation of the recommendations and what attempts have been made to resolve those difficulties ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The recommendations made by the Jha Committee that Indian style entertainment of the lighter variety should be presented for the benefit of tourists, and that sound and light spectacles centred at historic sites, particularly in Delhi, have been accepted by Government. The sound and light spectacle at the Red Fort, Delhi, was mounted in early 1965 and has been running successfully. Two sound and light shows are being mounted at Sabarmati (Ahmedabad) and Shalimar Gardens (Srinagar). A provision of Rs. 40.00 lakhs has been made in the Fourth Five Year Plan for expenditure on providing entertainment facilities for tourists. As for light entertainment in hotels and restaurants,

EVALUATION OF ESSAY ANSWER BOOKS AND PROJECT REPORT OF NATIONAL SCIENCE TALENT SEARCH EXAMINATION

3686. SHRI P. ANTONY REDDY : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the essay answer books and project reports of the National Science Talent Search Examination of National Council of Educational Research and Training are all evaluated at Delhi only;

(b) if so, the reasons why they are not sent to examiners outside Delhi;

(c) whether it is also a fact that the essay answers and project reports of different subjects (Physics, Chemistry and Biology) are sent to a person who is specialized in one subject only; and

(d) if so, how is it possible for a person to evaluate correctly the answer books in subjects other than those of own specialization ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). No, Sir. In some cases where, in a given language the number of essay answer books and project reports to be examined were too few, these were examined by persons who, though specialized only in one Branch, possessed due competence in other Branches also. However, instructions have since been issued that in all cases, the essay answer books and project reports in different Branches should be examined only by those who have specialized in the respective Branches.

**PROFESSORS AND HEADS OF DEPARTMENTS
OF NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH AND TRAINING**

3687. SHRI P. ANTONY REDDY :
Will the Minister of EDUCATION AND
YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Professors and Heads of certain Departments of National Council of Educational Research and Training were found unsuitable by the 'Appointments Committee' after interviewing them, even though these persons were officiating in these posts for the past two or three years; and

(b) if so, the reasons why only some of these persons were asked to appear before the Interviewing Board while others were regularized ?

**THE MINISTER OF EDUCATION
AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R.
V. RAO) :** (a) Yes, Sir. One Professor and one Head of the Department whose posts were advertised were interviewed, along with others, and were found unsuitable.

(b) Out of the four posts of Professors, three posts were not advertised because they were substituted for the old posts of Deputy-Directors under the scheme of rationalization of scales of pay and designations which was adopted with effect from 1-11-1965 and under whose terms, all the three Deputy-Directors, who had been recruited after advertisement and interview were automatically given the scale of pay and designation of a Professor. The fourth post had to be advertised because the person officiating against, it was a Field Adviser whose post had been equated, under the scheme of rationalization of scales of pay and designations with that of a Reader.

Out of the 13 posts of Heads of Departments, 9 were not advertised because these were substituted for the old posts of Directors under the scheme of rationalization of scales of pay and designations and under whose terms all the old Directors automatically became the Heads of Departments. Three more posts were also not advertised because they were held by pro-

fessors whose scale of pay was Rs. 1100—1600 which is the same as that of the Heads of Departments. One post had to be advertised because it was held, on an *ad-hoc* basis, by a person on deputation.

**TEXT BOOKS IN PHYSICS, CHEMISTRY AND
MATHEMATICS PUBLISHED BY NATIONAL
COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND
TRAINING**

3688. SHRI P. ANTONY REDDY :
Will the Minister of EDUCATION AND
YOUTH SERVICES be pleased to state
whether the text books in Physics, Chemis-
try and Mathematics published by the
Department of Science Education of
National Council of Educational Research
and Training are actually written by the
officers of the Department or are adopted
from the Russian text books ?

**THE MINISTER OF EDUCATION
AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R.
V. RAO) :** The text-books in Physics,
Chemistry and Mathematics published by
the Department of Science Education of
the National Council of Educational Re-
search and Training are not adaptations of
Russian text-books. They have been
written by the officers of the Council with
the assistance of Unesco experts.

**RECRUITMENT IN NATIONAL COUNCIL OF
EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING**

3689. SHRI P. ANTONY REDDY :
Will the Minister of EDUCATION AND
YOUTH SERVICES be pleased to state
whether Government are contemplating
recruitment of class I and II posts in the
National Council of Educational Research
and Training by the Union Public Service
Commission in view of the general dis-
satisfaction about the working of the
Council ?

**THE MINISTER OF EDUCATION
AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R.
V. RAO) :** No, Sir. No dissatisfaction
about the working of their Appointments
Committee has come to notice of the
National Council of Education Research
and Training.

इलैक्ट्रॉनिक्स की शिक्षा

3690. श्री महाराज सिंह भारती: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रॉनिक्स के सामान की बढ़ती हुई मांग तथा भाभा समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रॉनिक्स की शिक्षा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितने व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ हो जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव): (क) और (ख). लगभग 670 विद्यार्थियों के वार्षिक दाखिले के लिये 21 इंजीनियरी संस्थाओं में इलैक्ट्रॉनिक्स और रेडियो इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उत्तर स्नातक स्तर पर उच्च प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये, लगभग 100 विद्यार्थियों के वार्षिक दाखिले के लिये 10 केन्द्रों में सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। 21 पालिटैक्निक लगभग 600 विद्यार्थियों के वार्षिक दाखिले के लिये रेडियो इंजीनियरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं।

मामले की निरन्तर जांच की जा रही है और इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिये तकनीकी कर्मचारियों की मांग के आधार पर, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।

इन संस्थाओं में वर्तमान दाखिले के अनुसार, चौथी आयोजना की अवधि के दौरान लगभग 25,000 अतिरिक्त स्नातक इंजीनियर, मास्टर्स डिग्री वाले 500 विशेषज्ञ और लगभग 2,000 डिप्लोमाधारी उपलब्ध होंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नौवहन सम्बन्धी आवश्यकताएँ

3691. श्री महाराज सिंह भारती : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत में कितने जहाज बनाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) उनसे और विदेशों से खरीदे जाने वाले जहाजों द्वारा पूरी होने वाली देश की नौवहन की आवश्यकताओं की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) भारतीय जहाजों की कमी के कारण हमारा कितने प्रतिशत वैदेशिक व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा किया जाता है ?

संसद् काय विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम की चौथी योजना काल में लगभग 21 समुद्रपार जहाजों को बनाने की संभावना है। वाणिज्य सम्बन्धी जहाजों की संख्या जो माजागों डाक और गार्डन रीच वर्कशाप उसी अवधि में बनाएगा, अभी विचाराधीन है।

(ख) चौथी योजना में भारतीय शिपयार्डों में बनाये जाने वाले जहाजों के कुल अभिग्रहण की कोई विशेष प्रतिशतता निश्चित नहीं की गई है लेकिन उनकी जहाज निर्माण क्षमता, वर्तमान और प्रत्याशित दोनों पर बाहर से जहाजों के आदेश देने से पहले पूरा विचार किया जाता है।

(ग) चौथी योजना के अन्त तक, भारतीय जहाजों का देश के समुद्र पार के व्यापार को लगभग 40 प्र० श० ले जाने की सम्भावना है। शेष 60 प्र० श० विदेशी जहाजों द्वारा ले जाया जायेगा परन्तु इसमें से 10 प्र० श० भारतीय जहाजों के कमी के कारण है क्योंकि

आयात/निर्यात मास के ले जाने के मामले में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय तल में ऐसे मास का लगभग 50 प्र० श० के बहन से अभिप्राय है ।

UNIFORM CONDITIONS REGARDING ADMISSION OF STUDENTS IN UNIVERSITIES AND ADMISSION IN DELHI COLLEGES AND DELHI UNIVERSITY

3692. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no uniform conditions of admission in Colleges;

(b) if so, whether Government propose to make uniform conditions of admission in each University;

(c) what are the conditions of admission for B.A. (Pass), B.Sc. and B.A. (Honours) and B.Com. students in the colleges of Delhi University, Agra University, Calcutta University and Allahabad University;

(d) How many students in Delhi were denied admission in Delhi Colleges and Delhi University in different courses of degree and post-degree classes in the last 3 years; and

(e) whether Government could give assurance that no student will be denied admission in the Delhi Colleges and Delhi University in the next year ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir. The conditions for admission depend upon the particular University to which the college is affiliated.

(b) Government of India has no power to lay down uniform conditions of admission in each University.

(c) and (d). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(e) The Central Government is not in a position to give such an assurance as the matter primarily concerns the Delhi Administration and the University and is also subject to availability of resources.

नासिक के निफाद नगर में हरिजनों की हत्या

3693. श्री शिव चरण लाल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अक्तूबर, 1969 को गांधी जन्म शताब्दी के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाद नगर में दो हरिजनों की हत्या की गई थी;

(ख) क्या हत्यारों को पकड़ लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस घटना का पूरा व्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 1 अक्तूबर, 1969 को नासिक के निफाद तालुक में रावलास गांव में दो भाइयों की हत्या की गई थी। वे हरिजन थे। छः अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप-पत्र दे दिये गये हैं। मामला न्यायाधीन है।

AGREEMENT REGARDING "CHANDIGARH-YALE PROJECT FOR RESEARCH OF EARLY HOMONIDS"

3694. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether in August, 1967, the Department of Anthropology of Punjab University and the Peabody Museum of Yale (U.S.A.) University concluded an agreement to work on the Project known as "Chandigarh-Yale Project for the research of early homonoids";

(b) if so, whether the attention of Government has been drawn to a news-item published in "Patriot" dated the 21st October, 1969, under the caption "India's work on early homonoids—U.S. Scientists attempt to steel laurels"; and

(c) if so, the reaction of Government to the same ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): (a) The Punjab University, Chandigarh entered into collaboration with the Peabody Museum of Yale University, USA, regarding research on 'Early homonoids'. The project was approved by the Government of India in October, 1967.

(b) Yes, Sir.

(c) According to the information furnished by the Punjab University, there is nothing on record to show that such an attempt was made.

सांता क्रुज हवाई अड्डे के निकट एक विमान-शाला (हंगर) का निर्माण

3695. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरीदे जाने वाले विमानों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये सांता क्रुज हवाई अड्डा बम्बई के निकट एक विशाल विमानशाला बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके आकार और किस्म का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर-इंडिया की बोइंग-747 विमानों के लिये एक हंगर के निर्माण की योजना है। इंडियन एयरलाइन्स बम्बई हवाई अड्डे पर एक केन्द्रीय एनेक्सी सहित दो हंगरों का निर्माण कर रही है। ये हंगर 300 फीट × 200 फीट के होंगे और केन्द्रीय एनेक्सी 300 फीट × 90 फीट की होगी।

(ग) एयर-इंडिया के हंगर के निर्माण पर लगभग 55 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है, जबकि इंडियन एयरलाइन्स के दो हंगरों की लागत का अनुमान 122 लाख रुपये है।

(घ) हंगरों का उपयोग विमानों के ओवरहालिंग और संधारण के लिये किया जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद को समाप्त करना

3696. श्री शिवकुमार शास्त्री : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्व-विद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राध्यापक के पद के लिए अनुभव सम्बन्धी कोई शर्त नहीं होगी;

(ग) क्या इस परिवर्तन के कारण कुछ सहायक प्राध्यापकों को कार्य मुक्त कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उनको दूसरा कौनसा रोजगार देने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) से (घ). विश्वविद्यालय अथवा कालेजों में सहायक प्राध्यापकों के कोई पद सुस्थित नहीं हैं। किन्तु, प्राध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर, व्यक्तियों को प्राध्यापकों के पदों पर अस्थायी तौर पर सहायक प्राध्यापकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 1 नवम्बर, 1969 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया था कि विश्वविद्यालय के विभागों और कालिजों में प्राध्यापकों के पदों पर सहायक प्राध्यापकों

के रूप में नियुक्ति की वर्तमान प्रथा को, तत्काल बन्द किया जाना चाहिए। परिषद ने, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को बन्द करने के निर्णय से उत्पन्न विभिन्न मामलों की जांच, विश्लेषण और सिफारिशें करने के हेतु तथा साथ ही निर्णय पर अमल करने के लिये उपाय सुझाने के वास्ते एक कार्यकारी दल भी नियुक्त किया है। कार्यकारी दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

ABOLITION OF CONTRACT LABOUR SYSTEM IN SHIPPING CORPORATION OF INDIA

3697. SHRI N. SREEKANTAN NAIR : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether contract labour system in the Shipping Corporation of India is proposed to be abolished; and

(b) if so, when ?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND SHIPPING AND
TRANSPORT (SHRI RAGHU
RAMAIAH) : (a) and (b). The Shipping
Corporation of India Limited do not
employ any contract labour as a rule. How-
ever, all Indian Shipping companies in-
cluding the Shipping Corporation enter into
contracts for various ships jobs in ports
like stevedoring, chipping and painting etc.
by inviting tenders from licensed contrac-
tors and for these jobs, contractors utilise
dock labour registered with dock labour
boards at wages prescribed by concerned
official authorities. The Shipping Corpora-
tion do not employ such dock labour.
Hence the question of abolition of contract
labour system in the Corporation does not
arise.

कटिहार बिहार में प्रजा-समाजवादी दल के
सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज

3698. श्री लखन लाल कपूर : क्या
गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या यह सच है कि बिहार
राज्य के पूर्णिया जिले में कटिहार न्यायालय
के अदालत में प्रजा-समाजवादी दल के तत्वावधान

में बाढ़-राहत तथा चकबन्दी के लिए आन्दोलन
कर रहे सत्याग्रहियों पर 31 अक्टूबर
तथा 1, 3 और 13 नवम्बर को स्थानीय
पुलिस ने बुरी तरह लाठी चार्ज किया और
उनको जूतों से मारा जिसके परिणामस्वरूप
बहुत से सत्याग्रहियों की हालत गम्भीर है;
और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार
द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री
के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख).
राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे
हैं।

**VISIT BY MINISTER OF STATE FOR INFOR-
MATION AND BROADCASTING TO ALIGARH
MUSLIM UNIVERSITY**

3699. SHRI BENI SHANKER
SHARMA : Will the Minister of EDUCA-
TION AND YOUTH SERVICES be
pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister
of State for Information and Broadcasting
was invited by the Aligarh Muslim Univer-
sity to lay the foundation stone of a
Gandhi Hall in the said university in Octo-
ber last;

(b) whether it is also a fact that he had
to return therefrom without performing the
ceremony;

(c) if so, whether Government agree
that a miniature Rabat was re-enacted
there; and

(d) what steps, if any, he has taken to
heal the wounds of insult inflicted not only
on Shri Gujral but also on the Government
and the people of India ?

THE MINISTER OF EDUCATION
AND YOUTH SERVICES (DR.
V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The
Minister of State for Information and
Broadcasting was invited by Aligarh Mus-
lim University to inaugurate the Gandhi
Centenary Commemoration meeting on
October 2, 1969. He was given a very warm
welcome by the students and the authori-
ties of the Aligarh Muslim University.

(c) and (d). Do not arise.

ARRANGEMENTS FOR TRANSLATION IN
VARIOUS MINISTRIES

3700. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the arrangements so far made by the various Ministries/Departments for translation work arising from the enforcement of the Official Languages (Amendment) Act, 1967;

(b) whether adequate staff for the purpose, as suggested in the programme for 1968-69 of his Ministry, has since been provided; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). Some nucleus translation staff exists in almost all the Ministries/Departments. Efforts have been made to augment this staff keeping in view the increased workload. At present in 15 Ministries/Departments, the translation staff now available with them is considered adequate. In the remaining Ministries/Departments, proposals to sanction additional translation staff are being processed. In the Ministry of Home Affairs, adequate translation staff have been appointed to meet the present requirements.

(c) This is a continuing process and as the translation work increases, steps are being initiated to further increase this staff.

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

3701. श्री राम चरण :

श्री शिव चरण लाल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन दिल्ली के शिक्षा विभाग में उप-प्रधानाचार्यों, प्रधानाचार्यों, उप-

शिक्षा अधिकारियों, विज्ञान परामर्श-दाताओं और टेलीविजन अधिकारियों के पृथक-पृथक कितने पद हैं ;

(ख) उक्त पदों पर अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

CIVIL LIST OF GRADE IV ASSISTANTS

3702. SHRI RAM CHARAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new civil list of Grade IV Assistants has been prepared;

(b) if so, whether the names of more than three hundred persons have been added to the list and these persons have been made senior to those persons whose names were already in the civil list of 1961; and

(c) if so, the effect of adding these names on the seniority of others and the reasons for doing so?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

JOINT CADRE OF MINISTRIES OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

3703. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether cadre of the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development and the Ministry of Supply is the same;

(b) the reasons why the cadre of the Ministry of Supply is with the Department of Works and Housing when it is a separate Ministry and the cadre of the Department of Urban Development is separate when it is a part of the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development;

(c) whether this is affecting the promotion of the staff; and

(d) if so, whether any steps are being taken by Government to protect the affected staff and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Pending reconstitution of cadres, consequent on the last reorganisation of Ministries, the old cadres *viz.*, (i) Ministry of Health, Family Planning and Urban Development and (ii) Ministry of Works, Housing & Supply are continuing.

(c) and (d). Disparities in promotions are inevitable in a decentralised set up. However, in order to minimise such disparities the C.S.S./C.S.S.S./C.S.C.S. Rules have been amended recently to provide for promotions being made in the decentralised grades only within certain 'zones' to be prescribed by Ministry of Home Affairs.

REPORT OF COMMITTEE ON INLAND WATER TRANSPORT

3704. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bhagwati Committee on Inland Water Transport has submitted its report; and

(b) if so, when and the main recommendations made by the Committee ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

DEVELOPMENT OF SMALLER AIRPORTS IN DARBHANGA DISTRICT

3705. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have any plans for developing smaller airports like Bhowara (in Darbhanga District of Bihar), so that they can be inter-linked with other services of the Indian Airlines;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Indian Airlines have no proposal to introduce scheduled air services to these places.

RUNNING OF SCHOOLS IN TENTS BY DELHI ADMINISTRATION

3706. SHRI N. R. DEOGHARE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the total number of Schools run at present by the Delhi Administration;

(b) how many of these are housed in buildings and how many in tents;

(c) the dates since when these schools have been functioning in tents; and

(d) the action being taken to house these schools in proper buildings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) 278 Government Higher Secondary Schools.

(b) 246 schools in Buildings and 32 in purely tented accommodation. However, in 63 buildings, under occupation of 97 Government schools, tents are being used to meet the shortage of the built-up accommodation.

- (c) 1956-57—2 schools
 1958-59—1 school
 1961-62—1 school
 1962-63—3 schools
 1963-64—2 schools
 1964-65—5 schools
 1965-66—6 schools
 1966-67—1 school
 1967-68—7 schools
 1968-69—2 schools
 1969-70—2 schools

Total : 32 schools

(d) According to the information supplied by the Delhi Administration, 14 schools will be housed in buildings, which are under construction. 12 schools will be housed in buildings for which sanctions regarding construction of buildings have been issued during 1969-70. 2 schools are expected to be housed in a building, which is to be vacated by a College in 2/3 months time, 4 schools will be housed in buildings when sites, which are under acquisition, become available for construction purposes.

In regard to the tents in 63 buildings, referred to in reply against part (b) above, these tents are now being replaced under a crash programme by constructing *pucca* additional rooms and Tubular Truss Structures. The tents in these schools are likely to be removed by the end of 1970.

APPOINTMENT OF DIRECTOR/ASST. DIRECTOR FOR NATIONAL MUSEUM, NEW DELHI

3707. SHRI N. R. DEOGHARE :
 SHRI YASHPAL SINGH :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Museum at New Delhi is without a Director or an Assistant Director for over a year and the work there has been at a stand still;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action Government propose to take in this regard and to attend to such important items of work which have not been attended to during the year ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) to (c). The National Museum is without a Director since January 1969 and without an Assistant Director also since July, 1969, but the work there is not at a stand still. Efforts are being made to fill up these posts as early as possible and important items of work in the Museum are being attended to by the other staff in the Museum with the help of the Ministry, wherever necessary.

AIR SERVICE BETWEEN INDIA AND CEYLON

3709. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken or are proposed to be taken to improve the air services between Ceylon and India; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). Yes, Sir. Effective from November 1969, Indian Airlines have replaced viscounts with Caravelle aircraft on the Madras-Colombo-Madras route. Additionally, the frequency of HS-748 service on the route Trivandrum-Colombo-Trivandrum has been increased from once-weekly to twice-weekly.

सरकारी क्षेत्र में नए होटल की स्थापना

3710. श्री ओंकार सिंह: क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में निकट भविष्य में और कितने होटल खोलने का प्रस्ताव है और उन पर कितना धन व्यय होगा ?

पर्यटन तथा अतंनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): चौथी पंचवर्षीय योजना में सार्व-जनिक क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बेंगलोर, श्रीनगर, गुलमर्ग, दमदम हवाई अड्डा (कलकत्ता) जयपुर, औरंगाबाद, उदयपुर (सक्ष्मी विलास पैलेस होटल का विस्तार) और कोवालम (होटल और 40 पर्यटक कुटीरों) में होटलों के निर्माण के लिये 6.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बेंगलोर में होटल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है तथा इसके 150 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जून 1970 तक पूरा हो जाने की आशा है।

एयर इंडिया भी बम्बई में सांताक्रुज और जूहतर पर क्रमशः 100 लाख और 300 लाख रूपयों की अनुमानित लागत से दो होटलों के निर्माण की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

SCHEME FOR AWARD OF PRIZES, TO AUTHORS WRITING BOOKS IN INDIAN LANGUAGES

3711. SHRI N. R. LASKAR :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI R. BARUA :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have instituted a scheme for award of prizes to authors for writing books in any Indian language;

(b) if so, the main features of this scheme; and

(c) when it is likely to be introduced ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. L.T-2350/69.]

(c) It has been introduced from the current financial year i.e. 1969-70 and the first awards will be announced towards the end of this year.

CONFERENCE OF INTERNATIONAL HOTEL ASSOCIATION HELD IN NEW DELHI

3712. SHRI N. R. LASKAR :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI R. BARUA :
SHRI HIMATSINGKA :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of International Hotel Association was held in New Delhi on the 4th November, 1969;

(b) if so, how many countries were represented in the conference;

(c) what were the subjects discussed; and

(d) the decisions arrived at ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. A Meeting of the Council of Administration of the International Hotel Association was held in New Delhi from November 4 to 6, 1969.

(b) It is understood from the Federation of Hotel & Restaurant Associations of India who were host to the Association that 16 countries including India were represented in the Meeting.

(c) and (d). Copy of a Press Note issued at the end of the Meeting is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2351/69.]

CONSTRUCTION OF A MOTEL AT CHANDIGARH

3713. SHRI N. R. LASKAR :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI R. BARUA :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a motel costing Rs. 10 lakhs is likely to be constructed in Chandigarh soon for the tourists;

(b) if so, whether a team of experts of the Central Government has visited the site;

(c) whether the team has submitted its report; and

(d) if so, when the final decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). The Chandigarh Administration has suggested the construction of a Motel at Chandigarh at an estimated cost of Rs. 5 lakhs. In September, 1969, an officer of the Department of Tourism and an officer of the India Tourism Development Corporation were shown two alternative sites for the location of the proposed Motel when they happened to be in Chandigarh for some other discussions with the representatives of the Government of Haryana.

(d) A decision will be taken after a feasibility study has been made.

बिहार में हरिजनों को भूमि का वितरण

3714. श्री राम सेवक यादव: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरिजनों आदि के लिए आवास की व्यवस्था करने हेतु भूमि के वितरण की मांग के समर्थन में महात्मा गांधी जन्म शताब्दी दिवस से बिहार में चलाये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त आन्दोलन का व्यौरा क्या है; और

(ग) आन्दोलनकारियों की मांगों को पूरा करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एल० रामास्वामी) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

RIOTS IN SOPORE IN JAMMU AND KASHMIR

3715. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that literature calculated to provoke disturbances was distributed two days before the Sopore riots in Jammu and Kashmir on the 20th August, 1969;

(b) whether Naxalities' hand was suspected in the incidents;

(c) whether it is a fact that literature purported to have been distributed contained a pamphlet published in Lahore and gave details of how Arab Commandos began the Palestine liberation campaign and that 1000 Commandos on the Palestine liberation model were needed to liberate Kashmir; and

(d) whether any inquiries have been made into the incidents and if so, with what results and the action proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). Information is awaited from the Jammu and Kashmir Government and will be laid on the Table of the House.

YOUTH UNREST

3716. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state : .

(a) whether his Ministry has expressed serious concern with the law and order aspect of youth unrest and the upward trend in student agitations, in a note on the recent study in the matter;

(b) whether his Ministry has also proposed to expedite its examination of the do's and don'ts set by the 1966 conference of Inspectors-General of Police, keeping the Education Ministry in the picture;

(c) if so, the action taken in the matter so far; and

(d) what steps are proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) In a note circulated to the Members of Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs on an item of youth unrest included in the agenda for the meeting held on October 8, 1969, mention was made of certain disturbing trends.

(b) to (d). Recommendations of the conference of Inspectors-General of Police have been forwarded to all the State Governments, since it was for the State Governments to take suitable action on these recommendations relating to public order. The comments of the University Grants Commission have also been sought through the Ministry of Education, so that the State Governments could be apprised of the views of the University Grants Commission.

MEASURES AGAINST SENAS

3717. SHRI BENI SHANKER

SHARMA :

SHRI RAMAVATAR SHASTRI :

SHRI K. M. MADHUKAR :

SHRI JAGESHWAR YADAV :

SHRI BHOGENDR JHA :

SHRI C. JANARDHANAN :

SHRI K. HALDER :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Central Government have forwarded to the State Governments the recommendations of the National Integration Council that 'stern and effective measures should be taken against various senas that are provoking disturbances by appealing to regional sentiments of people', for appropriate action;

(b) the reaction of the various State Governments thereto; and

(c) the steps proposed to be taken by the State Governments in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). State Governments have intimated that a close watch is being kept on the activities of such organisations and appropriate action under law would be taken whenever necessary.

REDESIGNATION OF CHIEF COMMISSIONERS OF MANIPUR AND TRIPURA AS LT. GOVERNORS

3718. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have decided re-designate the Chief Commissioners of Union Territories of Manipur and Tripura as Lt. Governors; and

(b) if so, what will be the advantages by this change ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) There has been persistent local demand that these territories which have special problems, should also have mature and experienced persons as their administrators like territories of Himachal Pradesh, Goa and Pondicherry. The change not only satisfies genuine and strong local sentiment but enlarges the field of choice to select suitable and senior persons as administrators.

अपराधों की रोकथाम

3719. श्री प० ला० बारूपाल :

श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में अपराधों की रोकथाम के लिए एक विस्तृत योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपराध प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान् । चूंकि अपराधों का नियंत्रण तथा रोक-थाम राज्यों का उत्तरदायित्व है, अतः राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में अपराधों की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई करती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1964 से 1968 तक देश में सूचित किये गये भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रज्ञेय अपराधों की संख्या तथा प्रगति लाख जन संख्या में अपराध की मात्रा दिखलाई गई है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष	कुल प्रज्ञेय अपराध	प्रति लाख जनसंख्या में अपराध की मात्रा
1964	759013	159.6
1965	751615	154.4
1966	794733	159.4
1967	881981	172.5
1968	*862602	164.6

दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरियों में वृद्धि

3720. श्री ओंकार लाल बेरवा: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कारों, स्कूटरों तथा अन्य मोटरगाड़ियों की चोरी के मामलों की संख्या में बराबर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कारों तथा स्कूटरों की चोरी के पृथक पृथक कितने मामले हुए;

(ग) कितने मामलों में चोरी का पता लगाया गया; और

(घ) चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कारों, स्कूटरों और अन्य वाहनों की चोरी की घटनाओं और पता लगाये गये ऐसे मामलों की संख्या को दिखाने हुए एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [घन्यलय में रखा दिया गया । देखिये संख्या LT—2352/69]

(घ) ऐसे अपराधों को रोकने हेतु निगरानी रखने के लिए प्रभावित इलाकों में पुलिस गश्त को तेजी से बढ़ाया गया है । महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में तथा बर्दों में पुलिस कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है । ज्ञात कार उठाने वालों तथा चोरों की क्रिया-कलापों पर निगरानी रखी जा रही है ।

EXCAVATIONS OF PURANA QILA IN NEW DELHI

3721. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have finalised plans for the excavations of Purana Qila in New Delhi;

(b) if so, the purpose thereof;

(c) the expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) the likely effect of the excavations on this ancient monument ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH): (a) No, Sir. The plans have yet to be finalised.

*यह संख्या त्रैमासिक अपराध पत्रिका पर आधारित है और अनन्तिम है ।

(b) Excavations are being undertaken to establish the antiquity of the site. Purana Qila is popularly believed to represent the traditional City of Indraprastha associated with the Mahabharat story.

(c) The total estimated cost has not yet been worked out; but the expenditure for about three months field season is estimated to about Rs. 60,000/-.

(d) The excavation proposed to be undertaken in the area is quite distant from the standing monuments and therefore no adverse effect is likely to be caused to them.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विनियम

3722. श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 आदिवासी जातियों के संरक्षण के अपने उद्देश्य में असफल रहा है और अब यह आवश्यक है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उक्त विनियम को समाप्त करने का है; और

(ग) उक्त विनियम के लागू होने के पूर्व तथा पश्चात् अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ईसाइयों की संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1951 की जनगणना के अनुसार अन्दमान व निकोबार द्वीप में ईसाइयों की कुल संख्या 9,494 थी और 1961 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल संख्या 17,973 है ।

दिल्ली में व्यायाम प्रशिक्षण शिक्षकों के वेतन-मानों का नियमित किया जाना

3724. श्री रामावतार शर्मा :

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

श्री नरदेव स्नातक :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1950 से 1959 तक नियुक्त किये गये सभी व्यायाम प्रशिक्षण शिक्षकों के वेतनमान शिक्षा मंत्रालय के 17 जून 1954 के पत्र संख्या एफ० 6-32/54-एच० 2, द्वारा उनकी बर्हताओं के अनुसार नियत किये गये थे और उनकी शिक्षा निदेशक दिल्ली के 31 जनवरी, 1961 को लिखे शिक्षा मंत्रालय के पत्र द्वारा नियमित किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने 1 अप्रैल, 1950 से 31 दिसम्बर, 1959 के दौरान सभी इन्टरमीडिएट पास व्यायाम प्रशिक्षण शिक्षकों को भेजे गये शिक्षा मंत्रालय के उपरोक्त पत्रों के अनुसार 17 जून, 1959 से अथवा उनकी नियुक्ति की तिथि से 100-250 रुपये (पुनरी-क्षित) 160-300 का वेतनमान दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

GRANTS TO RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH, DEOGHAR, (BIHAR)

3725. SHRI B. K. MODAK :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the amount of grants or aid given

to Ramakrishna Mission Vidyapith, Deo-ghar, Bihar, during the last three years;

(b) whether the functioning of this Vidyapith has been commented upon in the Audit Reports; and

(c) if so, the details thereof and action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) Under the scheme of Assistance to Voluntary Educational Organisations working in the field of School Education, the following grants were sanctioned to this Vidyapith :—

	Rs.
1966-67.	70,665.00
1967-67.	—
1968-69.	52,014.00

(b) The Ministry have no information about any comments in the Audit Reports of the Vidyapith regarding its functioning. The grants-in-aid released by the Ministry as mentioned at (a) have been utilized by the Vidyapith properly.

(c) Does not arise.

RECALL OF CENTRAL RESERVE POLICE FROM NORTH LAKHIMPUR

3726. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an entire Company of the Central Reserve Police based on North Lakhimpur in Upper Assam has been moved out of the town on Friday the 21st November, 1969;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken against those responsible for the accidental raid on a number of houses without provocation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The CRP camp at North Lakhimpur was closed down after some incidents on the 14th November, 1969 there reportedly involving some CRP personnel and civilians.

(b) This was ordered with a view to avoiding any tension and misunderstanding between the CRP personnel and the civilians.

(c) Two criminal cases have been registered with the local police by some people of the locality against the CRP personnel and one case against some civilians by the Commandant of the CRP. The matter is under investigation and further action will be taken on completion of the same.

CONSTRUCTION OF NATIONAL HIGHWAY No. 12

3727. SHRI NITIRAJ SINGH CHOUHDARY : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the total allotment made during this year and proposed to made for the next year for construction of National Highway No. 12.

(b) the amount out of the above allotment likely to be spent;

(c) the date when funds were placed at the disposal of the State Government for being spent for construction of this Highway; and

(d) when this highway is likely to be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (d). Out of Rs. 16.14 lakhs provided for original works on National Highways No. 12 for 1969-70, a sum of Rs. 6.94 lakhs has been allotted in August, 1969. It is proposed to make allotment from the balance amount available after consulting the State Government. It is, therefore, premature to indicate the amount likely to be spent during the current year. Until the budget for 1970-71 is passed, no allotment for the next year can be made. Subject to availability of funds, the present expectation is that the construction of missing links on National Highway No. 12 is likely to be completed in the Fourth Plan period.

निर्घनों तथा हरिजनों के लिए बिहार में खोले गये स्कूल

3728. श्री केदार पस्वान: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में निर्घनों तथा हरिजनों के लिए कुल कितने स्कूल खोले गये और प्रत्येक जिले में कितने कितने स्कूल खोले गये और क्या सरकार का विचार इन स्कूलों में हरिजनों के लिये कोई सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ये सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

FORMER CHIEF JUSTICES OF INDIA ASSOCIATED WITH COMMITTEES/COMMISSIONS

3729. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5302 on 29th August, 1969 regarding the former Chief Justice of India associated with Committees/Commissions and state :

(a) whether the required information from all State Governments and the various Ministries and offices of the Government of India has been received;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the information as made available is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2353/69].

(c) Does not arise.

SALE AND PURCHASE OF PLANES TO AND FROM PRIVATE PARTIES

3731. SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI E. K. NAYANAR :
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of planes bought from the Private parties during the last 3 years;

(b) the number of planes sold to private parties during this period; and

(c) the method adopted for the sale, with details ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) No such purchase has been made by the Government of India.

(b) During the same period, 6 aircraft were sold to private parties, two Dakotas by Indian Airlines, 3 Pushpaks by Hindustan Aeronautics Ltd. and one Auster aircraft by the Plant Protection Directorate.

(c) The sale of Pushpak aircraft was made on the basis of delivery ex-factory, Bangalore Division, against pre-quoted and accepted fixed price, and deliveries were made against prior payments.

Indian Airlines offered the aircraft for sale by advertising in the leading newspapers in the country.

The Auster aircraft belonging to the Plant Protection Directorate was sold through the Director General of Supplies and Disposals who invited global tenders for this purpose.

MONEY SPENT ON INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NEW DELHI

3732. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI E. K. NAYANAR :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) how much money has been spent so far on the Indian Institute of Technology, New Delhi;

(b) how much money has been spent on the construction of its building and when the same was completed; and

(c) whether it is a fact that big cracks have appeared in the building due to sub-standard materials used and bad workmanship?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): (a) and (b). The expenditure on land and its development, buildings and equipment up to the end of October, 1969 is Rs. 717.15 lakhs (including foreign aid for equipment). The expenditure incurred on buildings is Rs. 408.98 lakhs.

Different buildings were completed at different times during the period 1961-62 to 1968-69. Some buildings are still under construction.

(c) No, Sir.

जैसलमेर हवाई अड्डा

3733. श्री ओंकार लाल बेरवा: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि जैसलमेर में निमित्त हवाई अड्डे के मानचित्र पाकिस्तान समर्थक कुछ तत्वों द्वारा पाकिस्तान के सुपुर्द किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक ने, जो जैसलमेर में जुलाई, 1969 में गिरफ्तार किया गया, एक अन्य व्यक्ति को फंसाते हुए एक बयान दिया। उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसलमेर के हवाई अड्डे के मानचित्रों को पाकिस्तान को देने के बारे में आरोप जांच के दौरान सिद्ध नहीं हुए हैं।

DRESS REGULATIONS FOR MINISTERS GOING ABROAD

3734. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have prescribed any dress regulations for Central Government Ministers who go on tour abroad;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of Ministers together with their names who did not observe dress regulations during their tour abroad during 1969;

(d) if the reply to part (a) be in the negative the reasons for not prescribing the same when there is a national dress for India; and

(e) the steps taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) No such regulations have been prescribed by Government.

(b) and (c). Do not arise.

(d) and (e). In India there is a great variety of dress which is natural considering the variety of climate. Government have not, therefore, issued any orders prescribing any particular type of dress as the national dress for India. However, in order to foster the maintenance of correct standards, instructions recommending the use of certain types of dress by the officials on formal or ceremonial occasions and in offices were issued in 1954. It is open to the Minister to follow these instructions and it is not considered necessary to prescribe any rigid regulations in this behalf.

DISPLAY OF BANNERS AT PALAM AIRPORT IN CONNECTION WITH THE REQUISITIONED MEETING OF A.I.C.C.

3735. SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI RABI RAY :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards the complaint of Shri H. V.

Kamath that display of banners in support of the Requisitioned Meeting of A.I.C.C. was allowed at the Palam Airport;

(b) if so, whether any permission was sought for and given; and

(c) whether similar facilities were allowed in the past to political parties?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). No such complaint has been received in my Ministry. On the 18th November, 1969, the Secretary, Accommodation Committee, Requisitioned Meeting of AICC Members (Delhi Session) requested the Aerodrome Officer, New Delhi, for permission to put up a Reception Office inside the compound of Palam Airport. Permission was granted for a Reception Counter in the Arrival Hall to enable the Committee Members to identify individuals. A desk insignia was also allowed on the Counter. Banners in support of the Requisitioned Meeting of the AICC were not displayed within the Delhi Airport area.

(c) I am not aware of any request made in the past by political parties for permission to display banners within the Airport area. The facilities mentioned in reply to parts (a) & (b) of the question have, however, been allowed for various other organisations and conferences.

SEIZURE OF CONFIDENTIAL PAPERS AT SAFDARJUNG AIRPORT

3736. SHRI SHARDA NAND : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a confidential file of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, relating to the circulars and official instructions as well as postal delivery Zones was seized by the R.M.S. authorities at Safdarjung Airport from a postal bag, which was going to Pakistan, a few years ago;

(b) whether an enquiry in the matter was held; and

(c) if so, the action taken by Government against the officer responsible for this national offence?

L42LSS/69-5

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

SETTING UP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN SCHEDULED CASTE AREAS OF MANIPUR

3737. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the educational institutions so far set up in the Scheduled Caste areas of Manipur, namely Andro village, Sekmai, Khurkhum and Pheiyeng;

(b) whether it is a fact that in the village of Andro inhabited by at least 8,000 people, there is no High School; and

(c) if so, the steps taken to meet the educational backwardness in Andro and other scheduled caste areas of Manipur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DASHAN) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the Manipur Administration and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

MURDER OF COLLIERY WORKERS OF DHANBAD COAL FIELD

3738. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Ram Deo Singh, a C.P.I. (M) worker of Dhanbad Coalfield was murdered on the 18th September, 1969 at Madhuband Colliery while announcing the meeting to be addressed by Shri Mohammad Ismail, M.P., from a jeep;

(b) if so, how many persons were arrested by the Police;

(c) names and particulars of the persons arrested; and

(d) full details of the investigation conducted by the Police in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (d). According to information received from the State Government, some CPM workers were making announcements, during the night of September 18, 1969 in a jeep, about a meeting to be held next day at Nadkharkhi Colliery. When the jeep came near the Madhuban Colliery, about 25 persons suddenly attacked and killed one Ramdeo Singh. The Police registered a case and arrested five persons, including the Assistant Manager of Madhuban Colliery. The investigation of the case is in progress. The names of the arrested persons are being ascertained from the State Government.

REPORT OF SEMINAR ON CRIMINAL LAW AND CONTEMPORARY SOCIAL CHANGES

3739. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 836 on 25th July, 1969, regarding compensation to victims of crime and state:

(a) whether the report of the Seminar on Criminal Law and Contemporary Social Changes has been received by Government;

(b) if so, the particular steps taken by Government to provide for compensation to victims of crime; and

(c) whether other recommendations of the Seminar have been considered and if so, the nature of decision taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The report of the Seminar is under examination by the Government.

MEMORIALS FOR FREEDOM FIGHTERS IN ANDAMANS

3740. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have finalised a scheme for setting up memorials for the freedom fighters in Andamans; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). It has already been decided to preserve the Central Tower and the existing three wings of the Cellular Jail at Port Blair as a national monument. The details in this regard are being worked out. Marble plaques containing the names of the freedom fighters who were incarcerated in the Cellular Jail, have already been put up in the Central Tower of the jail.

It has also been decided to erect a memorial for Netaji Subhas Chandra Bose at Port Blair. The details in this regard are also being worked out.

ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT

3741. SHRI N. R. DEOGHARE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is wide-spread feeling in the country for the abolition of capital punishment; and

(b) if so, whether Government are considering any proposal to abolish capital punishment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). The Law Commission have given mature consideration to the question of abolition of capital punishment and submitted their recommendations in their Thirty-Fifth Report. The Report is still underprint. The Law Commission are in favour of retention of capital punishment in the present state of the country. The recommendations of the Law Commission on the question of abolition of capital punishment would have to be examined by the Government of India in consultation with the State Governments, before any final view is taken.

राज्यों के बीच सामान के लाने-ले-जाने पर लगाई जाने वाली ङुगी समाप्त करना

3742. श्री देव राव पाटिल: क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री 28 मार्च, 1969 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में लाई गई वस्तुओं

पर चुंगी तथा ऐसे अन्य शुल्कों को समाप्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से कोई पत्र-व्यवहार किया है और चुंगी के बदले अन्य शुल्क लगाने के संबंध में उनसे सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विभिन्न वस्तुओं पर जिसमें खाद्यान्न शामिल है, चुंगी हटा दी गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इक़बाल सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) जिन राज्यों में चुंगी ली जाती है उनमें से अभी तक किसी भी राज्य में चुंगी नहीं तोड़ी है सिवाय आंध्र प्रदेश के जहां तेलंगाना क्षेत्र में 1-4-65 से चुंगी बन्द कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में गंडक नदी पर पुल

3743. श्री विभूति मिश्र : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन जिले (बिहार) में गंडक नदी पर पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार इस पुल के निर्माण के लिये धन उपलब्ध कराने में हिचक रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इक़बाल सिंह): (क) ठेकेदार के द्वारा कुएँ देरी से खोदने के कारण प्रगति धीमी रही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मोतिहारी, चम्पारन (बिहार) में बरसात के दिनों में यातायात बन्द होना

3744. श्री विभूति मिश्र : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन जिले के तीन मुख्य पुलिस स्टेशनों तथा घोरा सावन, ढाका तथा पतासी से जिला मुख्यालय मोतिहारी-चम्पारन को सूखे के दिनों में और विशेषतः बरसात के दिनों में सिक्राहना नदी के कारण यातायात बन्द रहता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिक्राहना नदी पर लालबेगिया घाट तथा मधुवनी घाट पर पुल बनाने का है ?

संसद-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित कि जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-मटल पर रख दिया जायेगा ।

MOBILE EXHIBITIONS OF MUSEUMS FOR RURAL PEOPLE

3745. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government propose to give financial assistance to the State Governments if they undertake to establish mobile exhibitions of museums for the benefit of rural people, and

(b) if so, the terms on which such assistance would be offered ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) No, Sir. There is no such scheme.

(b) Does not arise.

QUESTION REGARDING PROVISION OF FACILITIES TO LEADERS OF OPPOSITION PARTIES IN PARLIAMENT

3746. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to give certain facilities to Leaders of Opposition Parties in the Lok Sabha and Rajya Sabha, as is prevalent in certain foreign countries and in certain State Legislatures; and

(b) if so, by what time a decision would be announced ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). The matter is under consideration.

PROMOTION OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND TRIBES

3747. SHRI KIKAR SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of candidates, year-wise Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others, separately, promoted through each Departmental Examination to which reservation was applicable (Examination, 1965—1963) with reasons for shortfall, if any, in the number of Scheduled Castes;

(b) whether the distribution in any year was changed if so, the court decision thereon;

(c) whether Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates of 1963 Examination better qualified than many non-Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates already promoted were ignored and also about 90 per cent Reserved vacancies of last three Examinations, were dereserved; if so, reasons therefor;

(d) whether there are any representations complaining of injustice to the qualified Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates of 1963 Examination; and

(e) if so, the particulars thereof and how do Government propose to undo the injustice done to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2354/69].

इंडियन एयर लाइंस को क्षेत्रीय उड़ानों में घाटा

3748. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या पर्यटन तथा, सैनिक उड़्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइंस की क्षेत्रीय उड़ानों में घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1968 में कितना घाटा हुआ तथा 1969 में कितना घाटा होने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय उड़ानों की उपेक्षा की जाती है इसलिये उनमें सभी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती या उनमें कुप्रबन्ध रहता है जिसके परिणाम स्वरूप यात्री इन उड़ानों के लिये आकर्षित नहीं होते ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह निश्चय करेगी कि सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड़्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1967-68 और 1968-69 के दौरान क्षेत्रीय मार्गों पर क्रमशः 603.00 लाख रुपये और 577.00 लाख रुपये का घाटा था । परन्तु, उन घाटों की अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर हुए लाभ से पूति हो गयी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) क्षेत्रीय उड़ानों पर अधिक ऊंचे किरायों से यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । पूर्वी क्षेत्र में किराये संचार के अन्य साधनों के अपर्याप्त होने के कारण जानबूझ कर कम रखे गये हैं ।

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा घेराव को एक बुराई के रूप में शामिल करने से इन्कार करना

3749. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक संघ विधेयक पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने घेराव को एक बुराई के रूप में शामिल करने से इन्कार कर दिया था और अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार न तो कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन के दौरान और न ही सामान्य विचार-विमर्श के दौरान राज्य श्रम मंत्री के भाषण में घेराव का कोई उल्लेख किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बच्चों का अपहरण

3750. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसा देशव्यापी गिरोह है जो बच्चों का अपहरण करता है और उनके अंग-भंग करके उन्हें भिक्षा मांगने के लिए बाध्य करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगस्त 1969 में जम्मू तथा काश्मीर और बम्बई में ऐसे गिरोहों के कब्जे से लगभग 200 ऐसे बच्चे बरामद किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों में काम कर रहे ऐसे गिरोहों को नष्ट करने तथा उनके चुंगल से बच्चों को छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या कायवाही की है ;

(घ) यदि ऐसी कोई कार्यवाही की गई है तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) सभी राज्य सरकारों (असम, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि ऐसा देशव्यापी गिरोह उनके ध्यान में नहीं आया है जो बच्चों का अपहरण करता है और उनके अंग भंग करके उन्हें भिक्षा मांगने के लिए बाध्य करता है । असम, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जम्मू और काश्मीर तथा महाराष्ट्र सरकारों ने सूचित किया है कि उनके द्वारा ऐसी कोई बरामगी नहीं की गई है । तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 6 और 7 अगस्त, 1969 की बीच की रात को ग्रेटर बम्बई पुलिस द्वारा संचालित एक विशेष अभियान में 296 बच्चों को ढूँढ निकाला गया । बच्चे बिगाड़े हुए अथवा भागे हुए थे जिन्होंने अकम्प्यता तथा भिक्षा का जीवन अपना रखा था ।

(ग) से (ङ). भिक्षा के लिए बच्चों के अपहरण की समस्या को एक जघन्य अपराध समझा जाता है । इस अपराध के दमन के लिए राज्यों की समन्वित कार्रवाई हेतु राज्यों के खुफिया पुलिस के उप-महानिरीक्षकों के सम्मेलनों में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ है और ऐसे मामलों में कारागार जांच-पड़ताल करने के लिए राज्यों द्वारा अनेक प्रक्रिया सम्बन्धी उपाय किये गये हैं ।

इस अपराध के लिए कड़ा दण्ड देने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 तथा 363-क के संशोधन का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ।

कलकत्ता से डिब्रूगढ़ जाने वाले रिवर
स्टीम नैवीगेशन कंपनी के स्टीमर

3751. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिवर स्टीम नैवीगेशन कंपनी 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष से पहले कलकत्ता से डिब्रूगढ़ के लिये कुल कितने स्टीमर चलाया करती थी;

(ख) उनमें से कितने स्टीमर पाकिस्तान द्वारा रोक लिये गये थे;

(ग) शेष स्टीमर इस समय कहां पर लंगर डाले पड़े हुये हैं और वे किस हालत में है ;

(घ) उन पर सरकार द्वारा प्रतिमास कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) पाकिस्तान के वर्तमान रवैये को ध्यान मे रखते हुये इन स्टीमरों के संबन्ध में सरकार का क्या निर्णय करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) 60 स्टीमर और 104 पत्ती ।

(ख) 15 मुख्य नहर स्टीमर, 32 पत्ती, 4 बन्द पड़े स्टीमर और 3 नाव ।

(ग) शेष स्टीमर आंशिकरूप से आसाम में और आंशिकरूप से कलकत्ता में विछिन्न हैं । पुराने स्टीमर जिनकी भरम्मत महंगी पड़ रही है रद्द माने गये हैं ।

(घ) कोई व्यय सीधे सरकार द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि जहाज सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारेपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्व में है ।

(ङ) कलकत्ता में जहाजों का उपयोग माल बोट के कार्य में, त्रिवेणी और हल्दिया के बीच रेत के प्रचलन में और यात्री नावों

के रूप में किया जा रहा है । आसाम में विछिन्न जहाजों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है कि किस तरीके से वे उपयोग किये जायें ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का अभाव

3752. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तथा प्रगति इसलिये नहीं हो पा रही है कि वहां सड़कें नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को क्या प्रोत्साहन दिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये राज्य सरकारों को किसी प्रकार की सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है?

संसद-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) से (घ). ग्रामीण सड़कों का ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में कड़ा महत्व है इस बात को पूर्ण मान्यता प्राप्त है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इन सड़कों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है । तथापि सारी सड़कों (राष्ट्रीय राज मार्गों को छोड़कर) जिन में ग्रामीण सड़के भी शामिल है, की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वे चौथी योजना में सड़कों के लिये अपने कुल निवेश का 25 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के लिये चौथी योजना में आवंटित करने के लिये सहमत हो गयी है । चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सड़कों के लिये उद्दीष्ट केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि योजना के अंतर्गत राज्य-योजना स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता "ब्लाक" ऋण और "ब्लाक" अनुदानों के रूप में होगी ।

MODIFICATION OF CIVIL SERVICE RULES

3753. SHRI S. D. SOMASUNDARAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government would modify the age old Civil Service Rules adopted from Britishers so that the officers with commendable record of service are not denied opportunities for promotion in the name of quota rule when one becomes eligible, as announced by the Prime Minister on the eve of the winter session;

(b) if so, the date by which the recruitment rules are likely to be modified; and

(c) the reasons for the delay in taking such action ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). Rules for recruitment to various Central Civil Services/posts under the Government of India are framed under Article 309 of the Constitution. These rules contain provision, *inter alia*, for the method/methods of filling up the posts in the particular Service. Depending upon the requirements of each Service, one or more methods of appointment thereto are laid down in such rules, e.g. direct recruitment, promotion, deputation, etc. Where, therefore, the recruitment rules of a Service lay down a quota for promotion and also another quota for direct recruitment, the intention is that by the process of direct recruitment, there should be infusion of fresh blood in the interest of the efficiency of the Service. In view of this position, the question of any amendment to the existing recruitment rules providing for filling up of all the posts by promotion only does not arise.

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय,
पटना के कर्मचारी संघ की मांगें

3754. श्री भोगेन्द्र झा : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय

कर्मचारी संघ पटना ने संघ को मान्यता प्रदान करने, बिना विलम्ब यातायात सेवाएं चालू करने, संयुक्त संवर्ग बनाने, अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तित करने, वर्कशाप कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें स्थायी घोषित करने की अपनी कुछ मांगें अधिकारियों के समक्ष रखी है; और

(ख) यदि हां, तो उन की मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). कर्मचारी संघ की मांगें 3 श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं :—

- (1) संघ की मान्यता ।
- (2) यातायात सेवाओं का पुनः स्थापन और
- (3) कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले । इन मांगों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

(1) संघ की मान्यता : किसी भी संघ को मान्यता देने का प्रश्न अनुशासन के निहित संहिता के स्वीकृति के एक वर्ष की समाप्ति पर ही विचार किया जा सकता है प्रश्न गत संघ को अभी संहिता की अपनी स्वीकृति भेजनी है इसने कुछ आधारित सूचना कागजात भी नहीं भेजे हैं ।

(2) यातायात सेवाओं का पुनः स्थापन : अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति एक पटना और बक्सर और दूसरी भागलपुर और कारागोला के बीच बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत गंगा में नदी सेवाओं का पुनर्स्थापन के लिये दो योजनाओं पर पहले ही विचार कर रही है । इस संबंध में और कार्यवाही समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर की जा सकती है ।

(3) कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले : इन पर संबंधित मंत्रालय से परामर्श करने की जांच की जा रही है ।

CURBING OF INDISCIPLINE AMONG POLITICIANS, TEACHERS, STUDENTS AND WORKERS

3755. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that highly responsible and progressive leaders of our country are critical of indiscipline among the politicians, teachers, students and workers and it is being apprehended that a stage has reached when if indiscipline is not curbed in time, it might destroy our democratic way of life; and

(b) whether Government would appoint a high power national commission to enquire into the different problems of indiscipline and to suggest ways and means to discourage and if possible, to punish indiscipline, if it reaches a certain stage ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Such opinions are also brought to the notice of Government.

(b) No such proposal is under consideration.

दिल्ली में सरकारी बस्तियों में गुंडों का आतंक

3756. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस की निष्क्रियता परम सीमा पर पहुंच गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में अधिकतर बाहरी गुंडों का व्यापक आतंक है और ये गुंडे लोगों को ज्यादातर दिन में आतंकित करते हैं और कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य उनसे भयभीत हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सेवा नगर में इन गुंडों का सब से ज्यादा आतंक है और उनमें से अधिकतर गुंडे इस बस्ती के वासी

नहीं है और उनके अधिकांश संरक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये गुंडे रात्रि स्कूलों तथा कालिजों से लौट रहे छात्रों को घेरते हैं और उन्हें छोड़ते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस आतंक को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली पुलिस को ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है ।

(ग) से (ङ) : सेवा नगर के इलाके में लोगो ने असन्तोष व्यक्त किया है । पुलिस आवश्यक निरोधक और अन्य कानूनी उपाय काम में लाती है और ऐसे इलाकों में तेजी से गश्त लगाती है । पुलिस को हिदायत दे दी गई है कि सेवा नगर इलाके में कड़ी निगरानी रखें ।

सितम्बर, 1969 में बम्बई पत्तन के गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3757. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर में बम्बई पत्तन के गोदी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के कारण कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या उनकी मांगों को जिन्हें इतने समय बाद पूरा किया गया है, इसी प्रकार से पहले पूरा नहीं किया जा सकता था ?

संसदकाय विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकाबाल सिंह) : (क) और (ख). बंबई में पत्तन कार्यकर्त्ताओं के कुछ तबके द्वारा कार्य के कुछ सांकेतिक रोक के अलावा सितम्बर 1969 में कोई हड़ताल नहीं हुई ।

गढ़वाल जिले में हवाई अड्डा

3758. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश का गढ़वाल जिला सामरिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां के संसत्सदस्य श्री भक्त दर्शन ने उस क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वह गढ़वाल में एक हवाई अड्डा निर्मित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या गढ़वाल को भी काश्मीर तथा कुमाऊं के समान ही आधुनिक बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पर्यटक गढ़वाल जाते हैं यदि हां, तो क्या उन्हें परिवहन संबंधी अनेक कठिनाइयों का समना करना पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री :
(डा० कर्ण सिंह) : (क) गढ़वाल के लिये योजनायें बनाते समय सरकार उसके सामरिक (स्ट्रैटेजिक) महत्व को उचित रूप से ध्यान में रखती है ।

(ख) सरकार को श्री भक्त दर्शन, संसद् सदस्य, द्वारा दिये गये किसी ऐसे आश्वासन की जानकारी नहीं है । इंडियन एयरलाइन्स का गढ़वाल के लिये विमान सेवाएं प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) राज्य सरकार की चौथी पंच-वर्षीय योजना में गढ़वाल में पोडी, बिनसर, श्रीनगर और नौगढ़ में पर्यटक बंगलों के तथा रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में तीर्थयात्रियों के लिये शालाओं (शैड्स) के निर्माण की व्यवस्था है ।

(घ) और (ङ). यद्यपि विदेशी पर्यटकों का कोई खासा मातायात नहीं है, तथापि गढ़वाल क्षेत्र में स्थित धार्मिक केन्द्रों को देखने के लिये भारतीय तीर्थ-यात्री एक बड़ी भारी संख्या में वहां आते हैं ।

मोटर चलाये जाने योग्य मार्गों द्वारा जुड़े हुए स्थानों अर्थात् बद्रीनाथ, गुप्तकाशी (केदारनाथ के लिये), गंगानी (यमुनोत्ती के लिये) शाला (गंगोत्री के लिये) पर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हैं, यद्यपि इन सेवाओं में सुधार और विस्तार की गुंजाइश है ।

ATTACK ON ANAND MARG DHARMA-CHAKRA

3759. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dharma Chakra at Anand Marg was attacked by C.P. (M) men at Cooch-Bihar, West Bengal recently and one follower of Anand Marg was brutally killed and 19 others were seriously injured in broad day light before many people;

(b) whether the religious head of Anand Marg and 30 others followers of Anand Marg were arrested and none of the assistants was apprehended; and

(c) if so, details about such incidents and the steps taken by Government to protect such religious organisation and its head and principal followers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). According to the report furnished by the Government of West Bengal the Anandmargis held a three day conference at Cooch-Bihar without obtaining permission. The local people objected to the followers of the Anand Marg carrying daggers and other weapons and held demonstration in front of the venue of the Conference on 28-8-1969. This was resented by the Anandmargis and a clash ensued resulting in injuries to 20 persons including Anandmargis, a few members of the public and a few police-men. One of the Anandmargis died later in the hospital. Shri Ahand Murti,

the head of Anand Marg, and 28 others were taken into police custody. Three cases have been registered under section 147/148/149/153A IPC and certain provisions of Indian Explosives Act.

The courts of law are already seized of the matter.

CONSTRUCTION OF AERODROME AT HOSPET IN MYSORE STATE

3760. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the stage at which the proposal for the construction of an aerodrome at Hospet near Hampi Ruins at Ginigera on the left side of Tungabhadra Dam in Mysore State is pending;

(b) the final estimated amount and the time by which the construction is likely to be started; and

(c) whether it is a fact that Government of Mysore have also recommended for construction of the said aerodrome at Hospet?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) and (b). The estimate for the construction of an aerodrome at Hospet has been recast and now amounts approximately to Rs. 40.18 lakhs. A provision for this could not be made in the Fourth Plan due to shortage of funds, but the question of financing the project from the Civil Aviation Development Fund is under examination.

(c) The proposal has been initiated at the instance of the Department of Tourism.

PROTECTED MONUMENTS IN MYSORE STATE

3761. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) what are the Protected Monuments in Bellary, Raichur and Dharwar Districts of Mysore State directly under the Union Government;

(b) whether it is a fact that very important architectural monuments at

Gadag in Dharwar District are maintained very badly and are without any Chowkidars to look after them;

(c) whether it is also a fact that there are some absentee Chowkidars at Lakkundi and Gadag of Dharwar District of Mysore State drawing their salaries sitting in their native places; and

(d) whether the encroachments in Kumbareswar temple at Lakkundi in Dharwar District have been removed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH): (a) A list of centrally protected monuments in Bellary, Raichur and Dharwar Districts of Mysore State is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2355/69].

(b) No, Sir. Though there is no Chowkidar, the monuments at Gadag are well preserved.

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir.

CONSTRUCTION OF APPROACH ROADS LEADING TO ASHOKAN INSCRIPTIONS AT MALIMALLESWAR

3762. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposed approach road construction leading to Ashokan inscriptions at Malimalleswar near Koppal in Raichur District of Mysore has not been completed and whatever portion is constructed is not properly maintained; and

(b) if so, what action is being taken to complete the construction of the approach road right up to the Inscriptions, and for its maintenance?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH): (a) and (b). It is presumed that the reference is to two Ashokan inscriptions situated on Palkigere

and Gavimath hillocks at Kopbal. If so, the approach roads leading to these inscriptions are outside the protected limits and as such the Archaeological Survey of India has no jurisdiction over them. The construction and maintenance of these approach roads is the responsibility of the State Government.

CONSTRUCTION OF A FIVE STAR HOTEL BUILDING AT BANGALORE

3763. SHRI S. A. AGADI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the construction of the Five Star Hotel building at Bangalore is complete;

(b) if not, the reasons for the slow progress; and

(c) the total estimated cost of the building and when the Hotel is likely to be started ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) No, Sir. The Hotel is still under construction.

(b) and (c). The plans of the Hotel were revised with a view to improving its functional efficiency, which caused some delay. The project is likely to be completed in 1970 at a total estimated cost of Rs. 150 lakhs.

INCREASE IN SALARIES OF PRIMARY AND HIGHER SECONDARY TEACHERS

3764. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering to increase the salaries of the Primary and Higher Secondary teachers in the country;

(b) if so, whether this matter has been taken up with the States; and

(c) if so, the reaction of the State Governments thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (c). No such proposal is under the consideration of the Government of India. Since school education is the responsibility of the States, it is for them to consider any such steps. The recommendations of the Education Commission about the revision of salary scales of school teachers were forwarded to State Governments for their consideration and implementation. Some of the States have already implemented them also.

CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICES (U. D. GRADE) EXAMINATION

3765. SHRI YOGENDRA SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Secretariat Clerical Services (U. D. Grade) Examination proposed to be held in December, 1966 was cancelled on the demand of the Central Government Clerks Union;

(b) whether there is a proposal to hold this examination in December, 1969;

(c) if so, whether Government have received a memorandum from the Central Government Clerks' Union requesting the Government to cancel the examination;

(d) whether Members of Parliament have also made a similar demand; and

(e) In the larger interest of the Service matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). Yes, Sir.

(e) In the larger interest of the Service as a whole and in the interest of efficiency, it was decided to hold the examination in accordance with the rules.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भागलपुर (बिहार) की एक फर्म के कार्य को जांच

3766. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले दिनांक 31 अगस्त, 1969

के हिन्दी दैनिक "आर्यवर्त" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो भागलपुर की उस फर्म के कार्य की जांच कर रहा है जिसने बिहार बिजली बोर्ड से लगभग 14 लाख 80 हजार रुपये प्राप्त किये परन्तु बिजली के जिस सामान की सप्लाई के लिए यह धन राशि प्राप्त की गई वह सामान, बिजली बोर्ड का ही था; और

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का क्या नाम है तथा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने 31 अगस्त, 1969 के "आर्यवर्त" नामक समाचार पत्र में "पीने दो करोड़ के आयकर की चोरी का रहस्योद्घाटन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार देखा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भागलपुर की किसी फर्म से सम्बन्धित कथित आयकर अपवचन के किसी मामले में जांच पड़ताल नहीं कर रहा है। किन्तु, केन्द्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न सौदों से सम्बन्धित उन मामलों की जांच कर रहा है जिन में विद्युत कार्य विभाग, बिहार के कर्मचारी अन्तर्गत्त हैं। इन मामलों में अब तक की गई जांच-पड़ताल के दौरान भागलपुर की कोई फर्म नोटिस में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

TERM OF DELHI MUNICIPAL CORPORATION

3767. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the term of the present Municipal Corporation of Delhi expires on 1971;

(b) whether Government propose to extend the term by one year to hold elections simultaneously with the general elections; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) No such proposal is under consideration.

(c) So far no case has been made out to justify such a postponement.

SMUGGLED FIRE-ARMS IN WEST BENGAL

3768. SHRIMATI ILA PAL CHOU-DHURI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have recently received information to the effect that some organised groups of some political parties in West Bengal have been supplied with a large stock of smuggled fire-arms including guns, double-barrel rifles, revolvers and grenades and carrying out their violent and subversive activities and thus to create chaos in the country and endanger the interest, security and integrity of the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken to trace the groups who are reported to be receiving arms etc. and with what results;

(d) whether Government have succeeded in getting to know the source of supply of the arms etc.; and

(e) if so, the details thereof and steps taken to prevent such smuggling of arms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No such information has been received.

(b) to (e). Do not arise.

ESTABLISHMENT OF A CENTRE FOR JAPANESE STUDENTS IN DELHI UNIVERSITY

3770. SHRIMATI ILA PAL CHOU-DHURI : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been arrived at between the Governments of India and Japan for establish-

ing a Centre for Japanese studies in the University of Delhi;

(b) if so, broad details of the agreement together with its financial implications so far as they may effect India;

(c) whether such Centres will also be opened in other principal towns of India viz., Calcutta, Bombay and Madras; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) The principal object of the Centre is to encourage the people of India in the academic study of Japanese affairs and culture as well as the Japanese language. The Government of Japan will provide the teaching staff and necessary educational materials for the Centre until such time as the local teaching staff is able to take full responsibility for the courses.

The Government of India will provide the Japanese teaching staff the privileges and facilities as are accorded to experts under Colombo Plan (Statement attached). The University of Delhi will give them the title of Visiting Professors/Lecturers and accord other privileges as are given to teachers of similar rank in the University.

(c) and (d). No such proposal is under consideration.

Statement

Privileges and Facilities to be accorded to the members of Japanese Teaching staff :

A. Exemption of Income Tax on the remittances of Japanese Teaching Staff's salaries from Japan.

B. Duty-free import of the following articles, subject to the execution of the usual certificate of undertaking by the Japanese Teaching Staff.

1. One personal automobile or motor-cycle;
2. One radio or radio gramophone;
3. One refrigerator and/or home freezer.
4. Two air-conditioners;
5. Minor electrical accessories and appliances; and

6. Professional equipment and gadgets.

C. Duty-free import of certain consumer articles (foods, drugs, medicines, liquor, tobacco, books and periodicals, toilet articles etc.) up to the following monetary ceilings :

1. Rs. 4,500 (Rupees four thousand and five hundred only) per year, if single; and
2. Rs. 7,500 (Rupees seven thousand and five hundred only) per year, in case of those with families (irrespective of number of children).

The members of the Japanese teaching staff shall have the privileges of importing above mentioned articles, on the same conditions accorded to the experts under the Colombo Plan.

LEGISLATION ON ARCHIVES

3771. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no archival law in India;

(b) whether it is also a fact that an expert committee had recommended the imperative necessity of such a law;

(c) if so, the reasons why the necessary legislation has not been brought before the Parliament during the last nine years;

(d) whether Government propose to bring a Bill before a Parliament in the near future; and

(e) if so, when, if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) to (e). Government regret the delay that has occurred in this matter. Apart from examining the legal, constitutional, financial and administrative implications and consulting the State Governments,

Ministries/Departments of the Central Government and statutory and other bodies concerned which is a time consuming process, Government have been considering the question of providing in advance concurrent facilities to meet the obligations which the proposed Archival Legislation will impose on the National Archives of India. Every effort will be made to bring the Bill before the Parliament as early as possible.

SHIPPING DEVELOPMENT FUND

3772. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a Shipping Development Fund from which financial assistance is given to Indian Shipping Companies;

(b) if so, what are the terms and conditions for the grant of financial assistance, the extent to which the assistance is given;

(c) whether it is also a fact that this Fund has practically remained unutilised and almost no applications have been received;

(d) if so, the reasons for it and steps taken by Government to remove the obstacles which stand in the way of parties getting the assistance; and

(e) if not, the number of applications received during 1967-68 and 1968-69 and the amounts that were advanced ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). Yes, Sir. The important terms and conditions on which the loans are sanctioned by the Shipping Development Fund Committee for purchase of ships are as follows :—

(i) The maximum quantum of loan is 90% of the price in the case of new vessels (95% in the case of vessels built at Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam) and 75% of the price in the case of second hand vessels.

(ii) The maximum period of amortisation of the loan is 18 years in the case of loans for new vessels and 3/4ths of the residual income-tax life in the case of second-hand vessels (full income-tax life being 20 years). An initial period of moratorium of two years is admissible if asked for by the borrower companies (in the case of vessels built at H.S.L., the maximum period of amortisation in 19 years with a moratorium of 3 years).

(iii) The loans carry interest at 8% p.a. but if payments of interest and repayments of principal are made by prescribed due dates, the rate of interest is reduced to 3% per annum only.

(iv) The security for the loans is given in most cases by the mortgage of ships and in other cases by acceptable guarantees from financial institutions.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) 17 applications were received during 1967-68 and 10 during 1968-69. An amount of Rs. 1373.32 lakhs was advanced during 1967-68 and an amount of Rs. 1971.04 lakhs during 1968-69.

असम सड़क के निर्माण में प्रगति

3773. श्री राम सेवक यादव : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाश्र्वं सड़क परियोजना के अधीन बनाई जा रही असम सड़क के निर्माण की क्या प्रगति है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में इस सड़क का निर्माण—कार्य रुक गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और कार्य को कब तक पुनः आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है !

संसद्कार्य विभाग और नौबहन मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री इकवाल सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय बरेली-अमीनगांव पार्श्व सड़क से है। 23 बड़े पुलों, 129 मध्यम पुलों और 153 छोटे पुलों में से 16 बड़े पुल, 40 मध्यम पुल और 45 छोटे पुल पूरे हो गये हैं। 873 मील लम्बी सड़कों में से 103 मील लम्बी सड़कें पूरी हो गई हैं। शेष मील दूरी पर तथा पुलों पर प्रगति विभिन्न प्रावस्थाओं पर काम चालू है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ANTI-INDIA SLOGANS IN KERALA

3774. SHRI N. SHIVAPPA :

SHRI NARAYAN SWAROOP SHARMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some anti-Indian and ProPakistani slogans were raised by some persons in January, 1969 in Kerala; and

(b) if so, steps taken by Government to prevent such anti-Indian activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) According to information received from the Government of Kerala no such slogans were raised in Kerala State in January, 1969.

(b) Does not arise.

DURGAPUR FIRING

3775. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the D.I.G. of Intelligence Department has stated in his report about the Durgapur firing that the police constables had gone out of control;

(b) whether it is also a fact that Police entered the Engineering College and indulged in acts of sabotage; and

(c) if so, the details of the report and the reaction of the Government of India in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The state government have reported that the entire matter had been inquired into by a retired High Court Judge, Shri T. P. Mukherji. His report has been published by the state government in the official gazette for general information, on 31st July, 1969.

आनन्द मार्ग के साधुओं और सन्यासियों पर हमले

3776. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि पश्चिम बंगाल के उग्रवादी वामपंथी साम्यवादी ने आनन्द मार्ग के साधुओं और सन्यासियों को राज्य से बाहर निकालने के उद्देश्य से उन पर शस्त्रास्त्रों से हमले करने आरम्भ कर दिये हैं तथा ऐसे अनेक सन्यासियों को चोटें आई ह;

(ख) तत्संबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन साधुओं और सन्यासियों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उनके रक्षा के लिये उचित उपाय किये जायें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि कूच-बिहार की घटनाओं के सम्बन्ध में आज लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 7529 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पहलगांव तथा अमरनाथ के बीच एक सड़क का निर्माण

3777. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पहलगांव (काश्मीर) तथा अमरनाथ के बीच एक पक्की सड़क बनाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हर साल पहलगांव से अमरनाथ जाने वाले लाखों यात्रियों को कम असुविधा हो ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सरकार प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने की इच्छुक है। पहलगांव से चन्दनवाडी तक जीप चलने योग्य एक सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका है। परन्तु चन्दनवाडी से आगे मंदिर तक के भूप्रदेश की चढ़ाई बड़ी तेज व सीधी है और एक उचित प्रकार की सड़क का निर्माण करना कठिन होगा। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये एक अश्व-पथ का उचित दशा में संघारण किया जा रहा है।

लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनाने की मांग

3778. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेह लद्दाख के बांदा संघ की संघर्ष समिति ने भारत सरकार को यह सूचना दी है कि उन्होंने लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनवाने की अपनी मांग को मनवाने के लिए एक आन्दोलन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में, राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। इस संबंध में 1 अगस्त, 1969 को इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 271 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

PROVISION OF ALTIMETER SETTINGS IN AIRCRAFTS

3779. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) what is the minimum information required by an aircraft for landing and take off;

(b) whether altimeter setting by means of pressure variations are provided in the aircrafts;

(c) whether numerous accidents have occurred due to faulty altimeter settings;

(d) whether Panagarh airfield and Chakulia airfield which are diversionary or alternative airfields for Dum Dum have not been provided with altimeter setting for pilots;

(e) if so, the reasons therefor; and

(f) whether there have been representations in this regard and if so, the steps taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) The minimum information required is :—

- (i) Altimeter setting (QNH) for take off and landing,
 - (ii) Airfield pressure (QFE) for landing,
 - (iii) Surface wind,
 - (iv) Surface temperature,
 - (v) Humidity,
 - (vi) Horizontal visibility (Runway Visibility Range),
 - (vii) Cloud base, amount and type of clouds,
 - (viii) Serviceability of runway with regard to water-logging, snow, blockage, runway lights, etc.
- (b) Yes, Sir.

(c) Some accidents in various parts of the world have been attributed to faulty altimeter settings.

(d) and (e). Pressure values have been provided at Panagarh. Arrangements for Chakulia are also being made.

(f) Yes, Sir. Representations in this regard were made by the Indian Commercial Pilots Association and Indian Airlines. The steps taken are indicated in the reply to parts (d) and (e) above.

AGREEMENT FOR PURCHASE OF SHIPS FROM GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

3780. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recently entered into an agreement with the German Democratic Republic for the purchase of ships from that country;

(b) if so the details thereof;

(c) the expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) whether Government have taken steps to assist the Indian ship-building industry simultaneously by acquiring indigenous ships ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c). No agreement has been concluded between the Government of India and the Government of German Democratic Republic for the purchase of ships from that country. However, during the current financial year contracts have been entered into by two Indian shipping companies with a Shipyard in the German Democratic Republic for the construction of 10 ships. The broad details are as follows :—

Type of ships—Cargo Liners.

Deadweight—Ranging from 12,920 tonnes to 14,900 tonnes each.

Price—Ranging from Rs. 3.147 crores to Rs. 4.125 crores per ship.

L/M42LSS/69—6

Terms of Payment—20% of the price upto the time of delivery and the remaining 80% in 10 equal annual instalments commencing one year after the delivery of each ship and carrying interest at 3.75% p.a.

(d) Yes, Sir. The following steps have been taken by the Government to encourage development of Indian ship-building industry :—

- (i) Grant of subsidy to Hindustan Shipyard Ltd. to enable it to meet the difference between the cost of production of ships and their sale price;
- (ii) Securing of orders to book the above shipyard's capacity fully for the duration of the Fourth Plan;
- (iii) Investment by Government in the share capital of Hindustan Shipyard for financing its development programme;
- (iv) Grant of loan to Hindustan Shipyard Ltd. for the construction of a dry dock;
- (v) Setting up of a Committee in 1968 to advise Government on all matters relating to shipbuilding, ship-repairs and manufacture of ship ancillaries;
- (vi) Establishment of a Development Cell in 1968 to promote the indigenous manufacture of ship ancillaries which were being imported hitherto; and
- (vii) Setting up of a Marine Engine Plant at Ranchi which is expected to produce the main engines required for building ships from 1971 onwards.

RECOMMENDATIONS OF SEMINAR ON TRAFFIC TRANSPORTATION IN METROPOLITAN CITIES

3781. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether at the Seminar on Traffic Transportation in Metropolitan Cities held in New Delhi recently, a suggestion was

made to create a unified metropolitan authority with full powers to deal with traffic problems;

(b) if so, whether Government have considered this suggestion as also others suggestions made in the said Seminar;

(c) if so, the salient features thereof; and

(d) the reaction of Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Detailed report of the Seminar is awaited.

प्राथमिक शिक्षा में समानता

3782. श्री राम सेवक यादव : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता लाने में पब्लिक स्कूल बाधक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय ने कम से कम दिल्ली में पब्लिक स्कूल बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) ; (क) जी, नहीं ।

!(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में साक्षरता

3783. श्री राम सेवक यादव :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री ओमप्रकाश त्यागी :

श्री रामगोपाल शालवाले :

श्री रणजीत सिंह :

श्री बि० प्र० मंडल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्र : यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने लोग साक्षर हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समुचे देश में सभी लोगों को निर्धारित अवधि में साक्षर बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की भी सलाह ली गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत में तथा प्रत्येक राज्य के लिए साक्षरता की प्रतिशतता, जैसी कि 1961 की जनगणना में दिखाई गई है, सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या LT 2356/69] 1969 में, सारे देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 33 होने का अनुमान है (जबकि 1961 में 24 था) 1969 वर्ष के लिए साक्षरता के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

(ख) बड़े पैमाने पर साक्षरता की शीघ्र उपलब्धि के लिए, सभी बच्चों के लिए यथा-शीघ्र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना; और साथ ही साथ प्रोढ़ों के बीच साक्षरता अभियान आयोजित करना आवश्यक है। वे दोनों जिम्मेदारियां विभिन्न राज्य सरकारों की हैं। धन की उपलब्धता को देखते हुए, राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए व्यवस्था कर रही हैं; और चौथी योजना में प्राथमिक स्तर पर 124 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला करने और 6½ आयुवर्ग के दाखिल बच्चों की प्रतिशतता 1968-69 में 78 प्रतिशत से बढ़कर

1973-74 में 85 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है। प्रौढ़ों में साक्षरता के प्रसार के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम विकसित करने का प्रस्ताव है :—

(1) स्वैच्छिक प्रयत्नों और स्थानीय सामुदायिक साधनों का संगठन;

(2) चुने हुए जिलों में मार्गदर्शी प्रायोजन-आजों का संचालन और प्राप्त अनुभव के आधार पर उनका अन्य क्षेत्रों में विस्तार;

(3) कृषक शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता का कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत दस लाख किसानों को शामिल किया जा सके;

(4) राष्ट्रीय सेवा योजना के एक अंग के रूप में, विद्यार्थियों की सहायता से साक्षरता कक्षाओं का आयोजन; और

(5) कार्यक्रमों के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने और सभी सम्बन्धितों और उनमें शामिल विभिन्न एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना। तथापि, समस्या की विशालता और साधनों की कमी को देखते हुए, चौथी योजना की अवधि में सार्वभौम साक्षरता प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) में वर्णित प्रस्ताव, केन्द्रीय सरकार द्वारा, चौथी योजना के कार्यक्रम तैयार करते समय, राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए थे।

ALLOCATION OF POSTS OF I.A.S. AND I.P.S. TO PUNJAB, HARYANA AND HIMACHAL PRADESH

3784. SHRIMATI NIRLEP KAUR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what principles or criteria were framed for allocation of posts in the I.A.S. and I.P.S. for the three States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh at the time of creation of the Punjabi Suba; and

(b) what is the remedy to an officer adversely effected by these principles or criteria ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The allocation of posts was made on the basis of the requirements of each State, involving where necessary the creation of new posts. It was made on the recommendations of the Shanker Committee. The allocation of the IAS and IPS Officers to Punjab, Haryana & Himachal Pradesh was also made on the basis of the recommendations made by Shanker Committee.

In making its recommendations regarding the allocation of posts and officers, the Committee kept in view all relevant factors including the needs of the different units, the necessity of forming balanced cadres and the special needs, including needs of development, of the units.

Under the Punjab Re-organisation Act, 1966, the allocations of the IAS and IPS Officers were treated as final and no representations thereon were entertained.

PARKING FEE FOR SCOOTERS AT PALAM AIRPORT

3785. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently a parking fee of Re. 1/- per car is being charged at Palam Airport;

(b) whether it is also a fact that the parking fee for two-wheeler self-driven scooter is also the same that is Re.1/- per scooter, at Palam airport whereas in Delhi and New Delhi it is only 0.25 paise at all other places like Railway station, shopping centres etc.;

(c) if so, the reasons for this big difference in charges;

(d) whether Government propose to revise the rate and bring it down to usual charges of 25 paise; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). A uniform parking fee of Re. 1/- is being charged for each category of vehicle.

(c) to (e). In view of the nature of traffic and the special requirements of the Airport it was decided to make a uniform charge. There is no proposal to fix different rates for different types of vehicles.

AGRARIAN UNREST

3786. SHRI BHAJAHARI MAHATO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Policy Planning and Research Division of his Ministry has done a detailed study on agrarian unrest and peasant movements for land reforms; and

(b) whether the summary of this study will be placed on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes.

(b) A summary is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2357/69.]

IMPROVEMENT IN THE EXISTING TOURIST FACILITIES

3787. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) what improvements in the existing tourist facilities are proposed to be made by his Ministry in view of the likely increase in the charter loads of foreign tourists resulting from the lifting of all restrictions on the number of tourists charter flights;

(b) whether any improvement in Customs clearance is also likely to save the tourists from lengthy procedures and consequent exasperating delay; and

(d) the steps being taken to streamline the entire approach to tourism ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Steps are being taken to increase hotel accommodation for tourists, to improve the existing supplementary accommodation in the shape of tourist bungalows, etc., and to augment transport facilities.

(b) This aspect is under constant consideration. A Single Baggage Re-export Form signed by the leader of the group is now accepted for the articles carried by members of the group.

(c) A High Level Committee on Facilitation has been set up to streamline and simplify formalities. To expedite clearance, this Committee has recommended the introduction of a channeling system at international airports and the combining of all documents required to be completed on arrival into a consolidated embarkation/disembarkation card.

INDIGENOUS PRODUCTION OF SOLID STATE MICRO-ELECTRONICS FERRITES

3788. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) what is the progress made in beginning the indigenous production of "Solid State Micro-electronics ferrites integrated circuits" a new terminology or radio and television machinery, by a leading Dutch electronic component maker;

(b) what are the advantage of this innovation; and

(c) to what extent the process is likely to yield results in miniaturisation that will help to reduce the size of the radio receivers, increase reliability and conserve raw materials ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Solid state micro-electronic circuits which are integrated circuits, are in the process of development at (i) The Tata Institute of Fundamental Research, Bombay (ii) the Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani and (iii) Solid State Physics Laboratory, Delhi.

Ferrites, which are also electronic components, are being developed at (i) National Physical Laboratory, New Delhi (ii) National Chemical Laboratory, Poona (iii) Solid State Physics Laboratory, Delhi and (iv) Regional Research Laboratory, Hyderabad.

(b) The advantage of the innovation is that it can reduce the size of components used in radio and T.V. considerably.

(c) Integrated circuits can replace a number of components and miniature radio receivers can be produced successfully. In addition, there is a great advantage of high reliability and cost reduction in adopting integrated circuits.

MID-DAY MEAL PROGRAMME FOR CHILDREN

3789. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) what are the reasons that no further expansion of the mid-day meal programme, started by his Ministry in 1962-63 for the children under aid from the CARE (Committee on American Relief Everywhere) has been made;

(b) whether the special assistance offered to Bihar as part of famine relief during 1966-68, shall continue or a part or the whole thereof is likely to be diverted to other needy areas;

(c) the contribution of the Government of India towards the programme; and

(d) whether the recipient State Governments also contribute to the programme and, if so, in what manner ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) The scheme was started in 1962-63 in five States, providing mid-day meals for 42 lakhs children. It has now been extended to 14 States and it provides meals for 131 lakhs.

(b) The special assistance provided to Bihar has ceased. No such provision exists for the current year, nor it is proposed to divert it to any other areas.

(c) and (d). The State Governments have been meeting incidental and administrative expenditure on the operation of the scheme. As far as the Government of India is concerned, thirty-three per cent up to 1966-67 and forty per cent during 1967-68 and 1968-69 of such expenditure used to be reimbursed by it. The pattern of Central assistance during the Fourth Plan has now been changed and assistance is provided by the Government of India to the State Governments in the form of Block grants and not scheme-wise.

REVISION OF GRADES OF SCHOOL LABORATORY ASSISTANTS

3790. SHRI P. VISHWAMBHARAN :
SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI LAKHANLAL KAPOOR :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Finance Ministry has communicated its concurrence with the recommendations of the Education Commission made in 1967 about the revision of grades of School Laboratory Assistants;

(b) if so, whether these recommendations are made applicable to all the categories of Laboratory Assistant;

(c) if not, what are the categories whose grades are being revised; and

(d) the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (d). The pay scale of all laboratory assistants in Higher Secondary Schools in Delhi, who were in position on 21-12-1967, has since been revised with the concurrence of Ministry of Finance. The question of the revision of the scale of pay of laboratory assistants employed in schools in the various States is the concern of the State Governments concerned.

MEMORANDUM DEMANDING BAN ON R.S.S.

3791. SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI E. K. NAYANAR :
SHRI SUSEELA GOPALAN :
SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any memorandum demanding a ban on the R.S.S.; and

(b) if so, the reaction of Government on this issue ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Demands have been made for a ban on communal organisations.

(b) In view of the recent communal disturbances, Government are considering measures to deal with the activities of organisations, which promote or attempt to promote, on grounds of religion or race, disharmony or feelings of enmity, hatred or illwill between different such religious or racial groups.

U.S.I.S. OFFICIALS' MEETING WITH STUDENT LEADERS

3792. **SHRI BHAGABAN DAS :**
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI SATYA NARAIN SINGH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three U.S.I.S. officials met the student leaders, who had called hartal recently in Gauhati, Assam; and

(b) if so, whether Government have enquired into their activities at that time and what are the findings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Two officials of the U.S.I.S. are reported to have visited Gauhati and Shillong in the month of September 1969 in the course of their official work relating to "USIS Book Programme". Their activities have not come to any adverse notice.

TRANSLATION OF GRAM GEETA

3793. **SHRI DEORAO PATIL :** Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken to translate "Gram Geeta" of Sant Tukdoji Maharaj in all the languages; and

(b) if so, the time by which the work is proposed to be completed ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The Government of India have not undertaken to translate "Gram Geeta" of Sant Tukdoji Maharaj in regional languages.

GRIH KALYAN KENDRA

3794. **SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5392 on the 29th August, 1969, and state :

(a) the names, designations and addresses of the member of the Grih Kalyan Kendra, which is stated to be a Registered Society, as also the names, designations, and addresses of the Office-bearers of the said Society;

(b) the income and expenditure account and the assets and liabilities account of the said Kendra for the last 3 years;

(c) the pay scale being given to the teachers in the Grih Kalyan Kendras in various colonies and elsewhere;

(d) the fees being realised from the trainees or children of various types of classes; and

(e) the monthly pay being paid to the chowkidars, peons and tailor masters in various Kendras ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Grih Kalyan Kendra was registered in May 1965 under the Societies Registration Act, 1860 as extended to the Union Territory of Delhi in pursuance of Memorandum of Association, a copy of which is attached.

The names, designations and addresses of the existing members of the Grih Kalyan Kendra Board are as follows :—

Shri L. P. Singh, Secretary,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi.

.....President

Other Members :

1. Shri Uma Shankar,
Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
2. Shri B. R. Patel, Secretary,
Department of Agriculture, New Delhi.
3. Shri G. K. Bhanot, Joint Secretary,
Ministry of Finance, New Delhi.
4. Shri N. J. Kamath, Joint Secretary,
Ministry of Industrial Development and Company Affairs, New Delhi.

5. Shri E. Kolet, Joint Secretary and Controller of Chartering, Ministry of Transport & Shipping (Transport Wing), New Delhi.

6. Shri P. N. Natu, Chief Welfare Officer, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Miss C. A. Radha Bai, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs who is also the Organiser of Grih Kalyan Board .. *Secretary of the Board.*

Other Office Bearers :

Mrs. Nilima Banerji, Deputy Organiser, Grih Kalyan Kendra, 19, Mahadev Road, New Delhi.

(b) Statements showing the Income and Expenditure account and the Assets and Liabilities account of Grih Kalyan Kendra for the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2358/69]. The accounts for the year 1968-69 have not yet been finalised.

(c) The teachers of Grih Kalyan Kendra working in various colonies and elsewhere are paid only Honorarium (not salaries) ranging as follows :—

		Duty hours,
<i>Teachers (Craft)</i>	Rs. 75 to 150 per month,	4 1/2 hours.
<i>Teachers (Nursery)</i>	Rs. 75 to 100 per month,	3 hours.
<i>Teachers (Music)</i>	Rs. 40 to 100 per month.	1-2 hours.

(d) The Fees charged from the trainees of various classes are shown below:—

(1) Craft	Tuition Fee.
Tailoring & Embroidery or Machine Embroidery	Rs. 3 per month.

Summer vacation Course

For one Subject:	Rs. 5 per month.
For two Subjects:	Rs. 8 per month.
Admission Fee:	Rs. 2/-
Examination Fee:	Rs. 2/-.

(2) *Bal-Kendra:*

For children of Class IV Staff,	Rs. 1/- per month.
For children of Class III Staff	Rs. 2/- per month.
For children of Class II Staff	Rs. 3/- per month.
For children of non-Government employees.	Rs. 5/- per month.
Examination Fee	Rs. 1/-
Admission Fee	Rs. 1/-.

(3) *Dance & Music*

Group Dance	Free
Kathak Dance	Rs. 3/- per month.
Bharat Natyam	Rs. 3/- per month.
Sitar	Rs. 3/- per month.
Harmonium	Rs. 2/- per month.
Tabla	Rs. 2/- per month.
Classical Music	Rs. 3/- per month.
Light Music	Rs. 2/- per month.
Admission Fee	Rs. 2/-
Sister concession for two	Rs. 1/-.

(e) Honorarium is paid to Chowkidars, Labour boys and Tailor Masters in various Kendras ranging as follows :—

(1) Chowkidars, Labour Boys	Rs. 60 to 100 per month.
(2) Tailor Masters	Rs. 120 to 240 per month

TAMILNADU SCHEME FOR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES TO UNEMPLOYED ENGINEERS

3795. SHRI SEZHIYAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tamil Nadu Government have submitted a scheme for creating employment opportunities to un-employed engineering graduates;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government to the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) No, Sir. In May, 1968, Government of India decided on certain measures to augment employment opportunities for engineers and recommended these measures to the State Governments for implementation. A statement listing the measures was laid on the Table of the House in answer to Starred Question No. 138 on 26th July, 1968. In response to the suggestion, the Government of Tamil Nadu have decided to take up:—

- (1) investigation of irrigation schemes;
- (2) tank restoration schemes;
- (3) preparation of technical reports on selected projects; and
- (4) imposition of liability on contractors to employ engineers.

Other measures are also under the consideration of the State Government. Apart from these measures, which the State Government are taking in response to the suggestion of the Government of India, no other scheme has been submitted by the Government of Tamil Nadu for creating employment opportunities to unemployed engineering graduates.

(b) and (c). Do not arise.

PENSION AND RETIREMENT BENEFITS TO
RETIRING GOVERNMENT SERVANTS IN
MANIPUR

3796. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Government servants who have retired during the last three years under the Government of Manipur;

(b) how many of them have so far actually been given pension and retirement benefits; and

(c) whether there has been delay in granting pension to these retired Government employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). According to the Government of Manipur, 112 Government servants retired during the last three years, out of which 29 have been granted pension and other retirement benefits. The remaining cases could not be finalised for want of complete service records, etc. All possible efforts are being made by the Government of Manipur to expedite finalization of these case.

DELHI HIGH COURT'S JUDGEMENT REGARDING
JOINT INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE
CADRE FOR UNION TERRITORIES

3797. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Delhi High Court has quashed the Government's order for the formation of Joint Indian Administrative Cadre for the Union Territories;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken so far in the light of the Court's Judgement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Appeals against the judgement of the Delhi High Court and application for stay the judgement have been filed in the Supreme Court.

LOSS OF FILES FROM CUSTODY OF STATE
INTELLIGENCE IN MANIPUR

3798. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the loss of some important files from the custody of State Intelligence as published in the local monthly journal Lamyamba of Manipur in its 4th Number published on the 1st November, 1969 at page 26 under the heading "Yukhəl Marumda";

(b) whether Government's attention has already been drawn to the alleged corruption episodes referring to the Chief Commissioner, Manipur as published in the

aforsaid journal of the same number at page 28 and also of some other corruption stories as contained in the earlier publications of the Journal under the heading "Yukhalgi Marumda"; and

(c) if so, whether Government propose to make an enquiry and take appropriate action in both the cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

DEVELOPMENT OF TOURIST SPOTS IN BIHAR

3799. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of Tourist spots to be developed under the Fourth Five Year Plan in Bihar and the details of the development plans in respect of each spot;

(b) the estimated cost for development of each spot; and

(c) the extent of Central aid to be rendered in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). It is proposed to provide facilities for tourists during the Fourth Five Year Plan at Bodhgaya, Rajgir, Nalanda and Patna in Bihar. Detailed costs of the individual schemes have not been finalised but they will be financed entirely by the Central Government.

SUSPENSION OF INDO-CEYLON FERRY SERVICE

3800. SHRI SEZHIYAN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the Indo-Ceylon ferry Service is to be suspended during the months of November and December;

(b) whether it is a fact that during the Company days the ferry boat operated throughout the year; and

(c) the reasons for the closure of the ferry service now ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Till December 1964, the Southern Railway was operating a regular ferry service between Dhanushkodi and Talaimannar with two steamers, viz. t.s.s. 'Irwin' and t.s.s. 'Goschen' throughout the year as an extension of the overland railway service. In December, 1964, the pier at Dhanushkodi and the railway track between Mandapam and Dhanushkodi were severely damaged by a cyclone and one of the vessels operated by the Railways, viz. t.s.s. 'Goschen', ran aground near Talaimannar. As a result of this catastrophe, the Railways suspended the ferry service. The Railways did not resume it as they found it uneconomical.

With a view to maintaining close link with Ceylon, the Government of India directed the Shipping Corporation to operate a passenger service between India and Ceylon. As a result of the severe damage to the Dhanushkodi pier and the railway track between Mandapam and Dhanushkodi, it was no longer possible to operate the service from Dhanushkodi. Further, due to the severe damage sustained by the vessel, t.s.s. 'Goschen' owing to grounding only one vessel, viz. t.s.s. 'Irwin' was available for operation. The Shipping Corporation took over and reconditioned the vessel t.s.s. 'Irwin' and started operating regular service between Rameswaram and Talaimannar from 31st March, 1966. The service is at present operated from stream about a mile and half from shore at Rameswaram. Due to the severe cyclonic weather conditions prevailing in that area, this service remains suspended during November and December every year, in the interests of the safety of passengers. Further, under the Merchant Shipping Act and the Mercantile Marine Regulations, every passenger vessel has to undergo a passenger survey every year, which is compulsory. The annual survey of the t.s.s. 'Irwin' is carried out in Bombay every year during the period when the service remains suspended, with a view to ensuring the safety of life at sea and satisfactory ship's service during the rest of the year.

11.03 HRS.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORTS OF INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR AND INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, AHMEDABAD

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : Sir, on behalf of Dr. V. K. R. V. Rao, I beg to lay on the Table—

- (1) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the year 1968-69.
- (2) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Management, Ahmedabad for the year 1968-69. [Placed in Library. See No. LT-2332/69].

REPORT RE. RAILWAY ACCIDENT AT LUCKEESARAI, EASTERN RAILWAY

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Commissioner of Railway Safety on the accident involving train No. 22 Down North Bihar Express at Luckeesarai Station of Eastern Railway on the 24th October, 1966. [Placed in Library. See No. LT-2333/69].

STATEMENT RE. CYCLONE IN ANDHRA PRADESH IN NOVEMBER, 1969

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : I beg to lay on the Table a statement (Hindi and English versions) regarding November, 1969 Cyclone in Andhra Pradesh. [Placed in Library. See No. LT-2334/69].

ANNUAL REPORT OF KERALA AGRO-INDUSTRIES CORPORATION LTD.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING) : Sir, on behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg

to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Kerala Agro-Industries Corporation Limited Trivandrum for the year 1968-69, along with the Audited accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [Placed in Library. See No. LT-2335/69].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT, 1951

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Sir, on behalf of Shri Vidya Charan Shukla, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

- (1) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G. S. R. 2670 in Gazette of India dated the 29th November, 1969.
- (2) The Tenth Amendment to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 2671 in Gazette of India dated the 29th November, 1969.
- (3) The Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1968, published in Notification No. G.S.R. 2677 in Gazette of India dated the 29th November, 1969. [Placed in Library. See No. LT-2336/69].

MORMUGAO PORT TRUST (PROCEDURE AT BOARD MEETINGS) AMENDMENT RULES, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : I beg to lay on the Table :

- (1) A copy of the Mormugao Port Trust (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G.

S. R. 1736 in Gazette of India dated the 26th July, 1969, under sub-section (3) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963.

- (2) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification. [Placed in Library. See No. LT-2337/69].

RULES COMMITTEE

MINUTES

श्री नारायण स्वरूप शर्मा (डुमरियागंज) :
 उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम समिति की 8
 दिसम्बर, 1969 को हुई बैठक का कार्यवाही
 सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

SHRI SEZHIAN (KUMBAKONAM) :
 Sir, regarding item 2, I have a point to
 make. It is about the Report of the Com-
 missioner of Railway Safety. I do not
 know how Dr. Karan Singh is concerned
 with the Commissioner of Railway Safety.
 Anyhow, this report of the Commissioner
 of Railway Safety is on the accident in-
 volving the North Bihar Express at Luc-
 keesarai Station of Eastern Railway on the
 24th October, 1966. About three years
 have elapsed. Why has there been so
 much delay in making inquiry and placing
 the Report on the Table of the House ?

MR. DEPUTY SPEAKER : It is a little
 irregular.

DR. KARAN SINGH : The office of the
 Commissioner of Railway Safety is under
 the Ministry of Tourism and Civil Avia-
 tion. It was removed from the Railway
 Ministry and taken into another Ministry
 in order to ensure its impartiality. I will
 find out the reasons for the delay and let
 the House know about it.

11.05 HRS.

COMMITTEE ON GOVERNMENT
 ASSURANCES

(i) SEVENTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi
 Sadar) : I beg to present the Seventh Re-
 port of the Committee on Government
 Assurances.

(ii) EVIDENCE

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I beg
 to lay on the Table a copy of the Evidence
 given before the Committee on Govern-
 ment Assurances.

11.05½ HRS.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
 TARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND
 TRANSPORT (SHRI RAGHU
 RAMAIAH) : With your permission, Sir,
 I rise to announce that Government Busi-
 ness in this House during the week com-
 mencing Monday, the 15th December,
 1969, will consist of :—

- (1) Further consideration and passing
 of the Monopolies and Restrictive
 Trade Practices Bill, 1969, as
 passed by Rajya Sabha.
- (2) Consideration of any item of
 Government Business carried over
 from today's Order Paper.
- (3) Consideration and passing of :

The Assam Reorganisation
 (Meghalaya) Bill, 1969.

The Indian Tariff (Amendment)
 Bill, 1969.

The Requisitioning and Acquisi-
 tion of Immovable Property
 (Amendment) Bill, 1969.

SHRI RANGA (Srikakulam) : What
 about Mr. Imam's Resolution ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : It was
 agreed yesterday that it will come up on
 Tuesday.

SHRI RANGA : It should have been
 mentioned.

SHRI RAGHU RAMAIAH : It was an-
 nounced in the House yesterday.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begu-
 sarai) : Sir, a very serious situation ob-
 tains in Jamshedpur. About 40,000 engi-
 neering workers have been on strike since
 18th November. 26 days have passed.

[Shri Yogendra Sharma]

This question was raised here and the hon. Labour Minister had assured that there will not be any victimisation. About 200 workers have been suspended and because of that the strike is continuing. We should get some opportunity to discuss it. The hon. Labour Minister had given an assurance and this assurance has not been implemented. You may kindly ask the hon. Minister to make a statement at least of what has been done in order to see that his assurance is carried out and the strike is called off. If the strike is not called off, anything may happen. You know the situation in Jamshedpur. Lately, I have got the information. There have been police provocations and, if they are not stopped, anything may happen.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Note will be taken of that.

श्री शिव चन्द्र शा (मधुबनी): उपाध्यक्ष जी, अभी श्री योगेन्द्र शर्मा ने जो जमशेदपुर की हड़ताल के मुताल्लिक कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सरकार को इसपर जल्दी वक्तव्य देना चाहिए।

दूसरे यह कि पिछले हफ्ते में मैं ने यह बात उठाई थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में देरी हो रही है और मुझे शक है कि उसको लाने में सरकार टाल मटोल कर रही है, वह इसको लाने की अवधि और बढ़ायेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार, खास तौर पर प्रधान मन्त्री सदन को बतावें कि हकीकत में चौथी योजना सदन के सामने कब तक आएगी।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): डिप्टी स्पीकर महोदय, एक बहुत गम्भीर बात जो कि देश से ताल्लुक रखती है वह आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उसपर अपना ध्यान दे। आज हमारा देश कहां जा रहा है? मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट इस बात का ध्यान रखे और आप इस बात का ध्यान रखें। बात यह है कि कैबिनेट का एक मिनिस्टर कहता है कि अगर चंडीगढ़ नहीं दिया तो हम इंडियन यूनियन से अलग हो जाएंगे। साथ साथ यह भी कहता है कि

अगर चंडीगढ़ नहीं मिला तो हम वार कर देंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि चंडीगढ़ किसको मिले बल्कि सवाल यह है कि देश के साथ कुछ आदमी खुल्लम खुल्ला गद्दारी का प्रचार करते हैं। देश की इन्ट्रिटी और सिक्योरिटी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यह हालत बड़ी खतरनाक है जिसकी नोटिस इस पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। मैं आपकी माफ़त चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में एलान करे। सरकार के पास अनलाफुल एक्टिविटीज ऐक्ट है और दूसरी प्राविजन्स हैं। अगर बाड़ ही खेत को खायेगी तो फिर खेत में क्या रहेगा? गवर्नमेंट के बड़े बड़े वजीर ऐसे हैं जोकि पाकिस्तान के साथ घुलमिल कर ऊट पटांग बातें करते हैं। इस तरह से इस देश का क्या बनेगा? मैं चाहता हूँ कि खास तौर पर होम मिनिस्टर साहब इम मिलसिले में स्टेटमेंट दें और उसके लिए टाइम निकालें।

जैसा कि मैंने अभी पंजाब मन्त्रिमंडल के एक मन्त्री जीवन सिंह उमरांगल द्वारा चंडीगढ़ के बारे में कही गई बात का जिक्र किया तो पंजाब के उस मन्त्री का वह घोर आपत्तिजनक वक्तव्य और कलकत्ते में जो अराजक तत्व सक्रिय हो रहे हैं और हाल की कलकत्ते के एक बैंक में दिनदहाड़े माओ त्से तुंग के हार्मियों द्वारा डाका डालने की घटना ने सभी देश का हित चाहने वालों को घोर चिन्ता में डाल दिया है और समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर इस देश में क्या होने वाला है। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इन दोनों चीजों पर खास तौर पर ध्यान दें और हाउस को इस बारे में बतलाएं।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): I support Mr. Randhir Singh.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): Sir, only eight working days are left—5 days next week and 3 days thereafter. The Government business now announced by the Minister will consume all the eight days.

Sir, there are a number of important things which need to be discussed. There is a report of the Committee on Defections which is being postponed week after week. Then there is the discussion on the resolution of Shri Prakash Vir Shastri about subversive activities.

Then there are certain issues over which the Delhi Administration or the Metropolitan Council have no control and which have to be discussed in this House. They include the problem of unauthorised colonies and admission to Delhi colleges. I want that discussion on these matters must be held. I do not know if the time will be found for them. If there is not time, then Government business may be postponed to the next session, but these matters should be discussed.

Then I come to the question which Mr. Randhir Singh has raised, viz., the question of Chandigarh and about the reported talks between Pakistanis and some Punjab leaders. Government must make a statement about that. I also want the Government to make a statement to give us an opportunity to discuss what is happening in West Bengal. To-day only we read about an armed robbery in a Calcutta bank. It is not a State subject, it is a subject dealt with by the Finance Ministry and I want that the Finance Minister should make a statement about it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : A calling attention motion on this subject has been admitted for Monday.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Therefore, for all these questions time must be found. If time cannot be found—do whatever you like—these subjects cannot be postponed just because Government's business will be held up and they want to oblige this man and that man and make the Parliament go on holiday.

SHRI RANDHIR SINGH : That Punjab Minister who spoke against the country should be arrested.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have made your submission. There are other things also. I am sure all that you raise here is being noted down by the Minister and will be considered at the proper time.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : There is another point. It is not the business of the head of the administration here to go and criticise the other heads of administration in States as the Prime Minister has been doing frequently. Therefore, that matter also must be discussed next week.

श्री क० ना० तिवारी (देतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इधर काफ़ी दिनों से पश्चिमी बंगाल में ला एंड आर्डर की पोजीशन ठीक नहीं है। डकैतियां वहां पर पड़ रही हैं और यह अभी दिनदहाड़े कलकत्ते के एक बैंक में 4 लाख 62 हजार रुपए की डकैती पड़ी है। आप ने अभी कहा कि इस बारे में सोमवार को एक कौलिंग अटेंशन नोटिस आ रहा है तो मेरा सुझाव यह है कि इस तरह की कई डकैतियां बंगाल में हो चुकी हैं इसलिए बजाए कौल अटेंशन के इस पर अलग से हाउस में डिस्कशन ऐलाऊ किया जाए और केवल कौल अटेंशन से ही काम नहीं चलेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि बिहार में मन्त्री-मंडल निर्माण के सवाल को लेकर तरह तरह की बातें वहां पर चल रही हैं और उस पर भी हाउस में एक डिस्कशन कम से कम एक घंटे का या आध घंटे का रखा जाए ताकि बिहार के लोगों को पता लग जाए कि दरअसल दिक्कत कहां है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This, I told you, has been admitted.

DR. RAM SUBHAG SINGH : This is a very good point that must be discussed because the Government of India is interfering in the State of Bihar. They are not allowing the leader of the majority to form the Government. Here the Governors' Conference is going on. The leader of the Congress Party in the Bihar legislature who has submitted a list of 184 persons must be permitted to form a government. (Interruptions).

श्री शिवचन्द्र झा : बिहार में एस० एस० पी० को मन्त्रिमंडल बनाने का मौका मिलना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह: एस० एस० पी०
वहाँ नहीं है।

MR. DEPUTY SPEAKER: This is not an occasion when we can enter into argument with each other. Submissions have been made by various members who feel that certain important items should be included. I am sure all these are being noted by the Minister in-charge and they will be taken up and considered and whatever can be done will be done. Kindly have patience. Let us hear one by one patiently.

SHRI SEZHIAN (Kumbakonam): Regarding the proposal of the Government to decontrol cement from 1st January, 1970 I feel it is a very important question that should be discussed by this House. 133 Members of Parliament during the last session have sent a Memorandum to the Prime Minister and the Minister for Industrial Development. No reply has since been received for that so far. Also, the Members of the Consultative Committee have also expressed themselves against any decontrol at this stage and for that also no positive action has been taken by this Government. It is a very important question. This is going to affect the consumers throughout the country. If they abolish the price control system it is going to encourage monopoly in cement industry and help big business. So, I would call upon the Government to give some opportunity to this House to discuss this question of decontrol of cement on a positive Motion. I don't want to have some discussion and then it is left off. I want to have a positive motion which should be discussed so that the opinion of the House can be expressed in unequivocal terms against any decontrol that is contemplated by the Government.

AN HON. MEMBER: Too much bungling is going on...

MR. DEPUTY-SPEAKER: That has been noted.

श्री राम चरण (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफ़े इस पार्लियामेन्ट में यह आवाज उठाई गई है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट

जोकि सन् 1967-68 की है और जोकि संसद् में 15 मई को पेश भी की गई है अभी तक उस पर बहस नहीं हुई है।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जो अनटचेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट है उस की भी वही हालत है। उस पर भी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मन्त्री जी कहते रहे कि अब डिस्कस होगी और तब डिस्कस होगी लेकिन अभी तक उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया है। अप्रैल में वह हाउस की टेबुल पर रखी गई थी लेकिन यह दुख का विषय है कि अभी तक उस पर हाउस में बहस नहीं हो पाई है। यह दोनों रिपोर्ट अभी तक डिस्कस नहीं हो पाई हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। यह असलियत को ऐक्सपोज करने वाली है। कम से कम एक रिपोर्ट पर तो इस सेशन में अवश्य डिस्कसन हो।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I have to bring to your kind notice two things. One is, the situation in Kerala. The United Front Government was there. The marxists communist party Government had resigned. The communist party today who are in minority party today Government. Our Prime Minister had instructed the Governor to allow them to form the Government. They have allowed the minority Government there. That is a very serious things, asking a minority group to form the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You want that to be included as a subject for discussion?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Yes.

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): It is not a minority Government. I want to raise a point of order. (Interruption) In Kerala, it is not a minority Government. It is a majority Government. We will prove our majority absolutely.

SOME HON. MEMBERS—rose

MR. DEPUTY-SPEAKER: I request Hon. Members to resume their seats. Why did you not call the Assembly? (Interruptions)

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry): What the hon. Member has just now said is absolutely correct, it is a minority Government. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly resume your seat. Kindly let me say one sentence. (*Interruption*) I am on my legs. What he has stated is one point of view and he is entitled to have his point of view. But this is not really the time or the occasion to enter into a discussion over this issue. It has not been admitted. It is only a suggestion made.

SHRI A. SREEDHARAN: I want to make a submission. We can understand if they want a discussion on the political situation in Kerala with regard to the formation of the Government—we can understand all that—but he said that the Kerala Government is a minority Government. (*Interruption*) It is not a minority Government.

SHRI P. GOPALAN: Who said so? It is a minority Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him conclude.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I want to say this about the proposal of the Government to decontrol cement from 1st January, 1970. Government have taken a very big donation for their party, that is, the rebel Congress Party and that is why they want to decontrol cement....

SHRI RAGHU RAMAIAH: This is a wholly untrue and an unfair allegation.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: The price of cement will go up by Rs. 5 per tonne; Government purchase about one-third of the cement that the consumers take; as a result, the country's finances will suffer, and Government will lose about Rs. 3 crores...

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member has started a discussion.

SHRI RAM KISHAN GUPTA (Hissar): They have taken about Rs. 25 lakhs.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): May I make one submission? This is for you.

I have already submitted an adjournment motion on the failure of Government to prevent the armed robbery at the State Bank of India branch operating at Calcutta. This is not the first time that such an armed robbery has taken place there...

MR. DEPUTY-SPEAKER: That has no relevance to the statement made by the hon. Minister.

SHRI HEM BARUA: That was why I said that it was meant for you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is a separate point. We can discuss it separately. That has no relevance to the statement made by the hon. Minister.

SHRI HEM BARUA: I want this matter to be discussed. For, this is not the first time that there has been such armed robbery at Calcutta.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are now only concerned with the business of the House for the next week which has been announced by the hon. Minister.

SHRI HEM BARUA: That was why I said that it was meant for you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot say anything on that now. We are now concerned only with the list of business for next week as announced by the hon. Minister.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): The business for the next week is discussed in the Business Advisory Committee first, and a convention has been developed that normally we should not raise issues here in the House without first discussing them in the Business Advisory Committee. But when the business is announced here, naturally we get some opportunity to highlight some problems. On the 24th of this month, the current session of Parliament is coming to an end. News has appeared in various newspapers that the life of the Preventive Detention Act is going to end very soon. We would like to know whether that is true or not.

I would plead that we should have some discussion regarding the abolition of the

[Shri S. M. Banerjee]

privileges and privy purses of rulers, a motion for which has already been tabled and we would like to have a discussion on it for three hours.

I would also like to submit that in spite of the assurances of the Prime Minister and the Home Minister, 1,200 Central Government employees are still rotting in the streets and have not been taken back. We want a statement from the Prime Minister on this matter. She delivers speeches to those who go and meet her, and they sound very well, but actually they have not been taken back. I would request the hon. Minister....

SHRI BAL RAJ MADHOK : Thou too, Brutus !

SHRI S. M. BANERJEE : ...of Home Affairs or the Prime Minister to make a statement on this.

Shri Kanwar Lal Gupta called us the other day as the drummer-boys of the Prime Minister, I was thinking that I could call them the dancing girls of the Syndicate...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. Let us not enter into that controversy now.

SHRI RANGA : I would like some time to be found by Government, if possible, during the next week, as early as possible, or if necessary by extending the duration of the session or by postponing the rest of the work, to discuss the law and order situation in West Bengal. The whole House is aware of what is happening there. All over the State, hunger-strikes or fasts are going on. The Chief Minister himself who belongs to one of the constituent parties of the United Front has made so many allegations against his own Ministry and against his own Government and has given figures of the number of people killed or mauled or robbed and so on. He himself bore witness to the fact that there is no proper law and order there and there is no security of life, not to speak of property. I would request Government to give us an opportunity to have a full discussion of this particular matter.

SHRI P. GOPALAN : On a point of order...

MR. DEPUTY-SPEAKER : How can there be a point of order now ? A certain submission is being made by the hon. Member for consideration for the purpose of its being included in the list of business for next week. He may not like certain things which are being said by the hon. Member, but it is only a submission that he is making for consideration by the House. If the hon. Member Shri P. Gopaln has any objection, he can raise it at the appropriate stage. Already, I find that this item is taking more time than it should. So, let hon. Members be very brief.

SHRI RANJEET SINGH (Khalilabad) : I would submit that time should be found and also allocated for discussing the following subjects which are of primary importance. We are already going to have a discussion on the law and order situation in certain places...

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is only a submission which has been made.

SHRI RANJEET SINGH : I submit that we discuss the nation's security in general, because disclosures have been made even by people concerned with the defence set-up of the country, by people like Vice-Admiral Soman that our defence is weak in general and that, coupled with the breakdown of law and order in certain States, affects the nation's security in general.

Then, the Bank nationalisation Bill is pending before the Supreme Court, and judgment may be delivered any day. We should be permitted to discuss the consequences arising out of that judgment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That can be considered when the judgment is delivered.

SHRI RANJEET SINGH : We should also have an opportunity to discuss another small matter relating to the large business empire of Ministers, especially a Minister who has got his hand in 42 organisations; I am referring to Shri Jagjivan Ram.

श्री श्रीधर शा (जयनगर) : बिहार के एक एम० एल० ए० श्री केदार दास ने मेरे पास एक तार भेजा है जिसको मैं आपकी आज्ञा से टेबल पर रखना चाहूंगा। आज बिहार भर में जमशेदपुर दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों को इसके बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। लेकिन मालूम ऐसा पड़ रहा है कि या तो श्रम मंत्री की बात टाटा पर लागू नहीं होती है या फिर बे दिल से इसको करना नहीं चाहते हैं, अपने आश्वासन की पूर्ति करना नहीं चाहते हैं। मेरा गूह है कि जमशेदपुर के सवाल पर बयान हो और बहस हो। जो इन्होंने आश्वासन दिया था उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। बिहार में असम्बन्धी काम नहीं कर रही है। बिहार का शासन केन्द्रीय सरकार के अधीन है। आप इन्हें कहें कि इनके आश्वासन का जो उल्लंघन हो रहा है, उसके बारे में एक वक्तव्य भेजें।

बिहार में मधोलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वहां के एक मिनिस्टर कामाख्या नारायण सिंह को उसने मुजरिम पाया है। उन्होंने निजी स्वार्थों के लिये सरकारी पद का दुरुपयोग किया है। वहां पर असम्बन्धी काम नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री इस बारे में एक बयान दें। उनको मुद्दालय बना कर क्या सरकार कचहरी में खड़ा करने जा रही है या नहीं?

मैं आपकी आज्ञा से इस तार को टेबल पर रखना चाहूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He cannot lay it on the Table of the House now. He can only make his submissions.

श्री तुलसीदास जाधव (बारा मती) : हरिजनों के ऊपर हमसे होते रहते हैं और इनके समाचार अखबारों में छपते रहते हैं। कभी आंध्र में होता है, कभी उत्तर प्रदेश में और कभी मध्य प्रदेश में। आज वे ही अखबारों में आया है कि सिहोर जिले के गोगखिया गांव में ठाकुरों

ने हरिजनों पर हमला किया और उनके बारह आदमियों को घायल किया। मैं चाहता हूँ कि हरिजनों को संरक्षण देने के वास्ते इसको एक स्पेशल सबर्जक्ट के तौर पर रखा जाए और इस पर यहाँ बहस की जाए।

SHRI S. M. BANERJEE : The Labour Minister has already made a statement on Jamshepur. So, you may kindly ask the hon. Labour Minister to make a statement on this again.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I am very sorry to point out that the motion of Shri Prakash Vir Shastri on violent activities in the country which had been included earlier in the list of business for today has suddenly been removed in the Revised List of Business for today. I had to go to Calcutta today morning, but I cancelled it yesterday as I found this motion was to be taken up today because I consider this motion to be very important in relation to West Bengal. You know the harvest there has turned into a bloody harvest, every day hundreds of people are injured and dozens of people are being killed. Every day reports are coming in the papers. Coming as I do from West Bengal I wanted to participate in that debate and I cancelled my trip to Calcutta yesterday evening, but now I find that the discussion is not being held today.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The whole matter was gone into by the Business Advisory Committee and it was decided that since there is a heavy backlog of business, today, though normally it should be a holiday, should be a working day in order to dispose of urgent Government business. So, it was the decision of the Business Advisory Committee.

SHRI SAMAR GUHA : Why did he mislead us then? It is the whimsical and mercurial attitude of the Minister of Parliamentary Affairs that has changed it. Who authorised him to change it?

Then I want to draw the attention of the Government to a serious impropriety, breach of the constitutional provisions, being committed by the Government of West Bengal.

[Shri Samar Guha].

You know that foreign affairs is under the exclusive jurisdiction of the Centre. I have full sympathy with the NLF, the Viet Nam revolutionaries, but you might have seen in today's papers that the West Bengal Government is going to officially accord a reception to them and constitute a fund from the Government coffers to give that delegation.

SOME HON. MEMBERS : Shame.

SHRI SAMAR GUHA : Unofficially I will welcome them, and for that matter any revolutionary, but the question is whether a State Government can usurp the right of the Centre defined in the Constitution. I want to know Government's attitude on that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is a different question. I take it that you would like this to be discussed.

SHRI S. M. BANERJEE : Why don't you allow us to congratulate the UP Government ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri K. L. Gupta. Kindly conclude in one or two minutes. Otherwise, it becomes difficult, the whole day will go on like this.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बात कहनी है। एक तो यह दिल्ली का सीधा सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है और जैसा अभी प्रोफ़ेसर मधोक जी ने कहा कि यहाँ पर एडमीशन का प्राबलम है, झुम्मी-झोड़ी का प्राबलम है और हमेशा से यह परम्परा रही है कि हर एक सेशन में दिल्ली के एक या दो इश्यू डिस्कस किये जाते हैं, लेकिन यह पहला सेशन होगा जिसमें दिल्ली का कोई इश्यू नहीं डिस्कस होगा।

दूसरी बात रीजनल इम्बैलेंस के बारे में मैंने प्रस्ताव दिया था और वह रीजनल इम्बैलेंस का प्रस्ताव पिछले सेशन में भी स्वीकार किया गया था, इस सेशन में भी स्वीकार किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा और उसके लिये भी समय रखें। आज सी०

वी० गुप्त ने इस बिल की मांग की है कि जूडिशियल कमीशन बिठाया जाए जिसमें इसकी जांच हो कि केन्द्र सरकार उसके लिये कितनी जिम्मेदार है और कितनी राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो यह रीजनल इम्बैलेंस का जो सवाल है यह बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर माननीय मंत्री नमय दें।

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Sir, you are a tribal; they are Harijans and we are women. We are also very backward. The other day we passed the Constitution (Amendment) Bill, extending the reservation period for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Now, there are alarming reports in the country, in different parts, that some reactionary parties—the Jan Sangh and the Akali coalition—are pressurising the Central Government to amend the Hindu Succession Act regarding property rights of women and also they are pressurising the other Governments. I want an assurance from the Central Government that they are not going to yield to this. The Law Minister must make a statement about it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right; you have made your point.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The hon. lady Member need not worry about it. (Interruption)

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA : One more point, Sir. I am making this point seriously : that the women's organisations all over the country are very much perturbed about it. They want an assurance from the Central Government that this is not going to happen and the Government are not going to yield to this.

Another point is this. We read in the papers today that in U.P. 17 SSP members are defying their own party, and there is no majority for Shri C. B. Gupta there. The Governor must convene the Assembly. (Interruption) 17 SSP members have asked for the suspension of their own leader. (Interruption)

SHRI P. GOPALAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, about the decision taken by

the West Bengal Government to give a reception to the NLF delegation—

MR. DEPUTY-SPEAKER : This point has already been made. If you want to raise it separately, it can be discussed at that time. There cannot be any discussion on this subject now.

SHRI P. GOPALAN : I take this opportunity to congratulate the UF Government of West Bengal for giving a grand reception to the NLF delegation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are entering into a discussion now. Shri Sayeed.

SHRI P. M. SAYEED (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands) : Sir, this is a very serious matter, and this subject has not been covered by the Business Advisory Committee. It is this. In Uttar Pradesh, a minority government is functioning under Mr. C. B. Gupta. A section of the people who have called themselves dissidents of the Congress party and some MLAs have already conveyed their assurance to the Governor, and they have all said that Mr. C. B. Gupta is running a minority government. I request that this subject be included in the agenda and it should be discussed threadbare in this House. An opportunity should be given to the House for discussing this matter. (Interruption)

SOME HON. MEMBERS rose—

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ कि गुजरात में जो अभाव-यमन परिस्थिति है, स्केर्मिटी के कारण लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और यह अहमदाबाद के टाइम्स आफ इंडिया का जो एडिशन है उसमें कहा गया है कि 48 आदमी स्टार्वेशन से मर गए हैं सिर्फ बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में तो इसको लेकर इस सदन को कुछ इसका महत्व समझना चाहिये क्योंकि आज मैं देखता हूँ हर जगह यह चर्चा चल रही है कि गुजरात को पैसे नहीं मिलता है और यहां तक कहा जाता है कि डी० एम० के० को खरीदने के लिये कुछ पैसे दिये गए और गुजरात को पैसे नहीं दिया गया, तो

मैं चाहता हूँ कि यह सही है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये।

श्री शशि भूषण (घारगन) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान में व्यक्तिगत सम्पत्ति के मौलिक अधिकारों की समाप्ति के संबंध में इन सदन में चर्चा होनी चाहिये जिसके लिये नाथ पं जी का बिल मांजूद है या अगर नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव लाए या हम लोगों को मौका दें चर्चा करने के लिये।

एक दूसरी बात मुझ कहनी है—भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा एक पूंजीपति के घर में गिरवी रखी हुई है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है कि वह उनसे वातचीत कर रही है। तो इस मामले को फौरन लिया जाए। मैं यह दरखवास्त कर रहा हूँ कि इस पर चर्चा करने का मौका दिया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not think there is anything more to be raised. Everything has been said. (Interruption)

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI rose—

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you agree. I will allow that gentleman one minute and the hon. lady Member one minute. After that, I will call the Minister.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : एक मिनट में भी चाहता हूँ। आपने सब को अनुमति दी है। मुझे भी एक मिनट देने का कष्ट करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : From your party, many hon. Members have made their submission.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो निवेदन करने हैं। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली ने सौतेला व्यवहार किया है।

[श्री जनेश्वर मिश्र]

उत्तर प्रदेश की तरक्की में केन्द्र बाधक हो रहा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। चूंकि मुख्य मंत्री के नाते यह बयान है, इसलिये इस पर यहां चर्चा होनी चाहिये। मैं संसद कार्य मंत्री से कहूंगा कि वे इस पर चर्चा का समय दें कि क्या केन्द्र ने ऐसा व्यवहार किया है? अगर किया है तो वह निन्दनीय है, अगर नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही या चेतावनी दी जानी चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिये बन्द है, यद्यपि यह आपका विषय नहीं है, लेकिन जिस वजह से झगड़ा है—यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के एक मोटर ड्राइवर ने वहां की एक नहकी के साथ बलात्कार किया, इस वजह से यह केन्द्र का विषय हो जाता है। इस पर भी विचार करने के लिये आधा घन्टा या एक घंटे का समय दिया जाना चाहिये।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI

(Bilhaar) : Seeing that the normal civic life in Calcutta has been dislocated and business is paralysed, and the citizen is denied basic things like security of life and seeing that the Constitution is being openly flouted as it happened at the civic reception which the Calcutta Corporation accorded to the President when neither the national flag was unfurled nor the national anthem was sung, can we not have a special session of the Parliament tomorrow or on some other day for two or three hours and give priority to the resolution moved by Shri Guha?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर प्रकाश डाले—इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम पर इस प्रकार की गन्दो फिल्में क्यों दिखाई जा रही हैं जिनका भारतवर्ष के नौजवानों पर बड़ा गन्दा प्रभाव पड़ रहा है.....

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी वहां गया था और मैंने देखा कि सब जनसंघ के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां पर थे, इसमें ऐसी क्या बात है।

So far as the International Film Festival is concerned, we are unable to *tyag* those films. If Mr. Tyagi wants, let him *tyag* them. There is nothing immoral in them.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चों का बिगड़ेगा। आप तो पहले ही बिगड़े-बिगड़ाए हैं।

SHRI RAGHU RAMAIAH : Hon. members have made various suggestions about various matters which they consider important. Some of them were before the Business Advisory Committee when it considered some of these things at the last meeting. In respect of some of them, provision has already been made either in the business of Government or by way of discussions which the hon. Speaker has fixed. I am not belittling any of these items, but it is a question of priorities and time.

SHRI RANDHIR SINGH : Let there be a debate in the House on Chandigarh.

SHRI RAGHU RAMAIAH : If there is any item of great importance which has been left over, I am sure the Business Advisory Committee will again consider such matters.

Mr. Guha raised the point about Mr. Prakash Vir Shastri's part-heard motion. Mr. Prakash Vir Shastri had himself said that he will not be in Delhi today and he had requested the Government to postpone it to a later date. That is why it has been done.

11.45 Hrs.

RE : INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now introduction of Bills. Shri Bhagat.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : On behalf of Shri Bhagat....

MR. DEPUTY-SPEAKER : At the introduction stage the Minister in whose name the Bill stands should be present. Under the rules it cannot be done by some other Minister. So, I will go to the next item.

1.46 Hrs.

BIHAR LAND REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALIDATION BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI JAGANATHA RAO) : I beg to move :

"That the Bill to validate certain provisions contained in the Bihar Land Reforms Act, 1950, and the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1964, and action taken and things done in connection therewith, be taken into consideration."

The Supreme Court in *Baij Nath Kedia vs. State of Bihar* held that (a) to the extent of the topics covered by the Parliamentary legislation [the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957] the powers of the State Legislature are excluded; (b) after the creation of statutory mining leases under the provisions of sections 9 and 10 of the Bihar Land Reforms Act, 1950, any attempt to regulate those mining leases will fall not in Entry 18 of the State List but in Entry 54 of the Union List although it touches land not *vice versa*; (c) the whole field of regulation and development of minor minerals have been taken over under the control of the Union and consequently certain provisions of the Bihar Land Reforms Act, 1950, as amended by the Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1964, and sub-rule (2) of rule 20 of the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1964, as inserted by the Bihar Minor Mineral Concession (First Amendment) Rules, 1964, were struck down.

The Government of Bihar have pointed out that as a result of the aforesaid judgment, the levy and collection of royalty on minor minerals in respect of statutory leases by the State Government under the provisions of the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1964, have not only become void but they may also be required to refund royalty collected by them on minor minerals in respect of those leases which runs into a few crores of rupees. It is also likely that as a result of the general principles laid down in the aforesaid Supreme Court judgment, the proceedings initiated by the State Government to resume unworked statutory lease-holds under section 10(2) of the Bihar Land Reforms Act, 1950, as amended by the Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1965, may be challenged.

In view of the principles laid down by the Supreme Court in the aforesaid judgment, it is Parliament which is competent to frame legislation in regard to matters referred to in paragraph 1 above. The Bill seeks to re-enact and validate the provisions of the State laws specified in the Schedule to the Bill.

Since it is a simple non-controversial Bill it is hoped that it will be passed unanimously.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to validate certain provisions contained in the Bihar Land Reforms Act, 1950, and the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1964, and action taken and things done in connection therewith, be taken into consideration."

It would like to acquaint the House with the time allotment in regard to this Bill. Altogether two hours have been allotted and the division of time is as follows : Congress (O) 12 minutes, Swatantra 8 minutes, Jan Sangh 6 minutes, DMK 6 minutes, CPI 6 minutes, CP(M) 4 minutes, SSP 4 minutes, PSP 4 minutes, UIPG 6 minutes, BKD 2 minutes, Unattached 6 minutes and Government 44 minutes.

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti) : May I know whether the areas which will be

[Shri Jaipal Singh]

affected by this amending Bill will get two minutes ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : During the discussion all this will come into light, I am sure.

SHRI P. G. SEN (Purnea) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, you know that Bihar is suffering under President's Rule and the administration is being carried on from here. Shri Harihar Singh, who has been Leader of the House, approached the Governor with a list saying that he holds the majority in the House. Nobody, I think, has contested that because the list shows majority; still, there is a report, which came here, which says that about 50 members of that list are such upon whom the Government could not rely or who may be said to vacillate to one side or the other. They are members of the Legislature, no doubt. Whether they vacillate or do whatever they like, it is within their right. They can do it. But we find that things have been fomented from the Centre which are having their effect there. Chief Ministers who are having majority find that their powers are being eroded. Some time back the DMK ministry and the ministries in Kerala and Bengal were trying to find fault with the Centre but now, it is very much disheartening to find and it is a disappointing affair, the Centre is trying to find fault with the States. The burning case is that of UP. From the papers I find that the Prime Minister goes there and says that because the UP Chief Minister was quarrelling with the Centre, UP is a backward area, is not getting the proportionate help that it should have got from the Centre. As an instance Shri C. B. Gupta has cited the example of the DMK ministry and said that the Madras Government got Rs. 24 crores out of the Consolidated Fund of India for relief and, I do not know exactly, what as help was rendered to that State, whereas the same amount of or more damage has been done to UP because of floods and other things and UP is the biggest and the largest State in the Union of India, still the proportion of help rendered to UP is far from that for giving help to the rural people there. They are at a loss and it is very difficult affair for them.

This Bill is a very innocent Bill. I am happy over the fact, though Bihar is under

President's rule, that there are two advisers there—Sarvashri P. K. J. Menon and T. P. Singh—for whom I have got the greatest regard. That is one hope. They have been to my area; they toured there and met the people. They are conversant with the area. I was there as Secretary of the District Congress Committee when Shri P. K. J. Menon was the District Magistrate there and I had the opportunity to work with him. I have the greatest regard for him.

I can assure the House for the reforms which have been sent here in regard to the difficulties facing the Bihar Government in regard to the small minerals. Bihar is a mineral area and it is true that we find in papers reports of how mica is being smuggled out. It is a very valuable commodity for export. These areas should be fully developed.

Now we find that the Supreme Court has gone against the executive power of the Bihar Government so far as the small minerals are concerned. The basic matter of the Bill is very good and I am glad to support it. This has been brought under the purview of the Union Government and Parliament to legislate on these matters. As the Lists have separate fields the Supreme Court holds that the Union Government or Parliament is the fittest authority to legislate. If it is not given, the Bihar Government will have to incur a great loss. They have already realised money in respect of these small minerals and if that rule is made void, the Government will have to make repayment of Rs. 5 crores to Rs. 10 crores which the Government is not in a position to do. In that respect, the Bill should receive the support of the House and it should be passed.

What I was going to say, in respect of Bihar, was as to why the Central Government is not allowing Shri Harihar Singh to form the Ministry when he claims a majority. Let the Legislative be called. Otherwise, there is no alternative for you but to go in for another mid-term poll. You must decide one way or the other. Why are you playing with them? Why are you dividing them? You are dividing those who are within the party, those who are loyal elements in the party, and you are instrumental in bringing a bifurca-

tion between them. You are bringing down to the whole of the country by your own actions, here and in all the States. You must take a lesson. As you are showing the example here, the States are doing there.

SHRI JAIPAL SINGH : Sir, on a point of order. I do not know what connection U.P. and other provinces which the hon. Member is mentioning has with this Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : This is not a point of order. It is a part of his speech.

SHRI P. G. SEN : So, my point is, when a mid-term poll has been done, if you do not want another mid-term poll to be held, you must call either of the parties or you call the Opposition to form the Ministry. Why don't you call the Opposition to form the Ministry? If you think that Shri Harihar Singh and others are not in a position to form the Ministry, why don't you call Shri Tiwary or the other S.S.P. leader who had seen the Governor? They can try to form the Ministry.

So far as this Bill is concerned, I welcome the Bill and, I hope, it will be passed by the House.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for calling me to speak on the Bill. Before I begin to speak, let me request you to ascertain whether there is quorum in the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Quorum Bell is being rung... Now there is quorum.

12 Hrs.

SHRI RANGA : Mr. Deputy-Speaker, Sir, there would have been no need for this Bill if the Central Government and its Law Ministry and those Advisers who are associated with the President had done their duty properly and effectively as per the Constitution. They had their own Congress Ministry, their counterpart, in Bihar. That is happening in the case of other States also wherever they have their own Congress Ministries. It is just because they allowed their Advisers in Government and those

associated with the President to go to sleep whenever these Bills came up for discussion in the Legislatures that this Bill has come.

We come across certain objections being raised by the Government only when non-Congress Ministries were in power and proposed certain legislation in their legislatures and then the advisers to the President in the Home Ministry as well as outside woke up, began to be rather watchful and began to examine every Bill in order to see whether that particular Bill came within the ambit of the Constitution or not, within the list of legislation that was specially allotted for the States. But, wherever there were Congress Ministries, they were not bothered at all. Any Bill could be passed in any legislature provided of course the local Government has made itself responsible for introducing it. This is how this legislation also in Bihar came to be passed. That only indicates that the Government here at the Centre has not been functioning as a federal government. It has been functioning in a political manner as a Party government looking into things merely or solely from the Party ends and that led the Constitution to be ignored and led the advisers to the President in the Home Ministry as well as outside also to go to sleep. Worse than that is this. Somehow somebody took it into his head to invoke the court. They went to the Supreme Court. Even then the legal experts of this Government did not have the foresight, did not display the necessary wisdom to admit that this particular legislation was beyond the ambit of the State's powers and therefore, they were prepared not to contest that case at all. On the other hand they were trying to justify this kind of legislation and they persisted with their refusal to accept the truth, to accept the obvious. They fought in the Supreme Court and the Supreme Court in its wisdom decided against the Bihar Government and incidentally also against the Union Government. This is how the need has arisen for this legislation.

What is happening in Bihar? My hon. friend from the Congress Party has already enlightened the House. Is there a Government? Which is the Government in Bihar which has informed the Government of India that if this Bill were not passed now, it would be put to so much loss, crores

[Shri Ranga]

of rupees loss? Is it the advisers' Government or the previous representative Government? Why should there be this advisers' Government? Now in the very beginning when this question was being mooted there whether there should be advisers' Government or not and whether the legislature should be suspended or not, a group of people came together, a group of political parties came together under the leadership of Mr. Harihar Singh and offered to form a Ministry and showed evidence of there being a majority behind them. We thought a Ministry was going to be formed. Suddenly something happened within the Congress Party and as a result of their political upsets, they have been preventing a Ministry being formed there. One can understand if these two sections within the Congress go on fighting on the all-India level. Is it necessary for them to go on fighting at the State level also? All right, even if they want to fight there, is it not possible for them to think in terms of working together along with non-Congress political Parties in a coalition and help Bihar people to have a representative Ministry, a coalition Ministry responsible to the legislature and in that way help that legislature to begin to function effectively? It is the cussedness and the partisanship and the vindictive spirit and un-cooperative attitude of the ruling group within the Congress even at the Centre that they should perpetuate this kind of unsettled conditions in Bihar.

They make it impossible for Bihar to have a real Government, a good Government, a people's Government. In the name of a Government which is not people's Government at all, a Government that is being run at the behest of the ruling party here, but in the name of the poor President, in the name of Rashtrapathi there, they just come here and say: Bihar Government is likely to lose crores and crores of rupees if you do not pass this legislation. Now if they are somehow managing to carry on without this legislation here at the Centre, why should not the Government wait for another 4 months or 3 months or 2 months, or at the worst, 6 months for this legislation to be placed on the Table of the House? They have brought it forward here because of their evil designs, because of their wrong intentions

which they keep as a secret of not enabling Bihar to have a really full-fledged representative Government in the next 6 months. That is the game behind this Bill. If they are really keen about having a Government there as soon as possible, a Government which is representative, a Government which would be backed by the legislature, it need not be a Government representing one party or even two but there can be a number of parties, getting together into a coalition. It is not such a new thing either, for, Bihar has had the experience of a number of coalition Ministries. It should be the primary duty of the Government of India to explore every possible way to see that representative Government is formed there by viable coalition. Instead of that Minister after Minister—not one Minister but four or five Ministers—go there on official duty simultaneously. They go like a gang of thieves—but they are Ministers, how can I say that they are thieves? but they may be thieves in political terms; we do not know—but anyhow, a group of 4 or 5 Ministers go there in order to prevent a representative Government, a Coalition Government, from coming into existence in that State.

This is the most heinous thing that any representative Government can possibly try to do. They claim here to be a representative Government, but they are not really representative also because it is a minority Government. They want to perpetrate their insult on the constitution and they are following their own practice by preventing a representative coalition Ministry from coming into existence in Bihar.

My fear is this. They want to continue the present arrangement for another 6 months. Otherwise there would not have been any need at all for this legislation. I would like to call upon the Government to give us a clear assurance that this Government will not perpetrate the absence of a representative Government in Bihar but that they will consider it their constitutional duty and politically their sacred duty to help the legislature there to provide for those people a representative Government, a coalition Government which would be representative of the legislature and enable that legislature also to function in a normal manner. Thank you.

श्री बृजभूषण लाल (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिहार लैंड रिफार्मस लाज (रेगुलेटिंग माईन एंड मिनरल्स) बिलिडेशन बिल, 1969 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैज नाथ केदिया के केस में दिय गए जजमेंट के कारण से लाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बिहार सरकार द्वारा माइनर मिनरल्स पर लगाई गई लेन और क्लैमसन आफ रायल्टी न केवल वाएड हो गई है बल्कि उन्हें इस रायल्टी रिफंड भी करनी पड़ सकती है जो कि कुछ करोड़ रुपये की है। कई करोड़ रुपया बतौर रिफंड के उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी एक झुबहा पैदा हो गया कि उस जजमेंट में जो जनरल प्रिंसिपल्स के डाउन किये गए हैं उनकी रोजनी में बिहार सरकार द्वारा अनवकंड स्टेबुटरी लाज-होल्डर्स रेंजूम करने के लिये जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं वह भी चैलेंज की जाएंगी।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) :
There is no quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member Shri Brij Bhushan Lal may resume his seat now. There is no quorum. The bell is being rung—

The hon. Member Shri Brij Bhushan Lal may now resume his speech.

श्री बृजभूषण लाल : यह भी सवाल पैदा हुआ था कि जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं अनवकंड स्टेबुटरी लाज होल्डर को रिन्यूम करने के बारे में उनको भी चैलेंज किया जा सकता है। इन सब बातों की वजह से गवर्नमेंट को यह बिल लाना पड़ा है। चूंकि वह सब चीज बिहार गवर्नमेंट की पावर में नहीं थीं, इस वास्ते आपको उस चीज को बैलियेट करने के लिये इस बिल को लाना पड़ा है। इसका तात्पर्य समर्थन करता हूँ, लेकिन इस सिजसिले में दो-तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक बार एक्ट बना दिया गया और पावर हासिल करली गई रायल्टी वसूल करने की तो क्या वह पावर बहुत सोच-विचार के बाद हासिल नहीं की गई? क्या वहाँ पर ला मिनिस्ट्री नहीं है? जब भी कोई इस तरह का बिल लाया जाए और इस तरह की पावर ली जाए तो सारे प्रास एण्ड कांज को थारोला कंसिडर करके ऐसा करना चाहिये। काबिल और होशियार आदमी वहाँ पर भी हैं। हर एक पहलू को पहले से देख लिया जाना चाहिये कि किसी भी बिल की कांस्टीट्यूशनल पोइजिशन क्या है। अगर किसी विषय पर पार्लियामेंट लैजिस्लेट कर सकती है और स्टेट असम्बली नहीं और बाद में यह चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है और जब वह चीज वायड डिक्लेयर हो जाती है, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। पार्लियामेंट की जो पावर है, उनको स्टेट गवर्नमेंट को युजमें नहीं करना चाहिये। जब ऐसा हो जाता है तो कितना रुपया बरबाद होता है। इसको आप देखें। ला मिनिस्ट्रीज हैं और ला मिनिस्टर हैं। फुल डिपार्टमेंट हैं, जो इन चीजों को देखते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि कांस्टीट्यूशनल पोइजिशन पर पूरी तवज्जह नहीं दी जाती है। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, इसको अगर पास न किया गया तो करोड़ों रुपया बिहार गवर्नमेंट को अदा करना पड़ेगा। इसलिये इसका तो मैं समर्थन करता हूँ लेकिन यह चीज जो है, इसकी तरफ भी गम्भीरता से ध्यान आगे से दिया जाना चाहिये।

बिहार में जो लैंड रिफार्म एक्ट है उसकी प्राविजंज से जमशेदपुर को बाहर रखा गया है। जमशेदपुर को उसकी जड़ से बाहर निकाल दिया गया है। यह डिस्टिंकशन क्यों किया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। वहाँ के लोगों को इसका एडवांटेज क्यों नहीं मिलना चाहिये? क्या सिर्फ इसलिये कि

[श्री बृजभूषण लाल]

वहां कोई विंग-विजनैसमें है। यह उचित नहीं है। जमशेदपुर को इस तरह से एक्स-क्यूड करना ठीक नहीं है। लैंड रिफॉर्म की प्राविजंज जमशेदपुर पर भी लागू होनी चाहिये। डोरी माइंड में जो दुर्घटना हुई उसमें कोई सौ आदमी मारे गए थे। जो कमीशन बैठा था उसकी रिपोर्ट में इस दुर्घटना का कारण नैग्लिजेंस बताया गया था। उन माइंड का जो ओनर था वह श्री कामाख्य नारायण सिंह था। उनकी नैग्लिजेंस की वजह से यह हुआ था। जब रिपोर्ट आ चुकी है और नैग्लिजेंस साबित हो चुकी है जिसकी वजह से सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे, तो क्या कारण है कि ओनर के खिलाफ प्रोसीक्यूशन लांच नहीं किया जाता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ लॉगल प्रोसीक्यूशन लांच की जानी चाहिये। किसी भी दोषी व्यक्ति को स्पेयर नहीं किया जाना चाहिये।

बिहार में प्रेजीडेंट्स कूल है। आपने असेम्बली को वहां सस्पेंड कर रखा है। क्यों आपने यह नीति अपनाई हुई है? क्यों नहीं आप वहां पापुलर गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। आप वहां एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिये मौका दें ताकि वहां प्रजातंत्र की स्थापना की जा सके। जो पार्टी वहां मैजोरिटी में हो, उसको मिनिस्ट्री फार्म करने का मौका आप दें ताकि पब्लिक को संतोष हो और वह समझे कि वहां भी पापुलर गवर्नमेंट है। यहां से डिक्लेट नहीं किया जाना चाहिये।

इस शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर

बिहार गवर्नमेंट को पावर नहीं थी रायल्टी वसूल करने की और उसको वैसे ही रहने दिया जाता तो बिहार को करोड़ों रुपया जो उसने एकत्र किया था, वापिस करना पड़ता। इस वानून के मुताबिक उसकी इस कार्रवाई को बंध करार दिया गया है और अब उसको जो रायल्टी उसने वसूल की है, उसको वापिस नहीं करनी पड़ेगी। आगे भी वह रायल्टी लेती रह सकेगी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बिहार की केन्द्रीय सरकार ने घोर उपेक्षा की है। केन्द्रीय सरकार ने बिहार को जब-बूझ कर बैकवर्ड बनाया है। बिहार में पर कॅपिटा इनकम लोएस्ट है, हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में। बहुत ही दयनीय स्थिति बिहार की केन्द्रीय सरकार ने बना दी है। कोई भी इसके लिये दोषी है तो केन्द्रीय सरकार दोषी है और वह केन्द्रीय सरकार जो कि केन्द्र में आजादी के बाद से सत्तारूढ़ रही है, दोषी है। ये बहुत ही दुःख की बात है। मिनरल्लज के मामले में बिहार सब से धनी राज्य है हिन्दुस्तान का। नोहा और कोयला वहां बहुत ज्यादा होता है। उस मामले में वह सब से धनी है। यूरेनियम दुनिया में सब से ज्यादा वहीं पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के काम में आता है। बावजूद इस सब के बिहार को उपेक्षा की गई है। मोटे तौर पर बिहार की और खास तौर पर नार्थ बिहार की उपेक्षा की गई है। उसको बहुमत ही बैकवर्ड बना दिया गया है।

वहां पर लोहे की खाने हैं और टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी है जो बहुत भारी कम्पनी है। टाटा का इंडस्ट्रियलाइजेशन था दूसरे मामलों में चाहे जो भी कॉर्पोरेशन रहा ही, अब समय आ गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी की जो ज़मींदारी है, उसको समाप्त किया जाए। आज बिहार की

जनता की यह मांग है, समाजवाद का यह तकाजा है, हिन्दुस्तान की यह आवाज है। इस वक्त वहां राष्ट्रपति का शासन है और मैं चाहता हूँ कि आप टाटा की जमींदारी का खात्मा करें। ईमानदारी से माइंड एंड मिनल्स के बारे में आप कोई सही नीति अपनाना चाहते हैं तो टाटा की जमींदारी को आप खत्म करें। टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का आप नेशनलाइजेशन करें। दूसरी जो खान हैं, कोयले को जो खाने हैं और जो प्राइवेट सैक्टर में हैं, उनको सरकार अपने हाथ में ले। राजा रामगढ़ के बारे में मघोलकर कमीशन की रिपोर्ट निकली है। उसमें चार्ज लगाए गए हैं। जिस तरह से वह पैसा बनाते हैं उससे न सिर्फ वहां की जनता पिस रही है बल्कि वहां की राजनीति को भी वह भ्रष्ट कर रहे हैं। फिर भी केन्द्रीय सरकार रामगढ़ के राजा के खिलाफ कार्रवाई करने की और उनको सजा दिलाने की बात नहीं सोच रही है। यह बहुत दुख की बात है। उसकी जो माइंड हैं वहां बड़ी बेइन्साफी हो रही है। सरकार का फर्ज है कि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी को तथा जितनी प्राइवेट सैक्टर में माइन्ड हैं, खाने हैं, अन्नक की, कोयले की तथा दूसरी, उन पर सरकार अपना कंट्रोल स्थापित करे, उनको नेशनलाइज करे। ऐसा किया गया तभी बिहार की तरक्की हो सकती है।

संविद की सरकार ने टाटा कम्पनी के खात्मे के लिये एक विधेयक तैयार किया था, लेकिन वह उसको ला नहीं सकी। वह विधेयक पास नहीं करा सकी। अभी वहां राष्ट्रपति का शासन है। आप इसको कर सकते हैं।

यदि आपको जन्तंत्र से मुहब्बत है, यदि आप जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो वहां आप लोकप्रिय सरकार की स्थापना करें। आपके जो कांग्रेस दल हैं वे अलग-अलग लिस्ट दे रहे हैं। हरिहर सिंह जी तथा दूसरे की जो लिस्ट हैं वे वोगस लिस्ट हैं। उनको सरकार

बनाने का मौका देने की बात ही नहीं होनी चाहिये। आपके जो पिछलग्गू हैं वह भी निकम्मे हैं। इसीलिये जनतंत्र का वहां तकाजा है कि विरोधी दलों को एक बार मौका और दिया जाए कि वह सरकार बनाएं। विरोधियों में खास कर के बड़ी पार्टी एस० एस० पी० है। उसको मौका मिलना चाहिए कि वह बिहार में सरकार बनाए। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये उनकी सरकार नहीं चलती है। नहीं चलती है तो खत्म हो जाएगी। इसमें ऐसी कौनसी बात है? लेकिन एक बार मौका उसको मिलना चाहिए ताकि संविद सरकार ने अपने पहले टर्म में टाटा की जमींदारी खत्म करने का रास्ता अख्तियार किया या, और जनता के हित के काम करने शुरू किये थे, उन कामों को वह पूरा कर सके। साथ ही साथ बिहार को इन्होंने पिछड़ा बनाया है, बिहार के साथ इन्होंने बेइन्साफी की है पिछले 22 सालों में, यदि आज बिहार फँसला कर ले तो सारे हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था को हम पैरालाइज कर सकते हैं, देखते-देखते हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था पैरालाइज हो सकती है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में इतना धनी होने के बाद भी राजनैतिक और आर्थिक तौर पर बिहार को आज पीछे गिराया है, क्या बिहार को आज एटामिक प्लान्ट लगाने का हक नहीं है, जब कि वहां यूरेनियम है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कई बार यह बात उठाई गई है, मेरा बिहार एटामिक एथारिटी विधेयक भी यहां पेश हो चुका है, सरकार का यह फर्ज है कि वहां पर एटामिक प्लान्ट वह लगाए। उत्तरी बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एक बरौनी को छोड़ कर और जितना ही उत्तर में चले जाएं, पिछड़ा इलाका मिलता चला जाएगा। यातायात की सुविधा भी वहां नहीं है। वहां पर आम और नीची का भंडार है और एक कैनिंग फ़ैक्ट्री आसानी से वहां लगाई जा सकती है और भी दूसरे उद्योग वहां चल सकते हैं। अभी रेशम उद्योग के बारे में बात कही गई थी। उत्तरी बिहार में रेशम के भी बड़े अच्छे दुनकर हैं और

[श्री सिध चन्द्र झा]

रेशम का उद्योग भी वहाँ बड़ा अच्छा चल सकता है। लेकिन वहाँ और रेशम का उद्योग खोलने को कौन कहे, भागलपुर में जो यह उद्योग है उसकी भी हालत खराब है। इस तरह से बिहार और खास कर के उत्तरी बिहार को इस सरकार ने पिछड़ा बनाया है। इस विधेयक के ज़रिए यदि आप करोड़ों रुपये बचाना चाहते हैं तो जितने वहाँ माइन्स हैं, कोयला, लोहा वगैरह के जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करें, तभी वास्तव में आपकी ईमानदारी समझी जाएगी।

12.25 hrs.

At this stage some persons from the Victors' Gallery threw some leaflets on the floor of the House.

DR. RAM SUBHAG SINGH : What has happened may be taken note of.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Some people have thrown some pamphlets.

SHRI JAIPAL SINGH : This is the first opportunity I have to congratulate you. I am very glad that at long last an Adivasi is in the Chair. I hope Adivasis will be occupying other gaddis also throughout the country.

I have been very surprised at the irrelevant speech that has been made over this Bill. This Bill affects Jharkand. Jharkand is the richest mineral belt in the world. Everything is there. There is nothing that is not there.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Including poverty.

SHRI JAIPAL SINGH : Yes, not poverty of the heart.

I regret I cannot go all the way that my very old friend Shri Ranga did, although I do believe that there is some truth in what he has said. Let us not talk about Congress Ministries and ex-Congressmen's Ministries. They have all been in the Congress. What has hap-

pened is that they cannot get together. Congressmen have been caught out, ex-Congressmen have been caught out, and we are victims in Jharkand.

This colonial empire of the Bihari must disappear. There must be a Jharkand State. Then only there will be happiness in that area. Much is said about representative Government. I am very happy that there is President's rule. As far as Jharkand is concerned, we are for a change, for getting some justice, otherwise these Biharis would not be here today. Let me point out to them. I can give facts and figures as to how Members of Parliament here, when they belong to committees, just go there to get their sons and daughters and nephews and nieces and in-laws also jobs there as though we are no good.

Sir, I am afraid hon. Members do not quite realise the significance of this Bill. What has happened? It does not matter which Ministry was there. The fact is that teachers, professors, and even other Government civil servants have not been paid for months. For months they have not been paid. I suggest that we pass this Bill unanimously. I admit the mistake that has been made in the State, just as mistakes are often made by the Centre also. The Bills that are pushed through Parliament here because of a majority there are held invalid by the Supreme Court. Prof. Ranga is perfectly correct in saying this: what is the Law Ministry there for? Do they not understand the Constitution, the implications of the Constitution, if certain legislation is passed, whether it is in order or not in order? Well, I do not wish to say more. All that I say is, let us pass this Bill unanimously so that people who have not been paid for six months, eight months, at least might get their pay. Let us not harp on the fault of the Congress Ministry or any other Ministry or even the Central Ministry. If we go into the details like that, I regret to say that I think the fault is more on this side than on that side.

Thank you.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह

कहना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास ब्यूरोक्रेसी में कतई नहीं है और जब तक ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कहीं की भी सरकार रहे, चाहे वह बिहार की हो या कहीं की भी हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हाथ ऊंचा रहे तो कभी भी देश का और जनता का भला नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा अपना ख्याल है कि चाहे किसी तरह भी हो वहाँ जितनी पार्टियाँ बिहार में हैं वह सारी पार्टियाँ इस बात के लिये कोशिश कर रही हैं कि वहाँ एक सरकार बनाएं, अभी तक उन्हें कामयाबी इसलिये नहीं मिली कि वहाँ के गवर्नर साहब इस निश्चय पर नहीं आ सके कि कौनसी पार्टी मेजारिटी में है, लेकिन जो भी पार्टी मेजारिटी में हो, उस पार्टी के ज़िम्मे यह काम देना चाहिये जिसमें कि वह बिहार का भला कर सके। राजनैतिक कंसिडरेशंस जो हैं मिनिस्ट्री बनने या न बनने में उस दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिये और खास करके गवर्नर को इस दृष्टि से उस पर विचार नहीं करना चाहिये। बिहार के दो हिस्से हैं। उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। (व्यवधान) झारखंड भी है और झारखंड की भी एक मांग है कि झारखंड को अलग किया जाना चाहिये। इस बात में भी अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिये यह तय करने में कि झारखंड होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। जो कुछ हो, चाहे उसको होना चाहिये, वह भी बात कह देनी चाहिये, नहीं तो यह आन्दोलन पहले शुरू में तो बहुत छोटा मालूम होता है लेकिन आगे चल कर के इसका रूप विशाल हो जाता है जैसे आन्ध्र में हो रहा है या हरयाने और पंजाब को लेकर हुआ है। इसलिये इस तरफ भी ख्याल जाना चाहिये जैसा कि अभी जयपाल सिंह जी ने भी कहा।

दूसरी बात यह है कि बिहार के जो दो हिस्से हैं, उसमें दक्षिणी हिस्सा खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। बहुत-से हमारे भाई लोग दो बानें खास कर के कहा करते हैं। एक

यह कि पब्लिक सेक्टर में इसको ले लिया जाए और दूसरे कारपोरेशन बना दिया जाए। कारपोरेशन के तो मैं इतना सक्त खिलाफ हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर मेरी चले तो मैं इसी वक्त जितने कारपोरेशन हैं सब को स्कैप कर दूँ क्योंकि कारपोरेशन का जो चैयरमैन है वह जितनी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके सब मिनिस्ट्रों के बराबर है।

एक माननीय सदस्य : अगर कारपोरेशन का चैयरमैन आपको बना दिया जाए तो ?

श्री क० ना० तिवारी : मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का काम हो। मैं इसके खिलाफ हूँ। जब आम लोगों से बात होती है तो लोग समझते हैं कि जो कारपोरेशन्ज़ के चैयरमैन हैं, वे जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ के मॅम्बर्स अगर किसी बात को चाहें, यहाँ के मिनिस्ट्रज़ अगर किसी बात को चाहें, तो मेरा ख्याल है कि नाक रगड़ कर रह जाएंगे, उनका काम बड़ी मुश्किल से होगा। अगर वह किसी जायज बात को भी चाहेंगे तो भी वह होनी मुश्किल है। यहाँ आप किसी भी मिनिस्ट्र से बात करके देख लें। कारपोरेशन्ज़ के चैयरमैन सुपर-मिनिस्ट्रज़ हैं। यह बात पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में कही जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पब्लिक सेक्टर के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं उसके मॅनेजमेन्ट के खिलाफ खरूर हूँ। जिस तरह से आज पब्लिक सेक्टर के मॅनेजमेन्ट का काम हो रहा है—गांधी जी कहा करते थे—खाओ उतना जितना हज़म कर सको, उतना न खाओ कि अजीर्ण हो जाय या स्वास्थ्य खराब हो जाए। आप इस समय जितना काम पब्लिक सेक्टर में उठा चुके हैं, पहले उसको अच्छी तरह से कीजिये, जब उसका प्रबन्ध अच्छी तरह से हो जाता है, तब आगे बढ़ कर दूसरा काम लीजिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी इकानमी मिक्सड इकानमी है। या तो आप प्लान कीजिये कि आपने अपनी नीति में परिवर्तन किया है,

[श्री क० ना० तिवारी]

आपकी नीति अब मिक्स्ट इकानामी की नीति नहीं रही, आप सभी चीजों को पब्लिक सैक्टर में लाना चाहते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिये कि मैं पब्लिक सैक्टर के खिलाफ हूँ और प्राइवेट सैक्टर के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं यह जरूर देखता हूँ कि हमारी आमदनी पर-कैपिटा नहीं बढ़ रही है, उसमें भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है और बिहार में भी उत्तर बिहार की हालत दक्षिण बिहार से भी खराब है। वहाँ कोई भी इण्डस्ट्री—स्माल, मीडियम या बिग—कुछ नहीं है, सिवाय वरीनी के। बिहार की डेवलपमेन्ट में इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक बिहार सरकार भारत सरकार के हाथ में है—इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

लोगों का ख्याल है कि जमीनों के बटवारे से ही अन-एम्प्लायमेन्ट कम होगी या उसकी समाप्ति होगी, लेकिन मेरा ख्याल है और दुनिया का इतिहास भी यही बतलाता है कि जब तक इण्डस्ट्रीज नहीं बढ़ेंगी आप जमीन का बटवारा चाहे जितना कर लीजिये, अन-एम्प्लायमेन्ट की समस्या हल नहीं होगी। बिहार में जो इण्डस्ट्रीज हैं उनमें बिहार के लोगों को काम नहीं मिलता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और समझता हूँ कि इसको अवश्य पास किया जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कौरम नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell is being rung—Now there is quorum. Mr. Khushwah.

श्री यशवंतसिंह कुशवाह (भिण्ड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं शासन से दो बातें निवेदन कवेरना चाहता

हूँ। एक तो यह कि काफी समय से वे लोग जो खदानों में काम करते हैं या जो खदानों की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी मांग रही है कि खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए—यह शासन के लिये भी हितकर है और श्रमिकों के लिये भी हितकर है। देश की तरक्की के लिये भी यह आवश्यक है कि देश की भूगर्भ सम्पत्ति का अधिक से अधिक शोषण किया जाए ताकि देश की तरक्की के लिये रास्ता प्रशस्त हो सके। जब दूसरी दिशाओं में राष्ट्रीयकरण की बातें सोची जाती हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जब कि उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, फिर भी राष्ट्रीयकरण करने में उसको प्राथमिकता दी गई तो समझ में नहीं आता कि देश की प्रगति के लिये जो आवश्यक चीज है—देश के खदानों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरफ अब तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि शासन की तरफ से राज्यपालों को इस बात की पूरी तरह आज्ञादी रहनी चाहिये कि वे अपने इंग से काम कर सकें और केन्द्र के राजनीतिक कारणों से वे प्रभावित न हों। यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि अगर आज केन्द्र से कांग्रेस, जो शासन पक्ष में है, उसकी गवर्नमेंट वहाँ पर (बिहार में) बन सकने की सम्भावना होती तो शायद बिहार के राज्यपाल की भाषा दूसरी होती। लेकिन जब आज दूसरे कांग्रेस पक्ष के सरदार हरिहर मिह इस बात का दावा करते हैं कि हम सरकार बनाने में सक्षम हैं, तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जाता? परीक्षण के तौर पर ही उनको मौका दिया जाता है और देखा जाता कि वे सरकार बना सकते हैं या नहीं। जनता की गवर्नमेंट वहाँ पर आए—इसके लिये केन्द्रीय शासन को किसी भी तरह की अड़ों की नीति नहीं अपनानी चाहिये। और जितना सम्भव हो, उतनी सहायता की नीति अपनानी चाहिये। इन दो निवेदनों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

12.38 Hrs.

ADJOURNMENT OF THE HOUSE

श्री कौकर सिंह (मटिष्ठा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि कल ईद थी, जो हमारे मुसलमान भाइयों के त्यौहार का दिन माना जाता है, उस सिलसिले में इस सदन की बैठक एडजान हो गई थी। आज गुरु तेगबहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस है, गुरु पर्व है, जिनको हम हिन्दू की ज़रूर समझते हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी याद में आज हाउस एडजान होना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly listen to me for one minute. This is not relevant. I would request him to resume his seat when I am on my legs.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, I endorse him and support him. This is a secular government and every religion should have equal opportunities.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सरदार कौकर सिंह ने जो कहा है, वह बिलकुल ठीक है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. Let all hon. Members resume their seats.

श्री कौकर सिंह : हम गुरु तेगबहादुर जी महाराज को हिन्दू की ज़रूर समझते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are in the midst of the discussion of a Bill. I thought the hon. Member was raising a point of order with regard to the Bill or in regard to what some other members have said about the Bill. But he is raising something very different which can be discussed on a different occasion.

श्री कौकर लाल गुप्त : कल राज्य सभा में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था, उसके बाद छुट्टी की बात आई। आप सरकार से पूछिये कि वह इसके लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री रणधीर सिंह : यह डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please help me to conduct the business of the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Let the government give their view.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Members to approach the Minister of Parliamentary Affairs with the request that this may be included for discussion. But let us not interrupt the discussion on this Bill. We will take it up at the appropriate time.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You ask the Government.

DR. KARNI SINGH (Bikaner): The same thing happened yesterday. Somebody raised the point and you adjourned the House. Why should a separate yardstick be followed for different communities?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Government proposed yesterday.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: No, the Government did not propose. It was Shri Randhir Singh who suggested that.

SHRI RANDHIR SINGH: I suggest it even today.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yesterday the proposal was made but not in the midst of a discussion of another matter. Now we are in the midst of a discussion of a Bill. Let us finish this.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buzar): You were not present here when the proposal was made yesterday. It was not only the Minister of Parliamentary Affairs of the Prime Minister who came and agreed but the entire House agreed to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not in the midst of a discussion.

DR. RAM SUBHAG SINGH: If those people did not know and if the Government did not agree to have today as a holiday... (Interruption).

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can censure the Government on that or bring up another motion but not in the midst of a discussion.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I support Shri Kikar Singh. Today is the day when Guru Teg Bahadur made the supreme sacrifice and the House should be adjourned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us finish this Bill... (*Interruption*).

12.41 Hrs.

BIHAR LAND REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALIDATION BILL—contd.

SHRI HIMATSINGKA (Godda): Mr. Deputy-Speaker, Sir, in view of the decision of the Supreme Court I have no alternative but to support this Bill but while I do so I just want to invite the attention of Government to the casual manner in which the Bills are rushed through the House. Not much care is devoted to examining the provisions of the Bill and no one gives any kind of attention to the provisions of the Bill; as a result, a large number of Bills are being struck down by the High Courts and the Supreme Court. Therefore what is necessary to avoid this kind of decisions from the courts is that proper attention should be given when a measure is being discussed in the House and proper time should be allowed to Members to discuss the same. They should not be hustled and stopped from putting forward what they want to say.

This is one of the simple pieces of legislation for the lawyers of the two governments, the Bihar Government and the Central Government, to examine the position so that this could have been avoided. To bring forward a measure to make it effective from the very first day the Bihar law was passed seems rather very awkward, but we have to support it in view of the difficulties which, otherwise, the Bihar Government would be put to.

I feel that greater attention is required to be given to legislative measures which are discussed in this House and in other Legislatures which, unfortunately, is not

being done. Very important legislation affecting the whole country and economic questions are rushed through without much attention being allowed to be given to them. But because of the difficulties which will be innumerable and the Bihar Government will be placed in an awkward situation I support this Bill. However, I request the Government to allow sufficient time to Members in this respect.

Then, I am rather amazed at the attitude of the Central Government in the matter of a popular government being allowed to be established in Bihar. Shri Harihar Singh, one of the members who has been elected the leader of the party, has been very definitely stating that he has got a majority but somehow or other the Central Government is not allowing the Governor to invite him to form a ministry. Attempts are being made to set up another set of persons and to put forward that gentleman to be invited by the Governor. That does not seem to be very fair in the circumstances. When Governor's rule is there, every possible opportunity should be given for a popular government to be established so that people may have their own representatives functioning as the government and the present state of affairs in the State may come to an end. As a matter of fact, at the present moment not one single grievance is being attended to by officials. I personally complained to the Adviser about particular case giving definite proof of money having been taken. But even the letter has not been acknowledged. This is the state of affairs under the President's Rule. Therefore, it is high time that Government takes steps to allow a popular Ministry to be installed there by the party which has got the majority; Mr. Harihar Singh is claiming a majority; another person is also claiming a majority. So far as we know, Mr. Harihar Singh has got the majority and he should be invited to form the Ministry. If he cannot form the Ministry, then, of course, somebody else should be given an opportunity to form the Ministry. Why should the matter be delayed simply because he is not in tune with the wishes of the people in power here, I feel this kind of discrimination should not be made and an opportunity should be given for a popular Ministry to be installed there.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का दो बातों से सम्बन्ध है। एक तो खान से और दूसरा भूमि सुधार से। बिहार में भूमि सुधार कानून होने के बावजूद वह इतना लंगड़ा कानून रहा कि वहां पर जमशेदपुर में आज भी टाटा की जमींदारी कायम है। वहां पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ है, वहां पर मध्यवर्ती के रूप में टाटा आज भी कायम है। अगर वहां पर कोई जमीन खरीदना चाहे तो वह टाटा की आज्ञा से। वह टाटा की जमींदारी में रहता है, बिहार सरकार से उसका कोई सांधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार कुछ हिम्मत करती। मैं जानता हूँ कि सिन्डीकेट के जो मज्जन इधर आए हूँ उनका भून अभी उस तरफ छूटा नहीं है। सरकार आज भी टाटा से डरती है। यही वजह है कि 26 दिनों से जमशेदपुर में हड़ताल चल रही है और भारत सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि अपने एजान को लागू करा गके। यही कारण है कि जमींदारी आज भी वहां कायम है 22 सालों के बाद भी और भूमि सुधार कानून में यह संशोधन करने की आवश्यकता है कि जमशेदपुर से जमींदारी हटा दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इस बात की कोई गुंजाइश नहीं की गई है। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे विधेयक के जरिए इस बाज को लाने की कोशिश की जाएगी।

सदन को यह भी मालूम है कि बिहार में खान के मामलान में जो मुजरिम है, राजा कामाख्या नारायण सिंह जोकि इस कानून के मातहत डोरी खान के मालिक थे, जहां पर सैकड़ों मजदूर मर गए, मुधोलकर कमिशन ने उसकी जांच की और वे मुजरिम पाए गए। लेकिन आज भी वे छुट्टा घूम रहे हैं। मिनिस्ट्री बनाने में भी शायद उनको जगह दी जाएगी। अब मुधोलकर आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दी है। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार हिम्मत करेगी और उनको मुहाले

बनाकर कचहरी में खड़ा करेगी। जो मुजरिम साबित हुआ है उसके हथकड़ी लगनी चाहिए। हमारे बिहार के जो बड़े-बड़े नेता हैं, सिन्डीकेट के जोकि मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, अइयर रिपोर्ट आने वाली है और उनको भी हथकड़ी लगाने का मौका आ रहा है। वे भी हथकड़ी पहन कर जेल की चहारदीवारी के अन्दर जाएं। (ब्यवधान)

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, अइयर आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं निकली है इसलिए उसमें क्या फसला होगा, क्या नहीं होगा वह अभी कहना अनुचित होगा।

That is a *sub judice* case. The Ayyar Report has not yet come out. To anticipate what the Ayyar Commission will say is most improper.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai) : He has referred to the Mudholkar Commission's Report which has found the Raja of Ramgarh guilty of misusing power (Interruptions). Such a person should not be allowed to join any Ministry. This is our charge against the Syndicate, that they are trying to form a Ministry with such people. . . . (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member referred to the Mudholkar Commission's Report which has been published. There is no point of order.

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अभी हमारे मित्र और विपक्षी कांग्रेस दल के नेता डा० राम सुभग सिंह ने भी यह कहा है कि बिहार में मन्दीमंडल बनाने का मौका श्री हरिहर सिंह को दिया जाए तो उन के एक मजबूत स्तम्भ राजा कामाख्या नारायण सिंह मुधोलकर कमिशन की जांच के आधार पर मुजरिम साबित हुए हैं . . . (ब्यवधान)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : He referred to the Aiyer Commission also.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Aiyer Commission has yet to give its findings. He

[Shri Yogendra Sharma]

is saying that it will be coming sometime in the month of January. That is what he has said.

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Moreover, he has said that other Ministers also will get handcuffed after Aiyer Commission report comes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Anyway I would request Mr. Jha not to say anything by way of anticipating about what a Commission that is inquiring into the matter is going to say or not going to say. If you refer to a report that is already published, that is all right but don't anticipate anything.

DR. RAM SUBHAG SINGH : The Ministers whose cases were examined by the Mudholkar Commission were in the United Front Ministry which had your own Party Ministers and they worked with your Party people.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Mudholkar Commission's findings are that the Ministers of the United Front Ministry have acquitted themselves even better than what their admirers expected.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Raja of Ramgarh was in your Ministry.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Mr. Bholu Paswan Shastri said that the Raja of Ramgarh should not be taken into the Ministry. He staked his Ministry on the question of Raja of Ramgarh. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is no point of order. He is making his own points. You had your opportunity. I will request you to kindly co-operate in allowing him to conclude.

श्री योगेन्द्र शर्मा : जैसा मैं कह रहा था कि बिहार में खान के मामले में जो मुजरिम हैं, राजा कामाख्या नारायण सिंह जोकि इस कानून के मातहत डोरी खान के मालिक थे, जहाँ पर सैकड़ों मजदूर मर गए, मुधोलकर कमिशन ने उस की जांच की थी और वे उस में मुजरिम पाए गए लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी वे छुट्टी घूम रहे हैं और मिनिस्ट्री

बनाने में भी शायद उन को जगह दी जाएगी। पिछली बार भी वह मिनिस्टर बने थे बड़ी मुश्किल से उन्हें कहीं जाकर हटाया जा सका था। मुधोलकर कमिशन ने इस कामाख्या नारायण सिंह को मुजरिम और भ्रष्टाचारी पाया है। ऐसे मुजरिम का नाम हरिहर सिंह ने अपने मन्त्रीमंडल की प्रस्तावित सूची में बतौर मन्त्री के रक्खा है। जनता पार्टी के राजा कामाख्या नारायण सिंह का नाम श्री हरिहरसिंह की सूची में है जिन्हें कि वह बतौर मन्त्री के अपने मन्त्रीमंडल में लेना चाहते हैं। यह चीज बिहार का लोकमत सभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यह ऐसे मुजरिम लोग जिन्होंने कि बिहार को पिछले 22 सालों से लूटा है और जिन्हें कि मुधोलकर आयोग ने दोषी व मुजरिम पाया है वह मिनिस्टर बने। मेरा विश्वास है कि अय्यर आयोग भी इन को मुजरिम करार देगा और यह हथकड़ियां पहनेंगे। मैं नहीं जानता कि उस अय्यर आयोग का क्या फसला होगा लेकिन मेरा यह विश्वास है कि वह उस के द्वारा मुजरिम घोषित किए जाएंगे और वह हथकड़ियां पहनगें।

आज की स्थिति में एक बड़ा खतरनाक साजिश बिहार में हो रहा है। जितने बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं वह बिहार के बड़े-बड़े मठाधीश सिडीकेट में इकट्ठा हो गए हैं। यह जमींदारों के नेता जनता पार्टी के नेता सिडीकेट गुट में इकट्ठा हो गए हैं। वह जनता पार्टी के नेता राजा कामाख्या नारायण सिंह आज मुजरिम साबित हो गए हैं..... (व्यवधान)

श्री क० भा० तिवारी : मुधोलकर कमिशन की रिपोर्ट जोकि सबमिट हो गयी है उस के बारे में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उस के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन वह अय्यर आयोग की रिपोर्ट तो भी नहीं सबमिट हुई है और उस के बारे में माननीय सदस्य का यह कहना कि अय्यर कमिशन यह करेगा वह उचित नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said so.

SHRI YOGENDRA SHARMA : He only says that all the landed interests in Bihar have assembled in the Syndicate. That is what he has said.

SHRI K. N. TIWARY : He has referred to Aiyar Commission also.

MR. DEPUTY SPEAKER : I would again request you not to say anything or create even a suspicion that you are referring to the work of a Commission which is still working.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैंने तो केवल यह कहा है कि तमाम लैंडिंग इंटरस्ट्स बिहार में सिंडीकेट के नीचे जमा हो गए हैं। वहां पर उन के द्वारा जनता पर यह लूट चल रही है। जो मधोलकर कमिशन द्वारा मुजरिम साबित हो गए हैं उन को हरिहरसिंह अपने मन्त्रीमंडल में मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं ताकि उन पर कोई कार्यवाही न होने पाए यह सारी साजिश वहां पर चल रही है। दुर्भाग्य से यहां इम संसद में सिंडीकेट गुट्ट के लोग, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के लोग उस साजिश में शामिल हैं।

मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को यहां पारित किया जाए परन्तु केन्द्रीय सरकार यह हिम्मत करे कि बिहार में जो जमीन की इजारेदारी है अर्थात् कुछ मुट्ठों भर लोगों के हाथ में जमीनें हैं उन को यह इजारेदारी तोड़ी जाए और जमीन का भूमिहीनों में समुचित बंटवारा करने की जरूरत है। भूमि सुधार को वहां केन्द्रीय सरकार तेजा से लागू करे।

मेरा आग्रह है कि बिहार में इन मुजरिमों की जमात को सरकार बनाने का मौका न दिया जाए। अगर उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाने दिया गया तो बिहार में जनता द्वारा विद्रोह कर दिया जाएगा। जनता इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी कि मुजरिम लोग मन्त्री बनें और उन्हें लूटें खसोटें। ऐसे मुजरिमों को जगह मन्त्रिमण्डल में नहीं अपातु जेलखाने में है। भूमि सुधार वहां पर लागू करने के बारे

में केन्द्रीय सरकार हिम्मत से काम ले और हदबन्दी के स्तर को नीचे गिराया जाए और वटाईदारों की जमीनें रेकार्ड की जाएं। इस के साथ ही जो खेत जोतने वाले हैं ऐसे लोगों को और हरिजनों को जमीन का अधिकार प्रदान किया जाए।

ज्यादा न कहते हुए अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मौजूदा विधेयक नाकार्की है और सरकार आगे चल कर पूर्ण विधेयक लाने की हिम्मत करे। मेरा सुझाव है कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि वहां पर एक लोकप्रिय जनता की सरकार स्थापित हो सके। इन के लिए मेरी राय है कि संयुक्त ममाजवादी दल आज यदि विभिन्न वामपन्थी लोगों के सहयोग से वहां पर सरकार बना सकता है तो उसे इस का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन यह जनता पार्टी की सरकार जिसके कि नेता मुजरिम पाए गए हैं उन्हें यह सिंडीकेट, स्वतन्त्र और जनसंघ से सांठगांठ करके सरकार बनाने नहीं देना चाहिए क्योंकि मुजरिमों का मन्त्रिमण्डल में रहना बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आज किसी तरह वहां पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना संभव न हो तो फिर बिहार विधान सभा को भंग किया जाए और बिहार में नए चुनाव करवाए जाए।

श्री सत्य नारायण सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है मैं उस का समर्थन करता हूँ लेकिन कुछ बातें संक्षेप में मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ।

जब कांग्रेस के अन्दर दो गुट्ट नहीं हुए थे और बिहार के अन्दर मिनिस्ट्रों सस्पेंड की गई तब से लेकर आज तक वहां पर एक नाटक चल रहा है और कोई भी लोकप्रिय सरकार वहां पर मौजूद नहीं है। वहां पर लोकप्रिय सरकार न होने के कारण यह स्थिति बन रही है कि जनता के हितों पर भारी संकट से हमले किए जा रहे हैं। बिहार में खेतिहर मजदूरों

[श्री सत्यनारायण सिंह]

और गरीब किसानों का आन्दोलन चल रहा है। उन को बड़ी निर्दयता से दवाने का कोशिश बड़े बड़े जर्नलदार वहाँ के कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा वहाँ पर कोई लोकप्रिय सरकार न होने के कारण गरीब जनता अपने चुने हुए सच्चे प्रतिनिधियों द्वारा अपनी मांगों, शिकायतों और उन पर होने वाले दमन व अत्याचार के विरुद्ध वहाँ पर असेम्बली में अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकती। वहाँ पर गवर्नर का शासन कायम है और इस स्थिति का नाजायज लाभ उठा कर बिहार के जो जमीनों के बड़े-बड़े मालिक व जमींदार लोग हैं वह खतिहर मजदूरों और गरीब किसानों को हर तरीके से तबाह कर रहे हैं व बर्बाद कर रहे हैं। गरीबों पर होने वाले अत्याचार इन हद तक बढ़ गए कि वहाँ पर एक आदमी को पकड़ा गया, उसे मारा गया और केवल मार कर ही संतोष नहीं किया गया अपितु उस गरीब को दोनों आँखें भी निकाल ली गईं। इस तरह के दर्दनाक और हैवानियत से भरे कारनामे आज वहाँ गरीबों पर हो रहे हैं लेकिन उन को कोई आवाज पार्लियामेंट और असेम्बली के अन्दर सुनाई नहीं पड़ती। उधर बंगाल में अगर कोई रेडिकल रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर ला एंड आर्डर की बात उठा कर खूब शोर किया जाता है लेकिन बिहार के अन्दर यह सब जो कुछ हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है उस के लिए कहीं कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आज बिहार की जो स्थिति है कि वहाँ पर कोई भी लोकप्रिय सरकार नहीं है तो यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए और वहाँ पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। जो पार्टियाँ यह कहती हैं कि वह बिहार में सरकार बना सकती हैं उन को सरकार को इन के लिए मौका देना चाहिए कि वह अपने दावे को सिद्ध कर सकें। जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि

यह बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे वहाँ पर सरकार बनाने के लिए मौका क्यों नहीं दिया जाता? यह बहुत आवश्यक है कि आज की बिहार की स्थिति को समाप्त किया जाए, वहाँ पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो और जनत पर होने वाले दमन व अत्याचार का अन्त किया जा सके। जनता की आवाज वहाँ की असेम्बली में उन के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा सके।

मैं उदाहरण महोदय के माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आज जब देश के कोने-कोने में यह बात मान ली गई है कि जब तक खेती में रेडिकल रिफॉर्म नहीं किए जाएंगे, जब तक देश के नामने मोजूद गहरे संकट की बुनियाद में जो खेतिहर संकट है उन हल नहीं किया जाएगा, तब तक देश का संकट नहीं किया जा सकता। सरकार जब तक वहाँ असेम्बली को काम करने का मौका नहीं देती है, जनता के प्रतिनिधि असेम्बली के अन्दर इकट्ठा नहीं होते हैं, तब तक कोई आर्डनेंस निकाल कर सरकार को रेडिकल रिफॉर्म को लागू करना चाहिए। ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? अगर ऐसा किया गया तभी हमारे देश और बिहार की जनता का संकट दूसरे करने में मदद मिल सकेगी।

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Ten Minutes Past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

MOTION RE: CONTEMPT OF HOUSE BY SOME VISITORS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMIAH):

I beg to move:

"This House resolves that the persons calling themselves (1) Shri Tarachand C. Shah, (2) Shri Krishna P. Patil and (3) Shri Gulabrao R. Deshmukh who threw some leaflets from the Visitors' Gallery on the floor of the House at 12.25 p.m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately have committed a grave offence and are guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till 6 p.m. on Saturday, the 20th December, 1969 and sent to Tihar Jail, Delhi."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"This House resolves that the persons calling themselves (1) Shri Tarachand C. Shah, (2) Shri Krishna P. Patil and (3) Shri Gulabrao R. Deshmukh who threw some leaflets from the Visitors' Gallery on the floor of the House at 12.25 p.m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately have committed a grave offence and are guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till 6 p.m. on Saturday, the 20th December, 1969 and sent to Tihar Jail, Delhi."

The motion was adopted.

14.12 hrs.

BIHAR LAND REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS VALIDATING BILL—contd.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnanagar): I would like to make one point. I want to bring something to the notice of the House. It is something which is agitating the minds of the people of West Bengal...

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are now in the minds of the discussion of a Bill....

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: I am not talking about bank robbery, but I have received telegrams and trunk calls..

MR. DEPUTY-SPEAKER: It cannot be raised like that here. Let her do it with a proper motion.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: Cultivators are being killed in West Bengal when paddy is harvested and taken home. In Burdwan and Midnapore and other places, this has happened....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Member to do it with a proper motion.

Now, the hon. Minister.

SHRI JAGANATHA RAO: I am grateful to the hon. Members who took part in the debate this morning....

ADJOURNMENT OF THE HOUSE—
 contd.

श्री कीकर सिंह (भाटण्डा) : डिप्टी स्पीकर साहब . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may raise his point after the hon. Minister has finished his speech.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): May I make one submission?....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has yielded and I have allowed Shri Kiker Singh to make a submission. Let him make his submission first.

श्री कीकर सिंह: आपने पहले भी यही कहा था कि इस काम को खत्म कर लेने दो, उस के बाद इस को लेंगे, लेकिन आप हाउस एडजार्न कर के चले गए। अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हाउस अभी-अभी एडजार्न कर दिया जाए।

SHRI SHRI CHAND GOYAL: Usually, after the lunch-recess, new subjects are raised, and in the morning you were kind enough to point out that in the midst of the debate, it would not be desirable and proper to raise new issues.

Today is a great day. Guru Teg Bahadur had laid down his life here in Delhi. It was an act of supreme sacrifice in the history of India. We adjourned yesterday when all the Members had come here and today the attendance in the House is also thin....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think Shri Kiker Singh is going to make the same submission. I have allowed him. Let him first make his submissions, and then I shall allow the hon. Member.

श्री कीकर सिंह: मेरा यह कहना है कि गुरु तेग बहादुर साहब, जिनको हम हिन्दुस्तान की चादर समझते हैं, उन का आज शहीदी दिन है। आज के दिन वे शहीद हुए थे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज हाउस उन के सत्कार में एडजर्न हो और हर साल आज का दिन छुट्टी का दिन होना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात को मान लें तो आपका बहुत शुक्रिया। यह मेरी खुशकिस्मती है कि इस मामले में सारा हाउस, मेरे तमाम साथी मेरे साथ है। इस के बारे में कोई मुखालफत नहीं है, इसलिए आप इस हाउस को एडजर्न कर दें।

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I rise to support the motion moved by Shri Kiker Singh....

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMIAH): It is not a motion, but a suggestion.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I rise to support the suggestion made by my hon. friend Shri Kiker Singh that the House be adjourned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think he has not made that submission. He has only made the submission that the House rise in honour of the memory of Guru Teg Bahadur. He did not make the submission to the House that the House should adjourn....

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I do not know whether he has been able to convey his request clearly. His request was for adjournment of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me clarify from Shri Kiker Singh what exactly his submission was. I think his suggestion was that the House should rise and stand up in honour of the memory of Guru Teg Bahadur. Was that his suggestion?

श्री कीकर सिंह: मैं चाहता हूँ कि हाउस एडजर्न कर दिया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I have understood Shri Kiker Singh correctly.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: He has made a request in his language that the House should adjourn in memory of Guru Teg Bahadur. In Indian history, such examples will be very rare where a person laid down his life in such a manner. It has no parallel in history....

MR. DEPUTY-SPEAKER: We all know the very great and glorious part played by Guru Teg Bahadur in the history of India. The country knows it. So, the hon. Member need not go into that. He has already supported the motion or suggestion of Shri Kiker Singh and I think that that should be sufficient.

SHRI RAM CHARAN (Khurja): I also support the suggestion made by Shri Kiker Singh.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: The Government and the House should not discriminate between the various communities....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member has made his submission already. Everybody knows the great part played by Guru Teg Bahadur. Let us be business-like....

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I was on a different point that we should not discriminate between community and community. It was in deference to the wishes of another community that the House adjourned, even though the festival had already been celebrated on a holiday earlier....

SHRI SONAVANE (Pandharpur): I object to the observation of my hon. friend Shri Shri Chand Goyal that any differentiation has been made....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may kindly leave it to me.

SHRI SONAVANE: That was a highly objectionable remark.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already said that the hon. Member may leave it to me.

SHRI BUTA SINGH (Rupar): I do not want to base my argument on the remarks that my predecessor has chosen to make, because Guru Teg Bahadur does not belong

to a community. He belong not to any community but to the whole of the community. Guru Teg Bahadur's sacrifice has no parallel in history. He had sacrificed his life, if I may say so, for the protection of the helpless people. His was the first sacrifice in India which was honoured not only by one particular community but by the whole of the community....

MR. DEPUTY-SPEAKER: We all know the great part played by him. So let not the hon. Member go into that just now. I think he is also supporting Shri Kiker Singh.

SHRI BUTA SINGH: I support Shri Kiker Singh's motion and I request that for the rest of the day the House may be adjourned.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think there is no more point in having a discussion about this. It is now before the House.

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon): I only want to say one word. I admire the fact that you have appreciated the great and glorious sacrifice made by Guru Teg Bahadur, and you have every mind to adjourn the House....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member should not anticipate what I am going to say....

SHRI ABDUL GHANI DAR: I think so. Yesterday, the House was adjourned for a political reason. There was no id yesterday. It was only because the resolution on Shri Jagjivan Ram was coming up and they wanted to avoid it that they had adjourned....

SHRI SONAVANE: I do not know why why he is importing politics into that. I do not know when good sense will prevail upon him.

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई कीकर सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। कल जो सभा स्थगित की गई थी, वह ईद के कारण स्थगित हो गई थी, मेरे भाई को घ्रान्ति है, यहाँ पर यह बात कही गई थी कि विस्की के

लोग ईद आज मना रहे हैं और उसी आधार पर सभा स्थगित की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज दो बजे से गुरू तेग बहादुर महाराज के सम्बन्ध में चांदनी चौक से, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, जुलूस निकलनेवाला है, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, उस में शामिल होना चाहते हैं। आज उन का शहीदी पर्व है, इसलिए उन के सम्मान में यह सभा स्थगित होनी चाहिए, इस में आपस में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। जैसा कल सब सम्मति से हुआ था, वैसा ही आज होना चाहिए।

SHRI RAGHURAMALAH: Government are no less in their devotion and respect to the late martyr. There can be no two opinions about that. It is for the Hon. Speaker and the leaders to meet and decide from time to time what should be holidays and what should not be. Government have regard for all communities and for all religions and for saints in an equal degree.

If that is the wish of hon. Members and if it is a question of taking part in the procession, may I say that we may sit till four o'clock and then adjourn? That will enable Members to attend the procession and also pay their respects to the sentiments expressed here, and those who want to take a procession can do so. This is only a humble suggestion by me. Hereafter, the Speaker and the hon. Members....

श्री राम गोपाल शालवाले: कल भी ऐसा हो सकता था लेकिन आपने सारे दिन के लिए हाउस स्थगित किया था। मेरी मांग है कि आज भी उसी तरह से सारे दिन के लिए हाउस स्थगित होना चाहिए। यह आप भेदभाव की बात कर रहे हैं कि जो जुलूस में शामिल होना चाहते हैं वे चले जाएँ। यह कहकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। कल आपने ईद के लिए सारे दिन की छुट्टी की थी, उसी तरह से आज भी होना चाहिए।
(*व्यवधान*)

SHRI RAGHURAMALAH: I am not saying no to anything at all. The Government is entirely in the hands of the House in this matter. Without showing any dis-

[Shri Raghuramaiah] regard to anybody, I would only suggest this for the consideration of the House. The hon. member said there is a procession in Chandni Chowk at 4 o'clock. The House may consider whether it would sit till 4 o'clock. To avoid any misunderstanding in future, I suggest that the Speaker may meet the leaders of various parties and groups and decide what holidays should be observed by the House. So far as today is concerned, I am in the hands of the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You can take the sense of the House.

SHRI RAGHU RAMAIAH : In any case, it is not an adjournment of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The whole country knows the great part played by Guru Teg Bahadur. This House also knows it. As Sardar Buta Singh said, he does not belong to any one particular community, but to the whole of India. Today the House is half way through its business. It is not an adjournment of the House any more, but as the Minister of Parliamentary Affairs has said, if the House is so pleased, to enable members to participate in the procession, we may agree to sit till 4 o'clock

श्री राम गोपाल शान्दाले : वह प्रोसेशन दो बजे निकलेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : For the future, it would be very good if the leaders of the various parties and groups and the hon. Speaker meet and decide as a matter of policy what is to be done. You don't expect the House or the Speaker to take any snap decision on a matter like this. So far as today is concerned, since the matter has been raised and the Minister of Parliamentary Affairs has made that suggestion, it is for the House to decide now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We may finish this Bill and then adjourn.

SHRI RANGA (Srikakulam) : That is a very good compromise.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : After this, there is a small Bill for reference to the Joint Committee. It is about the Commissions of Inquiry (Amendment) Bill. It may

be passed without discussion because after the Committee has considered it, it will come back for our consideration.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : If you want us to adopt it without discussion then we have no objection.

SHRI RAGHU RAMAIAH : May I appeal to the House to pass that motion also without discussion because it is only for reference to the Joint Committee ?

SHRI SHRI CHAND GOYAL : No, Sir. Two hours have been allotted for this Bill. We want to discuss it and make some suggestions for its improvement.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, the consensus of the House is that we must finish this Bill. Let us see what happens after that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : That is not fair. It was a compromise formula which was presented to you and all of us agreed to that. So, do not make your ruling vague. In that case, we will demand immediate adjournment of the House. You have to appreciate the feelings of the Members. Why do you insist that the other Bill should be taken up ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : Sir, as I have said, in a matter like this Government would not like to stand in the way. But this should not be treated as a precedent. So far as the future is concerned, I would suggest that all these matters should be thought out in advance by the Speaker in consultation with the leaders of groups and let us have a settled policy. Today, in view of the fact that it is the martyrdom day of a Sikh guru, we do not want to stand in the way. We leave it to the House to take a decision. If the House so desires, we can adjourn after this Bill is passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It seems that the consensus of the House is that the House will rise immediately after the passing of this Bill.

14.27 Hrs.

BIHAR REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALUATION BILLS—*contd.*

SHRI JAGANATHA RAO : Mr. Deputy-Speaker, I am thankful to the hon. Members who have supported this Bill in the morning. No point has been made out by

any hon. Member against the Bill, Hon. Members have given their whole-hearted support to the Bill. Most of them spoke about matters which are extraneous to the subject-matter of this Bill, most of them political. Almost every member stressed the need for ushering in popular government in Bihar. I am sure the House would not expect any reply from me on that point.

Some hon. Members spoke about the early implementation of the Bihar Land Reforms Act. It is true that the Bihar Land Reforms Act, like Land Reform Acts of other States, has to be implemented soon. I also feel that the ceiling on land put by the various State governments in their enactments should be revised because of the development of agriculture in the State Sector. But they are all matters not connected with the Bill.

One point made by Shri Ranga and repeated by one or two other Members is that the State Assemblies pass Bills without proper scrutiny by the respective Law Departments. In this case, may I submit that this legislation relating to mines and minerals was adopted by this House in 1957? Act 67 of 1957 was passed by this House under entry 54 of the Union List under which Parliament alone has the power to make laws for regulation and development of mines. Subject to this law, there is entry 23 in the State List which gives power to the State Government to legislate on matters which fall in the State List. So, there was no misunderstanding on that.

But the Supreme Court in a writ petition filed by a party which was aggrieved, has interpreted the position differently and stated that once the power of regulation is taken away by the Union Government under entry 54 of the Union List, all matters connected therewith should also be legislated by Parliament and not by the State Assembly. That was the interpretation given by the Supreme Court, the highest judiciary in the land and everybody is bound by that. Therefore, I am forced to come to the House to validate the enactments and rules made by the Bihar State Assembly and the Bihar

Government so that no injustice, difficulty or hardship is caused to the State Government. Otherwise, they may have to make refund of the royalties and other sums collected by them.

It is a simple Bill. Every precaution is taken and every thought is bestowed before a Bill is brought before Parliament. But when the Supreme Court gives a different interpretation of the Constitution, we are all bound by it. That is the reason why this Bill has been initiated and we have come before the House with it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to validate certain provisions contained in the Bihar Land Reforms Act, 1950, and the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1964, and action taken and things done in connection therewith be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANATH RAO : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 15, 1969/Agrahayana 24, 1891 (Saka).